R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2024-26

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 23 I अंक : 14
16 से 30 अप्रैल 2025
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

प्रधानमंत्री की कूटनीति रंग लाई

मोदी 'राज' में इंडिया पावरफुल

मुंबई हमले के आतंकी तहव्वुर राणा को एनआईए भारत लाई

ट्रंप ने निभाई दोस्ती, भारत के खिलाफ टैरिफ में दिखी सुस्ती

दृढ़ता से आगे बढ़ती मध्यप्रदेश की जल संरक्षण यात्रा

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

जल गंगा संवर्धन अभियान

30 मार्च से 30 जून, 2025

"प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जल संरक्षण अभियान से प्रेरित मध्यप्रदेश में सरकार और समाज की साझेदारी से वर्षा जल की बूंद-बूंद बचाने का "जल गंगा संवर्धन" अभियान प्रारंभ हुआ है। जन, जल, जंगल, जमीन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए संकल्पित मध्यप्रदेश का यह अभियान जन आंदोलन बन रहा है।"

- डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

- लघु एवं सीमांत किसानों के लिए बनाये जायेंगे 50 हजार खेत-तालाब
- 90 दिनों में 90 लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का होगा लोकार्पण
- ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व वाले जल स्रोतों एवं देवालयों की सफाई के साथ होगा जीर्णोद्धार
- 1000 नए तालाबों का निर्माण एवं 50 से अधिक नदियों के वॉटर शेड क्षेत्र में जल संरक्षण एवं संवर्धन के होंगे कार्य
- अनुपयोगी तालाब, चेक डैम एवं स्टॉप डैम का जीर्णोद्धार एवं हर दिन एक जल संरचना का होगा लोकार्पण
- नर्मदा परिक्रमा पथ का चिन्हांकन कर जल संरक्षण एवं पौधरोपण की योजना
- ग्रामीण क्षेत्रों में पानी चौपाल का आयोजन, प्रत्येक गांव से महिला-पुरुषों का चयन कर तैयार किए जाएंगे 1 लाख जलदूत
- सीवेज का गंदा पानी जल स्रोतों में न मिले, इसके लिए सोक पिट निर्माण को प्रोत्साहन
- 54 जल संरचनाओं का संवर्धन एवं नहरों को विलेज-मैप पर "सार्वजनिक नहर" के रूप में किया जाएगा अंकित
- बांध तथा नहरें होंगी अतिक्रमण मुक्त, करीब 40 हजार किलोमीटर लंबी नहर प्रणाली की होगी साफ-सफाई
- सदानीरा फिल्म समारोह, जल सम्मेलन, प्रदेश की जल परंपराओं पर आख्यान, चित्र प्रदर्शनी सहित विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम होंगे आयोजित

आइये, मिलकर सहेजें अपने जल स्रोतों को

जल दूत के रूप में सहभागिता के लिए **mybharat.gov.in** पर पंजीयन करायें

इस अंक में

विवाद

8 | 108 पर ठोका 25 करोड़...

मप्र में 108 एम्बुलेंस चलाने वाली छत्तीसगढ़ की जय अंबे इमरजेंसी सर्विसेस कंपनी पर परिवहन विभाग ने नकेल कसते हुए उस पर 25 करोड़ रुपए का रोड टैक्स की रिकवरी निकाली है। इसको लेकर परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा...

डायरी

10-11 | ब्यूरोक्रेसी की निष्क्रियता...

जबसे अनुराग जैन मुख्य सचिव बने हैं, वे अफसरों को समय-समय पर उनकी हैसियत और निष्क्रियता को उजागर करते रहते हैं। अभी हाल ही में मुख्य सचिव ने सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर 3 घंटे की मैराथन बैठक की।

सौगात

13 | 9 साल बाद होंगे कर्मचारियों...

मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रमोशन में बनी बाधा को हटाने का रास्ता निकाल लिया है। जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। इससे मप्र के चार लाख से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारियों को प्रमोशन मिलेगा। बता दें कि मप्र में अप्रैल...

बिजली

18 | लाइन लॉस का भार ईमानदार...

मप्र में देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे महंगी बिजली उपभोक्ताओं को मिल रही है। इसके बाद भी बिजली कंपनियां उसकी दरों को कम करने के उपायों पर काम करने की जगह लगातार बिजली की दरों में वृद्धि पर जोर देती रहती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है, लाइन...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की रणनीतिक कूटनीति के कारण आज भारत की पूरे विश्व में तूती बोल रही है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विश्व के शक्तिशाली देश अमेरिका हो या रूस या अन्य कोई देश, सबकी कोशिश यही रहती है कि भारत से उसके संबंध मधुर रहें। यही नहीं अमेरिका में तो प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप जबसे राष्ट्रपति बने हैं, तबसे इंडिया और पावरफुल हुआ है। इंडिया की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने मुंबई...

29

37

44

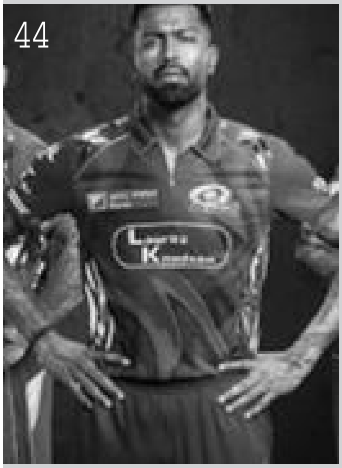

45

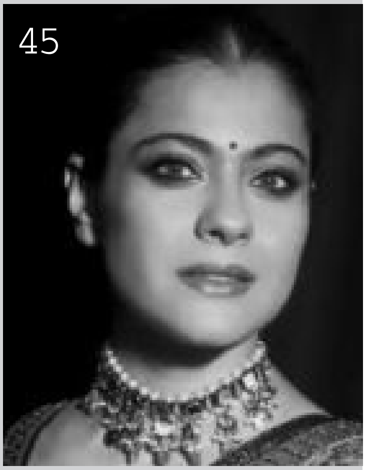

राजनीति

30-31 | क्या राहुल बदल...

भाजपा से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने खाका तैयार कर लिया है। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी सीडब्ल्यूसी की बैठक में पार्टी के भविष्य की दिशा तय कर ली गई है। कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करने और भाजपा के खिलाफ आक्रामक रुख...

महाराष्ट्र

35 | अब हिंदी-मराठी के बीच विवाद

महाराष्ट्र में भाषाई राजनीति एक बार फिर से भड़क गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के वरिष्ठ नेता सुरेश भैयाजी जोशी ने हाल ही में एक सार्वजनिक सभा में यह बयान दिया था कि मुंबई आने वाले लोगों के लिए राज्य की आधिकारिक भाषा मराठी को सीखना जरूरी नहीं है।

बिहार

38 | भाजपा से टकराने को तैयार बिहार

कांग्रेस आज के दौर में मंडल कमंडल की राजनीति की तर्ज पर भाजपा से टकराने को तैयार है। अब कांग्रेस ने बिहार के नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी की है, जिसमें राहुल गांधी के नारे, जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी को कमोबेश...

6-7 अंदर की बात
40 विदेश
41 महिला जगत
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

पाक्षिक अक्स

वर्ष-23, अंक-14, पृष्ठ-48
16 से 30 अप्रैल, 2025

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
टेलीफेक्स - 0755-4017788

email : akshmagazine@gmail.com
W ebsite : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

प्रमुख संवाददाता

भावना सक्सेना-भोपाल, जय मतानी-भोपाल,
हर्ष सक्सेना-भोपाल,
दक्ष दवे-इंदौर, संदीप वर्मा-इंदौर,
विपिन कंधारी-इंदौर, गौरव तिवारी-विदिशा,
ज्योत्सना अनूप यादव-गंजबासौदा, राजेश तिवारी-उज्जैन,
टोनी छाबड़ा-धार, आशीष नेमा-नरसिंहपुर,
अनिल सोडानी-नई दिल्ली, हसमुख जैन-मुंबई,
इंद्र कुमार बिन्नानी-पुणे।

प्रदेश संवाददाता

पारस सरावगी (इंदौर)
09329586555
नवीन रघुवंशी (इंदौर)
09827227000 (इंदौर)
धर्मेन्द्र कथूरिया (जबलपुर)
098276 18400
श्यामसिंह सिकरवार (उज्जैन)
094259 85070
सुभाष सोमानी (रतलाम)
089823 27267
मोहित बंसल (विदिशा)
075666 71111

क्षेत्रीय कार्यालय

नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी, फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
देवास : जय सिंह, देवास मो.-7000526104, 9907353976

स्वात्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

अपनी बात

उफ! ये जानलेवा गर्मी...जिम्मेदार कौन?

शायर राहत इंदौरी का एक शेर है...

शहर क्या देखें कि हर मंज़र में जाले पड़ गए
ऐसी गर्मी है कि पीले फूल काले पड़ गए।

कुछ ऐसी ही स्थिति इस साल गर्मी में होने वाली है। अभी गर्मी शुरू ही हुई है कि पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग आने वाले दिनों में भी दिल्ली-एनसीआर, उप्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मप्र सहित देश के विभिन्न हिस्सों में हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी कर चुका है। हीटवेव के कारण लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। हीटवेव के कारण लोगों के बीमार होने और हीट स्ट्रोक का खतरा बहुत बढ़ जाता है। हर साल हीट स्ट्रोक से सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस जानलेवा गर्मी के लिए कौन जिम्मेदार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक हीटवेव से स्वास्थ्य को काफी नुकसान होते हैं, जिनमें प्राय: डिहाइड्रेशन (पानी की कमी), ऐंठन, उष्माघात इत्यादि शामिल होते हैं। इसके अलावा थकान, कमजोरी, चक्कर आना, सिरदर्द, उल्टी, मांसपेशियों में ऐंठन आदि लू लगने के संकेत देते हैं। उष्माघात के लक्षणों में शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होना, दौरे पड़ना या कोमा शामिल है, जो एक घातक स्थिति मानी जाती है। प्रचंड गर्मी के कारण जहां बिजली की मांग बहुत ज्यादा बढ़ने से ग्रिडों पर भारी दबाव बढ़ रहा है, वहीं अनेक इलाकों में जलस्रोत भी सूख रहे हैं, जिससे देश के कुछ हिस्सों में सूखे जैसी स्थिति भी पैदा हो रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक आसमान से बरसती आग ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का ही असर है। जलवायु परिवर्तन से न सिर्फ तापमान बढ़ रहा है बल्कि मौसम का पैटर्न भी बदल रहा है, जो भविष्य में सामने आने वाले गंभीर खतरों का स्पष्ट संकेत है। तापमान में पहले के मुकाबले तेजी से बदलाव आ रहा है, जिसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ रहा है। तापमान में वृद्धि से आगामी वर्षों में लू, गर्मी का मौसम ज्यादा समय तक रहने और सर्दी के मौसम का समय घटने जैसी स्थितियां पैदा होंगी। इस बारे में मौसम वैज्ञानिकों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि जिस जलवायु परिवर्तन के बारे में अब तक हम केवल पढ़ते-सुनते रहे थे, वह अब हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है। भारत में वैसे तो 1980 के दशक से ही तेज गर्मी पड़ रही है लेकिन अमेरिकी संस्था बर्कले अर्थ के मुताबिक 1851-1900 की तुलना में 1980 तक केवल 0.4 डिग्री तापमान बढ़ा था लेकिन उसके बाद से यह अंतर आधे समय में ही 0.6 डिग्री बढ़ गया है अर्थात् भारत 2020 तक एक डिग्री ज्यादा गर्म हो चुका है, जिसके लिए ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार माना जा रहा है। शोधकर्ताओं के अनुसार 2026 तक रिकॉर्ड सबसे गर्म वर्ष होगा। वैसे इतिहास के सबसे गर्म वर्षों में लगभग सभी साल पिछले तथा इस दशक से ही रहे हैं। ब्रिटिश मौसम कार्यालय के एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने कहा है कि यदि जलवायु परिवर्तन नहीं हो रहा होता तो ऐसा चरम तापमान प्रत्येक 312 वर्षों में एक बार ही देखने को मिलता। अध्ययन में शोधकर्ताओं ने भारत और पाकिस्तान में हर तीन साल बाद प्रचंड लू की आशंका जताते हुए दावा किया कि जलवायु परिवर्तन गर्मी की तीव्रता को जिस तेजी से बढ़ा रहा है, उससे इन क्षेत्रों के लोगों को आने वाले वर्षों में 100 गुना ज्यादा लू के थपेड़े झेलने पड़ सकते हैं। एक तरफ मौसम विभाग ने 2025 में भी सामान्य से अधिक गर्मी रहने का अनुमान जताया है, तो दूसरी तरफ एक नए अध्ययन में सामने आया है कि भारत बढ़ती गर्मी के खतरों के लिए तैयार नहीं है। इस अध्ययन का विश्लेषण चरम लू के हालात से निपटने की सरकारी कार्यक्रमों व नजरिये पर सवाल उठाता है। आम जनता को जागृत करता है कि उनकी सरकारें वास्तव में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए क्या कर रही हैं। विश्लेषण में कहा गया है कि जिन शहरों में सर्वेक्षण किया गया है, वो शहर गर्मी की लहरों के लिए तात्कालिक उपायों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि दीर्घकालिक उपायों पर।

- राजेन्द्र आगाल

नक्सलियों पर नकेल जरूरी

मप्र में अब तक एक दर्जन से अधिक नक्सली घटनाएं सामने आई हैं। बीते 5 सालों में 1.52 करोड़ रुपए के 6 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। वहीं 3.31 करोड़ रुपए के ईनामी 20 नक्सलियों को पुलिस ने मार गिराया। सरकार को नक्सलियों के लिए और ठोस कदम उठाने चाहिए।

● **मोहसिन खान,** ब्यावरा (म.प्र.)

बढ़ रही माफिया की गुंडागर्दी

पिछले कुछ सालों में मप्र में रेत माफिया की गुंडागर्दी बढ़ गई है। 2024 और 2025 में कई ऐसी घटनाएं हुईं हैं, जिनमें माफिया ने खुलेआम कानून को तोड़ा है। रेत के अवैध खनन का मुद्दा संसद में भी उठ चुका है। शासन-प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है।

● **अभिषेक सिंह,** गैरतगंज (म.प्र.)

किसानों को मिल रहा फायदा

मप्र में बंजर, अनुपयोगी कृषि भूमि पर सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। इसके जरिए किसानों को बिजली उत्पादक बनाया जाएगा। यह सोलर प्लांट किसान और निवेशक मिलकर भी लगा सकते हैं। इससे उत्पादित होने वाली बिजली को सरकार खरीदेगी। मप्र के किसानों को इससे फायदा मिल रहा है।

● **नेहा वर्मा,** मुलताई (म.प्र.)

पानी की कमी से जूझ रहे बाघ

मप्र के छह टाइगर रिजर्व में करीब साढ़े तीन सौ सोलर पावर पंप के माध्यम से वाटर होल भरे जाते हैं। जबकि प्राकृतिक जल स्रोतों को भी संरक्षित किया जाता है। इसके बाद भी पानी की कमी कहीं न कहीं गर्मी के दिनों में उत्पन्न हो जाती है और ज्यादा उम्र के बाघ पानी की तलाश में अपना क्षेत्र छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। घने जंगल के अंदर पहुंचते ही फिर उनका सामना जवान और ताकतवर बाघों से होता है और इस तरह वर्चस्व की जंग शुरू हो जाती है। स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में वर्चस्व की जंग तेज हो सकती है। शासन-प्रशासन को चाहिए कि वे जंगलों में गश्त और सुरक्षा श्रमिकों की संख्या बढ़ाए। बाघों को पानी की कमी नहीं होने पाए इसके इंतजाम पर नजर रखी जानी चाहिए।

● **भीम राजपूत,** मंडला (म.प्र.)

भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो

2018 से 2022 के बीच मप्र में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को 10,060 करोड़ रुपए की राहत राशि वितरित की गई। इसमें से 13 जिलों में 23.81 करोड़ रुपए की राशि फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई। कैग ने सरकार से सिफारिश की है कि किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से उन सभी जिलों में आपदा राहत राशि वितरण की जांच कराई जाए, जो कैग की जांच में शामिल नहीं हैं। सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए और भ्रष्टाचारियों को कड़ी सजा देना चाहिए।

● **आनंद शिवहरे,** शाजापुर (म.प्र.)

कार्यकर्ताओं में जोश भरे कांग्रेस

आजादी के तत्काल बाद से ही जातीय और सांप्रदायिक वोटबैंक के आधार पर कांग्रेस ने देश पर लंबे समय तक शासन किया। हालांकि उसे 1952 में भी देश में सिर्फ 45 प्रतिशत वोट मिले। जब 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक पराजय हुई तो उपाध्यक्ष रहे राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की, जिसे एक स्वर से ठुकरा दिया गया। असल में, जिस संगठन में जब बॉस इज आलवेज राइट का चलन होगा तो उसकी चाल बिगड़ने से भला कौन रोक सकता है। कांग्रेस को इस माइंडसेट को बदलना होगा, जिससे कार्यकर्ताओं में जोश आए।

● **भूमि अहिरवार,** अलीराजपुर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स, एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

उप्र में बड़ा दांव खेलेगी भाजपा

उप्र भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चाओं का बाजार गरमा गया है। राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार पार्टी किसी दलित नेता को यह जिम्मेदारी सौंप सकती है जिससे वह समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) नैरेटिव को मात दे सके और बसपा के कमजोर पड़े वोटबैंक को अपनी ओर खींच सके। चर्चा जोरों पर है कि भाजपा किसी ऐसे दलित नेता को मौका दे सकती है जो आरएसएस और भाजपा के पुराने कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी के विचारधारा से मेल खाता हो और उसे मजबूत राजनीतिक आधार प्राप्त हो। ऐसे में तीन प्रमुख नाम सामने आ रहे हैं विद्या सागर सोनकर, रामशंकर कठेरिया और राम सकल का। कहा-सुना जा रहा है कि इनमें से ही किसी एक को इस महत्वपूर्ण पद का भार सौंपा जा सकता है। भाजपा ने अब तक उप्र में किसी दलित नेता को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया था। ऐसे में अगर पार्टी इस बार दलित समाज से किसी नेता को यह जिम्मेदारी देती है तो यह एक ऐतिहासिक कदम होगा। इस कदम से न केवल भाजपा को अपने दलित वोटबैंक को मजबूत करने में मदद मिलेगी, बल्कि सपा द्वारा पिछड़ा और दलित समाज के समर्थन के लिए चलाए जा रहे अभियान को भी कड़ी टक्कर मिलेगी।

पंजाब से राज्यसभा जाएंगे केजरीवाल!

पंजाब विधानसभा के लुधियाना पश्चिम सीट पर उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अभी तक ऐलान नहीं किया है। लेकिन प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी आप ने अपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा का नाम अभी से घोषित कर दिया है। आप के इस कदम से कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा के जरिए संसद में भेजना चाहती है।

वहीं संजीव अरोड़ा की उम्मीदवारी पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा ने सोशल मीडिया पर तंज भरे पोस्ट में लिखा अगर राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को लुधियाना पश्चिम उपचुनाव से आप उम्मीदवार के तौर पर नामित किया गया है तो मुझे यकीन है कि अरविंद केजरीवाल अपनी राज्यसभा सदस्यता ले लेंगे। यह स्पष्ट है कि केजरीवाल ने अरोड़ा को पंजाब में कैबिनेट में जगह दिलाने की रिश्वत दी है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि केजरीवाल पिछले दरवाजे से सत्ता में आएंगे और सत्ता में आए बिना नहीं रह पाएंगे। इसका मतलब यह भी होगा कि पंजाब के अधिकारों का हनन होगा और साथ ही पंजाब में एक ऐसा सांसद होगा जो पंजाबी नहीं जानता! मुझे आश्चर्य है कि भगवंत मान इस निर्णय का बचाव कैसे करेंगे क्योंकि वे पंजाबी भाषा के पक्ष में आवाज उठाते रहे हैं और अक्सर पंजाब के विपक्षी नेताओं को कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने के लिए फटकार लगाते रहे हैं।

महागठबंधन में ऑल इज वेल?

बिहार चुनाव में भले ही अभी कुछ महीनों का समय शेष है लेकिन नेताओं की हर गतिविधि चर्चा के केंद्र में है। रमजान के मौके पर इफ्तार पार्टियों का दौर जोरों पर था। नीतीश कुमार और लालू यादव से लेकर चिराग पासवान तक हर कोई दावत-ए-इफ्तार दे रहा था। लालू यादव की इफ्तार पार्टी में कई मुस्लिम संगठन के प्रतिनिधि पहुंचे लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता नदारद दिखे। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी भी नहीं नजर आए। इससे सवाल उठ रहा है कि महागठबंधन में सबकुछ ठीक तो है ना? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं का लालू यादव की इफ्तार पार्टी में न आना कई सवाल खड़े करता है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में नेताओं का एक साथ दिखना जरूरी होता है। मुकेश सहनी आरजेडी के प्रमुख समर्थकों में से एक माने जाते हैं। ऐसे में उनका इफ्तार पार्टी में न दिखना कई लोगों को हैरान कर रहा है। हालांकि आरजेडी नेताओं का कहना है कि सबकुछ ठीक है और कांग्रेस के नेता अपने क्षेत्र में व्यस्त थे। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा जारी है कि महागठबंधन में कुछ तो गड़बड़ है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इन पार्टियों के नेता इस मुद्दे पर क्या सफाई देते हैं।

संकट में भूपेश बघेल

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं। उनके घर पर बीते दिनों केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने छापेमारी की है। यह छापेमारी उनके भिलाई और रायपुर स्थित आवास पर की गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यह छापेमारी महादेव सट्टा ऐप के मामले में की गई है। जानकारी के मुताबिक आईपीएस अभिषेक पल्लव समेत अन्य कई पुलिस अधिकारियों के घर भी जांच एजेंसी ने दस्तक दी है। इससे पहले भी 10 मार्च को जांच एजेंसी ईडी भूपेश बघेल के घर पहुंची थी। गौरतलब है कि महादेव सट्टा ऐप में भूपेश बघेल को पैसे पहुंचाए जाने का आरोप ईडी ने लगाया था। आरोप था कि 508 करोड़ रुपए महादेव सट्टा ऐप वालों ने भूपेश बघेल को पहुंचाए थे। ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से जुड़े एक परिसर से कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और दस्तावेज भी जब्त किए। असल में महादेव बेटिंग ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए बनाया है। इस पर यूजर्स पोकर, कार्ड गेम्स, चांस गेम्स नाम से लाइव गेम खेलते थे।

झारखंड का कमान कौन?

देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा में इन दिनों प्रदेश अध्यक्षों से लेकर संगठन में फेरबदल जोरों पर है। पहले सदस्यता अभियान और बूथ कमेटियों के स्तर पर चुनाव हुए। उसके बाद प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव संपन्न हो रहे हैं। अब तक 14 राज्यों में ये प्रक्रिया पूरी हो गई है, सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होना बाकी रह गया है। राजनीतिक गलियों में सवाल उठ रहे हैं कि झारखंड भाजपा की कमान किसे मिलेगी। ऐसे में कई नामों पर कयास लगाए जा रहे हैं। जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवरदास, सांसद विद्युत वरण महतो, मनीष जायसवाल और आदित्य साहू के नाम शामिल हैं। पार्टी के इन बड़े नेताओं के नाम पर चर्चाओं का दौर चल रहा है। इन सबके बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ-साथ नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में संगठन का कामकाज जैसे-तैसे चल रहा है। रांची के भाजपा सांसद संजय सेठ से जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस विषय पर पूछा गया तो वे गोलमोल जवाब देते नजर आए।

परवान चढ़ा इश्क-मोहब्बत

भारतीय संस्कृति में एक लोकोक्ति है- हथेली पर दूब उगाना। कुछ इसी तर्ज पर प्रदेश के एक आईपीएस अधिकारी का इश्क-मोहब्बत परवान चढ़ा है। यानि साहब नक्सल प्रभावित जिले में कप्तान के रूप में पदस्थ किए गए हैं, ताकि नक्सलियों से लोहा ले सकें। लेकिन हैरानी की बात यह है कि साहब इस बीच भी अपने प्यार को परवान चढ़ाते रहे और अब स्थिति यह है कि उन्होंने जिस महिला से प्यार किया है, उसे अब अपने पास ही रख लिया है। सूत्रों का कहना है कि जिस महिला के प्यार में साहब ने अपना वैवाहिक जीवन खतरे में डाल दिया है, उक्त महिला साहब के साथ तब से है जब साहब राजधानी में पदस्थ थे। बताया जाता है कि उक्त महिला एक प्राइवेट कंसल्टेंसी के माध्यम से साहब के विभाग में पदस्थ थीं। जब साहब यहां से नक्सलियों से लोहा लेने के लिए तबादला होकर जाने लगे तो उक्त महिला को भी अपने साथ ले गए। इधर, साहब के प्यार में जिस महिला आईपीएस अधिकारी ने उनसे शादी करके अपना कैडर बदलवाया वह परेशान होकर गुहार लगाती फिर रही हैं। बताया जाता है कि पुलिस विभाग के मुखिया से मिलकर उन्होंने गुहार लगाई है कि साहब मेरे पति को बचा लो। उनकी गुहार पर बड़े साहब ने बेमन से कहा कि मैं इसमें जांच करा लेता हूं। जबकि यह मामला बहुत पुराना है और कोई व्यक्ति पत्नी के रहते दूसरी औरत के साथ कैसे रह सकता है।

आखिरकार दोनों ने मिलकर चाय पी या नहीं...

इस समय सरकार का पूरा फोकस सिंहस्थ की तैयारियों पर है। सिंहस्थ का आयोजन होने में अभी तीन साल का समय है। यानि 2028 में सिंहस्थ का आयोजन होना है, लेकिन शासन और प्रशासन की कोशिश है कि सारी तैयारियां समय पर और फुलप्रूफ हों। इसके लिए मुख्य सचिव निरंतर समीक्षा कर रहे हैं। विगत दिनों वर्क मैनेजमेंट सिस्टम की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने सिंहस्थ की तैयारियों के संदर्भ में अफसरों से जानना चाहा तो 2 हमनाम अफसर आईटी को लेकर आपस में भिड़ गए। एक अफसर ने कहा कि मैंने तो आईटी का काम पहले ही शुरू कर दिया और बहुत सारा काम करा भी लिया है। इस पर दूसरे साहब ने कहा कि हमने भी काम शुरू कर दिया है। आईटी का काम हम ही कराएंगे, क्योंकि हमारा विभाग उससे संबंधित है। सूत्र बताते हैं कि दोनों अफसर अपर मुख्य सचिव हैं। सिंहस्थ की तैयारी में दोनों विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन देखा यह गया कि आईटी का काम कराने के लिए दोनों विभागीय अफसर तत्पर दिखे। दोनों अफसरों की मैं-मैं से माहौल गर्माता देख मुख्य सचिव ने मोर्चा संभाला और उनसे कहा कि भाई, आप दोनों अपने काम के प्रति तत्पर हो यह देखकर अच्छा लग रहा है। अब बेहतर यह होगा कि आप दोनों एकसाथ बैठकर चाय पी लो और शांति से मसले का हल निकाल लो। पता नहीं दोनों अफसरों ने एकसाथ बैठकर चाय पी या नहीं।

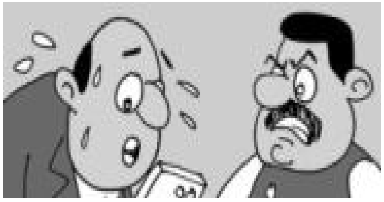

यह बेनामी संपत्ति किसकी ?

अभी कुछ महीने पहले ही प्रदेश में आयकर विभाग ने एक बड़ी छापामार कार्रवाई की थी। यह छापामार कार्रवाई एक कंस्ट्रक्शन कंपनी पर की गई थी। आरोप है कि इस कंपनी के माध्यम से बड़े-बड़े नेताओं और अफसरों ने जमीन के धंधे में अपनी काली कमाई ठिकाने लगाई है। सूत्र बताते हैं कि आयकर विभाग को छापे के बाद की गई पड़ताल में कई बेनामी संपत्तियां भी मिली हैं। बताया जाता है कि आयकर विभाग ने जब गहनता से पड़ताल की तो यह तथ्य भी सामने आया है कि बिल्डर ने अमीर लोगों के लिए जो कॉलोनी बनाई है, उसमें कई संपत्तियां संदेह के घेरे में हैं। इनमें गोल्डन पार्क सिटी में 5 और प्राइम पार्क में 4 बेनामी संपत्तियां मिली हैं। ये संपत्तियां किनकी हैं, इसको लेकर अभी पड़ताल चल ही रही है। उधर, सूत्रों का दावा है कि उक्त संपत्तियों का संबंध प्रदेश के एक पूर्व मुख्य सचिव से जुड़ता है। उक्त अफसर उसी कॉलोनी में निवासरत हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने इसी कॉलोनी में कई और संपत्तियां खरीदी हैं। इन बेनामी संपत्तियों का उनसे लेना-देना है कि नहीं यह तो भविष्य का विषय है। अभी सबकी नजर इस बात पर है कि आयकर विभाग कब इन संपत्तियों को लेकर नोटिस जारी करेगा। बताया जाता है कि जिस बिल्डर के यहां आयकर विभाग ने छापेमारी की थी, वह बिल्डर पूर्व मुख्य सचिव के कार्यकाल में तेजी से आगे बढ़ा है और उसके कारोबार में रसूखदारों ने अपनी काली कमाई लगाई है।

यारो... मैं नशे में हूं

मीर तकी मीर का यह शेर तो आपने सुना ही होगा- यारो मुझे मुआफ रखो मैं नशे में हूँ... अब दो तो जाम खाली ही दो, मैं नशे में हूं... कुछ इसी तरह की स्थिति एक आईएएस अधिकारी की है। 2015 बैच के उक्त आईएएस अधिकारी प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिले में कलेक्टर हैं। इस जिले में आदिवासियों की संख्या अधिक है। ऐसे में लगता है कि साहब पर उनका सुरूर कुछ इस कदर छा गया है कि वे भी दिन-रात शराब के नशे में रहने लगे हैं। सूत्रों का कहना है कि साहब अंगूर की बेटी के प्यार के गिरफ्त में इस कदर आ गए हैं कि उसके बिना वे एक पल नहीं रहते हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि साहब अक्सर बैठकों में भी शराब पीकर पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि कई बार बैठक में नशे में होने के कारण साहब उल-जुलूल भी बोल जाते हैं। लेकिन किसी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि साहब को यह बीमारी कैसे लगी और उन्हें इससे किस तरह निजात दिलाई जाए। साहब को भले ही अपने नशे की बदौलत लोकलाज का अहसास नहीं हो रहा है, लेकिन उनके मातहत साहब के नशे से परेशान हैं।

साहब को कुछ नहीं पता

प्रदेश में सभी प्रमुख विभाग सिंहस्थ की तैयारी में जुटे हुए हैं। जिस विभाग के पास जो काम है, वे उसे पूरी तत्परता से पूरा करने में जुटे हुए हैं। यही नहीं विभाग के बड़े अफसर रोजाना हो रहे और आगे किए जा रहे कार्यों का पूरा हिसाब-किताब तैयार रख रहे हैं। लेकिन विडंबना यह है कि जहां सिंहस्थ हो रहा है, वहां के बड़े साहब को ही पता नहीं है कि सिंहस्थ के लिए वहां क्या-क्या हो रहा है। सूत्रों का कहना है कि गत दिनों जब मुख्य सचिव ने सिंहस्थ के कार्यों की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई तो सिंहस्थ की समिति के अध्यक्ष भी उस बैठक में शामिल हुए। बैठक में मुख्य सचिव ने एक-एक विभाग से उनकी कार्ययोजना और प्रोग्रेस रिपोर्ट की जानकारी ली। विभागों में प्रेजेंटेशन देखकर मुख्य सचिव कुछ हद तक संतुष्ट नजर आए। इसी दौरान उन्होंने अध्यक्ष से पूछा कि क्या सिंहस्थ की तैयारियां ठीक ढंग से चल रही हैं, तो उस पर वे बगले झांकने लगे। जब सीएस ने दोबारा उनसे यही सवाल पूछा तो वे कुछ नहीं बता सके। इस पर सीएस ने उन्हें जमकर फटकारा। यहां बता दें कि साहब गैर प्रशासनिक सेवा से आईएएस बने हैं।

108 पर ठोका 25 करोड़ का रोड टैक्स

मप्र में 108 एम्बुलेंस चलाने वाली छत्तीसगढ़ की जय अंबे इमरजेंसी सर्विसेस कंपनी पर परिवहन विभाग ने नकेल कसते हुए उस पर 25 करोड़ रुपए का रोड टैक्स की रिकवरी निकाली है। इसको लेकर परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा ने कंपनी को नोटिस जारी किया है। साथ में सभी आरटीओ को निर्देश दिए हैं कि टैक्स जमा नहीं करने पर गाड़ियों के संचालन पर रोक लगा दी जाए।

जय अंबे सर्विसेस का विवादों से पुराना नाता है। कंपनी की गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ में हुआ है और वे मप्र की सड़कों पर चल रही हैं। ऐसे में जय अंबे इमरजेंसी सर्विसेस कंपनी पर रोड टैक्स के तौर पर 25 करोड़ रुपए बकाया है। टैक्स जमा करने के लिए जय अंबे सर्विसेस को परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा ने नोटिस जारी किया है। टैक्स नहीं जमा करने की दशा पर गाड़ियों को खड़ा करना पड़ सकता है। जय अंबे की मप्र में 2000 एम्बुलेंस चल रही हैं। परिवहन आयुक्त ने कंपनी को टैक्स जमा करने की सख्त चेतावनी दी है। कंपनी को समय पर टैक्स जमा करने की हिदायत भी दी गई है। परिवहन आयुक्त ने कहा कि अतिआवश्यक सेवा होने के कारण अभी गाड़ियों का संचालन नहीं रोका जा रहा है। हालांकि राशि जमा नहीं करने की दशा में विभाग को सर्विस रोकनी पड़ सकती है।

मप्र में जय अंबे इमरजेंसी सर्विसेस 108 एम्बुलेंस का संचालन कर रही है। प्रदेश में कंपनी की करीब दो हजार एम्बुलेंस दौड़ रही हैं। कंपनी पर आरोप है कि उसने रोड टैक्स जमा किए बिना गाड़ियों का संचालन शुरू कर दिया है। इसको लेकर परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा ने कंपनी को नोटिस जारी किया है। साथ में सभी आरटीओ को निर्देश दिए हैं कि टैक्स जमा नहीं करने पर गाड़ियों के संचालन पर रोक लगा दी जाए। नोटिस मिलने के बाद कंपनी ने आयुक्त के समक्ष प्रजेंटेशन भी दिया। इसमें बताया गया कि उनकी गाड़ियां छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड हैं, ऐसे में मप्र में टैक्स जमा करने का प्रावधान नहीं है। टेंडर जारी होने के बाद कंपनी को यह जानकारी दी गई थी कि टैक्स जमा करना होगा। बावजूद इसके कंपनी ने राशि जमा नहीं कराई है। वह भी तब जब वाहनों का उपयोग व्यावसायिक तौर पर किया जा रहा है।

नियमानुसार ऐसे में कंपनी को टैक्स की राशि जमा करनी होती है। परिवहन आयुक्त ने एनएचएम की डायरेक्टर सलोनी सडाना को पत्र लिखा है। पत्र में जय अंबे सर्विसेस से बकाया राशि जमा कराने की बात कही गई है। आयुक्त ने कहा कि कंपनी द्वारा टैक्स का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे में कंपनी को भुगतान की जा रही राशि से काट कर टैक्स की राशि जमा कराई जाए। इसे लेकर **सलोनी सडाना** ने कंपनी को तत्काल पैसा जमा कराने के लिए पत्र लिखा है।

जय अंबे सर्विसेस का विवादों से पुराना नाता है। **हाल में आईटी विभाग ने कंपनी पर छापामार कार्रवाई** की थी। इसके **पहले कांग्रेस भी कंपनी पर आरोप लगा चुकी है।** कांग्रेस ने पूछा था कि क्या अनुबंध के अनुसार जेएईएस द्वारा एनएचएम को लिखित में सूचित कर अनुमति मांगी गई थी कि उनके द्वारा लगाए गए समस्त एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन रोड टैक्स आदि का छत्तीसगढ़ राज्य में भुगतान कर गाड़ियां मप्र में संचालित की जा सकेगी। कांग्रेस ने परिवहन विभाग के नियमों का हवाला देते हुए कहा था कि एक राज्य का वाहन ट्रांसफर कराए बिना दूसरे राज्य में छह महीने से ज्यादा की अवधि तक नहीं चलाया जा सकता है, जबकि मप्र में जेएईएस द्वारा अनुबंध करने से लेकर वर्तमान समय तक 2000 एम्बुलेंस का संचालन छत्तीसगढ़ में कराए गए रजिस्ट्रेशन और वहां के रजिस्ट्रेशन नंबर पर किया जा रहा है। जय अंबे सर्विसेस का विवादों से पुराना नाता है। हाल में आईटी विभाग ने कंपनी पर छापामार कार्रवाई की थी। इसके पहले कांग्रेस भी कंपनी पर आरोप लगा चुकी है।

• कुमार राजेंद्र

900 करोड़ के घोटाले का आरोप

गौरतलब है कि कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने बड़े घोटाले का पर्दाफाश करने का दावा करते हुए सरकार पर आरोप लगाया है कि वह पिछले ढाई साल में दो हजार एम्बुलेंस के लिए 900 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है, जो एक बड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। इस मामले को गंभीर बताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ढाई साल में एम्बुलेंस के लिए किराए के तौर पर छत्तीसगढ़ की एक निजी कंपनी को जो पैसा दिया है, वह एम्बुलेंस की कीमत से तीन गुना ज्यादा है। जयवर्धन सिंह ने कहा कि हर सरकार का दायित्व होता है कि राज्य में चिकित्सा सुविधाओं पर नियंत्रण हो और उसकी गुणवत्ता अच्छी हो। मैंने विधानसभा में एक सवाल पूछा था कि एम्बुलेंस के लिए प्रदेश सरकार ने अब तक कितना भुगतान किया है। मुझे जानकारी मिली कि पिछले ढाई साल में छत्तीसगढ़ की एक निजी कंपनी जय अंबे इमरजेंसी सर्विसेज को 900 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इस कंपनी के पास करीब 2 हजार एम्बुलेंस हैं और इसका औसत किराया प्रति एम्बुलेंस 45 लाख रुपए दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर आप इसकी तुलना करें तो एक पूरी तरह से सुसज्जित एम्बुलेंस, जिसमें हर आधुनिक उपकरण जैसे वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, उसकी अधिकतम कीमत 20 लाख रुपए होती है। लेकिन, यहां सरकार 45 लाख एम्बुलेंस किराए के रूप में भुगतान कर चुकी है। यह सीधा-सीधा भ्रष्टाचार और सरकारी धन का दुरुपयोग है। यह सब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत मिलने वाले केंद्र सरकार के पैसों का गलत इस्तेमाल है।

लोकायुक्त की कमजोरी का सौरभ को फायदा

आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के यहां मिली अकूत काली कमाई के बाद ऐसा लगा था कि लोकायुक्त सहित अन्य एजेंसियां उसे सलाखों के पीछे भिजवाकर भ्रष्टाचार के बड़े नेटवर्क का खुलासा करेंगी। लेकिन विडंबना यह है कि गिरफ्तारी के दो महीने बाद विशेष न्यायाधीश आरपी मिश्रा की कोर्ट से जमानत मिल गई है। यह जमानत लोकायुक्त के प्रकरण में मिली है। हालांकि इसके बाद भी सौरभ को जेल में ही रहना पड़ेगा क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रकरण में उसे राहत नहीं मिली है। वहीं ईडी ने समय पर उसके खिलाफ चालान पेश कर दिया है।

गौरतलब है कि आय से अधिक संपत्ति से लेकर कई अलग-अलग आर्थिक अपराधों के मामले में सौरभ पर लोकायुक्त पुलिस, ईडी और आयकर विभाग ने कार्रवाई की थी। इसके बाद 28 जनवरी को उसे गिरफ्तार किया गया था। लेकिन गिरफ्तारी के 60 दिन से ज्यादा समय बीतने के बाद भी लोकायुक्त कोर्ट में चालान पेश नहीं कर सकी है। इस कमजोरी का फायदा सौरभ को मिला है, इसी कारण उसे फायदा मिला है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि लोकायुक्त समय पर चालान नहीं पेश कर पाया। जबकि सौरभ ने अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन में परिवार के सदस्यों के कॉलम में भाई की जानकारी छिपाई थी। सौरभ ने नहीं बताया था कि उसका बड़ा भाई सचिन शर्मा छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी में है। सौरभ की मां उमा शर्मा ने आवेदन में सहमति कॉलम पर हस्ताक्षर किए थे। इस मामले पर लोकायुक्त सौरभ शर्मा के खिलाफ कार्रवाई कर चालान पेश कर सकती थी।

गौरतलब है कि लोकायुक्त पुलिस ने 19 दिसंबर 2024 को उसके घर और जयपुरिया स्कूल की निर्माणाधीन बिल्डिंग में छापा मारा था। इस दौरान सौरभ के दोनों ठिकानों से करीब 50 लाख रुपए से अधिक के जेवर, लाखों रुपए की नकदी और करीब ढाई क्विंटल चांदी की सिल्लियां मिली थी। वहीं, देर रात को मेंडोरा के जंगल में एक इनोवा कार में करीब 54 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए नकदी बरामद हुए थे। यह कार सौरभ के करीबी चेतन सिंह गौर के नाम रजिस्टर्ड थी। बाद में चेतन की भी गिरफ्तारी हुई, वहीं उनका एक अन्य पार्टनर शरद जायसवाल भी गिरफ्तार हुआ। लेकिन तीनों ने इनावों में मिले माल को अपना नहीं माना।

1 अप्रैल 2025 को सौरभ शर्मा के वकील राकेश पाराशर और दीपेश जोशी ने विशेष अदालत में तर्क दिया कि लोकायुक्त ने गिरफ्तारी के 60 दिन बाद चार्जशीट दाखिल नहीं की। यह जमानत का आधार बन सकता है। विशेष न्यायाधीश राम प्रताप मिश्र ने यह दलील मान ली। इधर, सबकुछ साफ होने के बाद भी लोकायुक्त एसपी दुर्गेश राठौर कहते हैं कि साक्ष्यों के पूरे परीक्षण के बाद अभियोजन स्वीकृति मिलने पर चार्जशीट पेश की जाएगी। लोकायुक्त के डीजी योगेश देशमुख का तर्क है कि यह अनुपातहीन संपत्ति का केस है। ऐसे मामलों में काफी तथ्य और सबूतों की जरूरत होती है। इन्हें जुटाने में वक्त लगता है। अब यहां सवाल यह है कि और कितना परीक्षण करना चाहती है लोकायुक्त। हालांकि, तीनों आरोपियों की रिहाई अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कोर्ट में मामला चल रहा है। यहां 11 अप्रैल को जमानत आवेदन पर सुनवाई होगी, तब तक तीनों आरोपी न्यायिक हिरासत में सेंट्रल जेल में रहेंगे।

परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा केस में ईडी मनी ट्रेल और प्रॉपर्टी के दस्तावेज, तो इनकम टैक्स विभाग सौरभ के दोस्त चेतन सिंह गौर की गाड़ी से मिले 54 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए की जांच कर रही है। लोकायुक्त आय से ज्यादा संपत्ति की जांच, तो डीआरआई इस बात की जांच कर रही है कि जो सोना मिला है, वो लीगल तरीके से लिया गया है या नहीं? काली कमाई को कॉलोनी बनाने में खपाए जाने का कनेक्शन भी जांच एजेंसियों को मिला है। उधर, सौरभ शर्मा की जमानत से उन नेताओं को भी बड़ी राहत मिली है, जिनके संरक्षण में उसने काली कमाई का साम्राज्य खड़ा किया था।

● सुनील सिंह

लोकायुक्त की गलतियां

जानकारों का कहना है कि लोकायुक्त ने कई गलतियां कीं, जिसका फायदा सौरभ शर्मा को हुआ। 19 दिसंबर 2024 को छापेमारी के दौरान सौरभ के एक दूसरे घर और शरद जायसवाल के ठिकानों पर कार्रवाई नहीं की गई। आयकर विभाग ने 52 किलो सोना और 11 करोड़ नकद एक इनोवा कार से बरामद किया। यह कार छापे के वक्त सौरभ के घर के पास थी। सौरभ और उसकी पत्नी दिव्या 40 दिन तक फरार रहे। 27 जनवरी को सौरभ ने सरेंडर का आवेदन दिया, लेकिन कोर्ट से चला गया। 28 जनवरी को सौरभ ने कोर्ट में सरेंडर किया। इससे एक दिन पहले कोर्ट में सरेंडर का आवेदन दिया। लोकायुक्त को इसकी भनक नहीं लगी। ईडी के वकीलों ने कोर्ट में कहा कि उनके पास चार्जशीट दाखिल करने की समयसीमा 11 अप्रैल तक है। तय समय में इसे पेश कर दिया जाएगा। लोकायुक्त पुलिस अभी तक सोने और नकदी के असली मालिक का पता नहीं लगा सकी। जांच में भी खामियां सामने आती रहीं। लोकायुक्त ने 7.98 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी, जिसमें 234 किलो चांदी भी शामिल थी।

ब्यूरोक्रेसी की निष्क्रियता पर सीएस नाराज

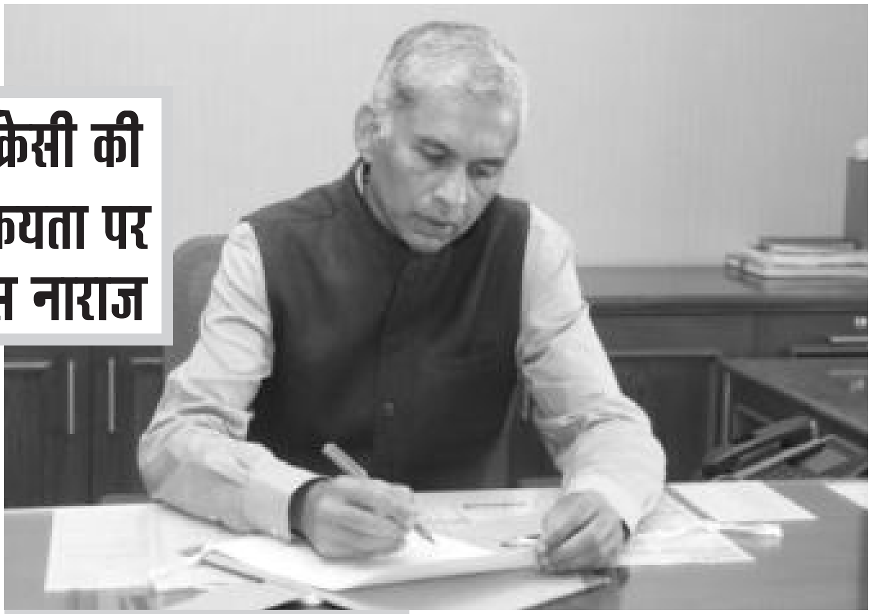

जबसे अनुराग जैन मुख्य सचिव बने हैं, वे अफसरों को समय-समय पर उनकी हैसियत और निष्क्रियता को उजागर करते रहते हैं। अभी हाल ही में मुख्य सचिव ने सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर 3 घंटे की मैराथन बैठक की। इस बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय शुक्ला ने करीब 30-35 करोड़ रुपए के ट्यूबवेल का प्रस्ताव रखा। इस पर मुख्य सचिव ने उनसे जवाब-तलब कर लिया कि पहले पंचकोशी यात्रा मार्ग पर लगे हैंडपंप की स्थिति का विवरण दें। कितने हैंडपंप चालू हालत में हैं और कितने बंद। इस पर शुक्ला ने कहा कि हम तो नोडल एजेंसी हैं, नीचे से जो मांग आती है, उसे देखकर हम मीटिंग की तैयारी कर लेते हैं। इस पर मुख्य सचिव ने आश्चर्य व्यक्त किया कि आप अपर मुख्य सचिव हैं, आपको सब चीजों को देखना है। सबको देखकर प्रस्ताव बनाना चाहिए। इसी तरह बैठक में अन्य विभागों के अफसरों की भी मुख्य सचिव ने जमकर क्लास ली। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव दिनेश मौर्य ने अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। मुख्य सचिव ने जब उनसे अस्पतालों की स्थिति के बारे में जानना चाहा तो वे कुछ नहीं बता पाए। इस पर मुख्य सचिव ने कहा कि आप लोग ऐसे कैसे काम कर रहे हो। क्या मुझे ही हर विभाग का प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा।

दुबे की पदस्थापना पर सवाल

आबकारी विभाग के सबसे भ्रष्ट अधिकारियों में से एक सहायक आबकारी आयुक्त संजीव दुबे को मुख्यालय ग्वालियर से जबलपुर पोस्टिंग को लेकर सीएस ने सवाल उठाए। दरअसल, गत महीने सरकार ने आबकारी अधिकारियों के थोकबंद तबादले किए। उनमें से दुबे भी एक थे। दुबे साल 2015 में इंदौर में सामने आए 42 करोड़ के शराब घोटाले में सस्पेंड हो चुके हैं। ऐसे में इस तरह के अधिकारी की मैदानी पदस्थापना को लेकर जब मुख्य सचिव ने सवाल खड़े किए तो उन्हें बताया गया कि खुद मुख्यमंत्री ने इनकी पदस्थापना के ऑर्डर किए हैं।

उज्जैन में निर्देश का पालन नहीं

नए वित्तीय वर्ष शुरू होने के कुछ दिन पहले आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल ने शराब के तीन दिन से अधिक भंडारण न करने का निर्देश दिया था। यह निर्देश मप्र में बार और रेस्तरां को संबोधित था। विभिन्न प्रकार की शराब के लिए अलग-अलग भंडारण समय सीमा निर्धारित की गई थी। उदाहरण के लिए, बीयर, वाइन, शैंपेन और एल्कोपॉप को तीन दिनों से अधिक समय तक संग्रहित नहीं किया जाएगा। यह निर्देश 31 मार्च तक के लिए था। इस नियम का जहां इंदौर सहित प्रदेशभर में पालन किया गया, वहीं उज्जैन में इसका असर नहीं दिखा। इसकी खबर मिलते ही मुख्य सचिव अनुराग जैन आगबबूला हो गए और उन्होंने निर्देश दे डाला कि अभिजीत अग्रवाल को सस्पेंड कर दो। उन्होंने सवाल खड़े किए कि इस तरह के आदेश किससे पूछकर निकाले गए। इस पर अधिकारियों ने सीएस को बताया कि यह निर्देश शराब के भंडारण और बिक्री से संबंधित आबकारी विभाग के नियमों का एक हिस्सा है। यह निर्देश हर साल जारी होते हैं। तब जाकर मुख्य सचिव शांत हुए। दरअसल, मुख्य सचिव की मंशा यह थी कि ऐसे मामलों को लेकर सरकार की बदनामी न हो।

राजनीतिक पार्टियों की मांग पर एससी शिक्षक को थमाया नोटिस

कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर

प्रदेश में अफसरशाही किस तरह काम कर रही है, इसका एक उदाहरण अभी हाल ही में जबलपुर संभाग में सामने आया है। जबलपुर संभाग कमिश्नर अभय वर्मा ने हिंदूवादी संगठनों और कुछ राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं के कहने पर अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले एक प्रभारी प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि शिकायत के बाद चित्तौड़ सिंह कुशराम तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षक शासकीय स्कूल घाटकोहका विकासखंड कुरई जिला-सिवनी के विरूद्ध तहसीलदार तहसील कुरई की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति गठित कर जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि कुशराम ने कांग्रेस पार्टी से विधायक पद के टिकट की दावेदारी की थी, जिसकी अनुमति शासन से नहीं ली गई। इसको लेकर जबलपुर कमिश्नर ने अवचार एवं कदाचार के संदर्भ में कुशराम को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया।

मास्टर प्लान है या ततैया का छत्ता

मप्र की राजधानी भोपाल का मास्टर प्लान लगता है ततैया का छत्ता बन गया है, जिसमें अधिकारी और नेता हाथ डालने से बच रहे हैं। शायद यही वजह है कि 19 साल बाद भी यह तय नहीं हो पाया है कि भोपाल का मास्टर प्लान कब लागू होगा। गौरतलब है कि इस बार भी सरकार ने दावा किया कि भोपाल और इंदौर के मास्टर प्लान की ड्रॉफ्ट रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। यह रिपोर्ट मार्च महीने के अंत तक जारी करने का ऐलान नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा किया गया था। इस नए मास्टर प्लान में शहरों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें सड़क निर्माण और हरियाली के अलावा अब विभिन्न वाणिज्यिक और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए जोनिंग का भी प्रावधान किया गया है। मास्टर प्लान के तहत कॉलोनियों में चौड़ी सड़कों के साथ हाइराइज

बिल्डिंग्स, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और आईटी हब जैसी सुविधाएं भी होंगी। इन बदलावों से शहरवासियों को बेहतर आवागमन और रोजगार की सुविधाएं मिल सकेंगी। लेकिन अभी मास्टर प्लान कहां है, यह किसी को नहीं पता। भोपाल का मास्टर प्लान 19 साल से अटका हुआ है। इस बीच चार बार भोपाल के मास्टर प्लान का प्रारूप जारी हो चुका है, लेकिन लागू होने के पहले ही कई बाधाएं सामने आ जाती हैं। ऐसे में बिना मास्टर प्लान के शहर का विकास हो रहा है। इससे आने वाले समय में जनता को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल, भोपाल का मास्टर प्लान 1995 में लागू हुआ था, जिसकी समय अवधि दिसंबर 2005 में समाप्त हो गई है। प्लान के लागू होने के समय शहर की आबादी 15 लाख के आसपास थी। ऐसे में उस समय के प्लान के अनुसार ही शहर में विकास हो रहा है।

अंशुल गुप्ता विदिशा, रोशन सिंह उज्जैन कलेक्टर बने

राज्य सरकार ने प्रदेश के 9 आईएएस अधिकारियों के नवीन पदस्थापना आदेश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी आदेश में 9 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। इसमें चार जिले उज्जैन, अशोकनगर, हरदा और विदिशा के कलेक्टर बदले गए हैं। आदेश के अनुसार संयुक्त मुख्य

निवार्चन पदाधिकारी एवं पदेन अपर सचिव (विधि एवं विधायी कार्य विभाग) को अपर सचिव, श्रम विभाग के साथ-साथ मप्र भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मंडल तथा असंगठित शहरी-ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह को हटाकर अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल भेजा गया है। वहीं, अशोकनगर कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी को हटाकर सामान्य प्रशासन विभाग में अपर सचिव पदस्थ किया गया है। वहीं, कलेक्टर हरदा आदित्य सिंह को स्थानांतरित कर कलेक्टर अशोकनगर बनाया गया है। विदिशा कलेक्टर रोशन सिंह को उज्जैन कलेक्टर और भोपाल अपर कलेक्टर सिद्धार्थ जैन को कलेक्टर हरदा पदस्थ किया गया है। इसके अलावा जनसंपर्क विभाग के संचालक और मप्र माध्यम के कार्यपालक निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे अंशुल गुप्ता को कलेक्टर विदिशा बनाया गया है। वहीं, इंदौर की अपर कलेक्टर ज्योति शर्मा को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत देवास नियुक्त किया गया है। देवास जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हिमांशु प्रजापति को मप्र औद्योगिक विकास निगम, इंदौर का कार्यकारी संचालक बनाया गया है। आदेश में जनजातीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव गुलशन बामरा को अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल के मुख्य कार्यालय अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ सिंहस्थ मेला उज्जैन के मेला अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके अलावा राज्य योजना आयोग के सदस्य सचिव एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी आयुक्त ऋषि गर्ग को अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के संचालक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

मप्र को मिले 5 नए आईपीएस

केंद्र सरकार ने 2024 बैच के 200 आईपीएस अफसरों को कैडर अलॉट कर दिया है, जिसमें मप्र को 13 आईपीएस मिले हैं। मप्र की माही शर्मा, माधव अग्रवाल, अर्णव भंडारी, रीतू यादव और काजल सिंह को होम कैडर मिला है। इसके अलावा उप्र के राजीव अग्रवाल, हरियाणा के दीपांशु, समीक्षा सरवरी, राजस्थान के माधव गुप्ता, लेखराम मीना, दिल्ली के मनोज गुप्ता, अंशुल गुप्ता और बिहार के अमित कुमार को मप्र कैडर मिला है।

2 आईएएस गए, 2 आए

मप्र की आईएएस छाया सिंह का कैडर बदलेगा और वे अब राजस्थान जाएंगी। छाया सिंह 2024 बैच की आईएएस हैं और मप्र के आईएएस छोटे सिंह की बेटी है। छाया सिंह का ट्रांसफर उनकी शादी के आधार पर राजस्थान किया गया है। उनका विवाह राजस्थान कैडर के 2022 बैच के आईएएस मोहित कासनिया से हुआ है। कासनिया वर्तमान में भीनमाल के एसडीओ हैं। छाया मूलत: भोपाल की रहने वाली हैं। मप्र से छाया सिंह के पहले अंजलि रमेश का कैडर बदलकर उन्हें महाराष्ट्र भेजा गया है। अंजलि 2020 बैच की आईएएस हैं और मूल रूप से तमिलनाडु की रहने वाली है। महाराष्ट्र ट्रांसफर से पहले उनकी पोस्टिंग बतौर जिला पंचायत सीईओ शहडोल थी। दो आईएएस मप्र से बाहर गए तो बदले में दो आईएएस मप्र को मिले हैं। इनमें पहला नाम सौम्या आनंद है। सौम्या 2021 बैच की आईएएस हैं और वे मूल रूप से हरियाणा की हैं। इसके पहले वे तमिलनाडु कैडर में थीं, लेकिन अब मप्र कैडर में स्थानांतरित हो गई हैं। मप्र कैडर मिलने के बाद उनकी पोस्टिंग असिस्टेंट कलेक्टर शहडोल की गई है। सौम्या ने मप्र कैडर के आईएएस संघ प्रिय से शादी की है। संघ प्रिय 2018 बैच के आईएएस हैं और अभी नगर निगम ग्वालियर में आयुक्त हैं। कैडर बदलकर मप्र आने वाली दूसरी आईएएस नवकिरण कौर है। 2024 बैच की कौर का कैडर त्रिपुरा है और मूल रूप से वे पंजाब की हैं। अभी उनके ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है।

अखेतो सेमा बने स्पेशल डीजी जेल

उधर, राज्य शासन ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जी अखेतो सेमा को पदोन्नत कर स्पेशल डीजी बनाया है। इसके अलावा छिंदवाड़ा के एडिशनल एसपी को हटाने के साथ तीन आईपीएस अफसरों के तबादले किए हैं। छिंदवाड़ा में अभी किसी की पोस्टिंग नहीं की गई है। गृह विभाग से जारी आदेश के तहत 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी जी अखेतो सेमा को एडीजी जेल से पदोन्नत कर स्पेशल डीजी जेल पदस्थ किया है। 9 माह बाद अखेतो सेमा रिटायर होने वाले हैं। प्रदेश में स्पेशल डीजी के 12 पद हैं जिसमें एक पद स्पेशल डीजी रेल मनीष शंकर शर्मा के आकस्मिक निधन के बाद पिछले माह रिक्त हुआ था। इसके बाद पीएचक्यू ने एडीजी जेल जी अखेतो सेमा को रिक्त पद पर प्रमोट करने का प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद इसके आदेश जारी कर दिए गए। वहीं गृह विभाग ने एक आदेश जारी कर आईपीएस प्रकाश चंद्र परिहार को एआईजी ग्रामीण इंदौर जोन से पुलिस उपायुक्त मुख्यालय नगरीय पुलिस इंदौर पदस्थ किया है। साथ ही, अवधेश प्रताप सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा को सेनानी 36वीं वाहिनी भारतीय रिजर्व बल बटालियन विशेष सशस्त्र बल बालाघाट और राजेंद्र कुमार वर्मा एआईजी प्रशिक्षण विशेष शाखा पीएचक्यू को पुलिस अधीक्षक पीटीसी इंदौर पदस्थ किया गया है।

अतिरिक्त प्रभार से मिलेगी मुक्ति

आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन के बीच चर्चा में अफसरों के ट्रांसफर को लेकर सहमति बन गई है। जल्द ही अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए जा सकते हैं। वर्तमान में मप्र कैडर के एसीएस और पीएस रैंक के 15 अधिकारी केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में पदस्थ हैं। अफसरों की कमी के चलते मप्र में एसीएस और पीएस रैंक के अधिकतर अफसरों के पास विभागों का अतिरिक्त प्रभार है।

● राजेंद्र आगाल

जबलपुर में होगा कांग्रेस का प्रादेशिक अधिवेशन

अहमदाबाद में हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद अब मप्र कांग्रेस मई माह में प्रादेशिक अधिवेशन आयोजित करने जा रही है। यह अधिवेशन 12 से 18 मई के बीच जबलपुर में आयोजित किया जाएगा। आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस अधिवेशन में मप्र कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता, संगठन पदाधिकारी और वरिष्ठ कार्यकर्ता शामिल होंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस अधिवेशन में आगामी चुनावी रणनीति, संगठनात्मक मजबूती और जन आंदोलनों की रूपरेखा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी।

प्रदेश स्तरीय अधिवेशन के पहले मप्र कांग्रेस के संगठन में ताबड़तोड़ नियुक्तियां की जाएंगी। प्रदेश भर में करीब 502 पीसीसी डेलीगेट्स नियुक्त किए गए थे। इनमें से विधानसभा, लोकसभा चुनाव के दौरान कई डेलीगेट्स पार्टी छोड़कर चले गए थे। कुछ नेताओं का निधन हो चुका है। ऐसे में इन डेलीगेट्स की जगह नई नियुक्तियां की जाएंगी। जबलपुर में होने वाले अधिवेशन में मप्र कांग्रेस संगठन के कामकाज की पूरी दिशा तय होगी। जिला अध्यक्षों से लेकर ब्लॉक, मंडलम, सेक्टर और बूथ तक के कामों की टाइमलाइन तय होगी। इस अधिवेशन के पहले जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्त की जाएगी। ताकि नई टीम को आने वाले समय के कामकाज के तौर तरीके बताए, सिखाए जा सकें।

कांग्रेस के संगठन प्रभारी संजय कामले ने बताया कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की ये सोच है कि अहमदाबाद के राष्ट्रीय अधिवेशन की तर्ज पर हम मप्र में एक अधिवेशन करें। इस पर भी गंभीरता से मंथन चल रहा है कि ये अधिवेशन एक दिवसीय हो या दो-तीन दिन का किया जाए। बहुत जल्द इसकी तारीख तय हो जाएगी। एक बहुत अच्छा अधिवेशन मप्र में आयोजित होगा। आने वाले समय में जिसके बहुत अच्छे परिणाम संगठनात्मक तौर पर देखने को मिलेंगे। अहमदाबाद के राष्ट्रीय अधिवेशन में ये तय हो गया है कि जिला अध्यक्षों की भूमिका संगठन में सबसे अहम होगी। संगठन में होने वाली नियुक्तियों से लेकर टिकट वितरण में जिला अध्यक्षों का रोल सबसे अहम होगा। इस ऐलान के बाद मप्र में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के लिए नेताओं ने जोड़-तोड़ करना शुरू कर दिया है।

कांग्रेस ने आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। पार्टी अब सीधे बूथ स्तर पर फोकस करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, पिछले दो दशकों में कांग्रेस की चुनावी हार का एक बड़ा कारण यह रहा है कि प्रदेश संगठन का संपर्क सिर्फ जिला और ब्लॉक स्तर तक सीमित रहा, जबकि बूथ इकाइयों को मजबूत करने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। अब यह स्थिति बदली जाएगी। विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी और स्थानीय संगठन पहले से बूथ समितियों का गठन तो करते रहे हैं, लेकिन अब प्रदेश स्तर से भी बूथ समितियों की निगरानी और फॉलोअप किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और संगठन के पदाधिकारी जिला, ब्लॉक, मंडलम और सेक्टर स्तर की टीमों से लगातार संपर्क में रहेंगे और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर बूथ पर सक्रिय और प्रभावशाली समिति काम कर रही हो।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के लिए अंदरूनी तौर पर बड़े स्तर के बदलाव के संकेत दे दिए हैं। जिसमें संगठन में उन्हीं नेताओं को जगह मिलेगी, जो सक्रिय रहेंगे। यानी घर बैठे नेताओं को संगठन के दायित्वों से मुक्त किया जा सकता है। ऐसे में अब विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद से निष्क्रिय चल रहे नेताओं को कांग्रेस संगठन में बने रहने के लिए सक्रिय होना पड़ेगा। कांग्रेस के तय मुद्दे जातिगत जनगणना, बेरोजगारी, अजा-अजजा अत्याचार, महंगाई, भ्रष्टाचार आदि पर नेताओं को विरोधी दलों और सरकारों के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करना होगा।

एआईसीसी के अधिवेशन के बाद मप्र कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जल्द ही प्रदेश स्तरीय अधिवेशन की रूपरेखा तैयार करेंगे। इससे पहले वे प्रदेश भर का दौरा करेंगे, जिसमें पार्टी के अन्य नेता भी भागीदार होंगे। पटवारी ने कहा कि मप्र कांग्रेस का अधिवेशन अगले महीने राजधानी भोपाल में हो सकता है। इससे पहले वे संगठनात्मक स्तर पर लंबित फैसलों पर निर्णय ले सकते हैं। बताया गया कि प्रदेश स्तरीय अधिवेशन से पहले जिलाध्यक्ष एवं ब्लॉक अध्यक्ष तय हो जाएंगे। अब पार्टी का फोकस हर ग्राम पंचायत में पंचायत समिति और शहरी क्षेत्र में मोहल्ला समिति बनाने पर है। इस दिशा में अब पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार की मनमानी नहीं होने देंगे। मप्र में हर वर्ग के हितों के लिए कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी।

● **अरविंद नारद**

घर बैठे नेता होंगे एक्टिव

लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव हारने के बाद मप्र कांग्रेस के ज्यादातर बड़े नेताओं ने खुद को सीमित कर लिया था। प्रदेश कांग्रेस की बैठकों एवं पार्टी के कार्यक्रम, आंदोलनों से भी दूरी बना ली थी। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। सभी नेताओं को पार्टी के कार्यक्रमों में भागीदारी करनी होगी। अभी तक कांग्रेस के दूसरे नेता सिर्फ बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते थे, खासकर कई मामलों में संगठन की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठा चुके हैं। निकट भविष्य में कांग्रेस की कार्यप्रणाली में बदलाव की संभावना है। ज्यादातर बड़े कार्यक्रम दिल्ली से तय होंगे। जिसमें सभी नेताओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी। प्रदेशाध्यक्ष को ज्यादा अधिकार मिलेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में नेताओं ने संकेत दे दिए हैं कि भविष्य में पार्टी किन एजेंडों के तहत आगे बढ़ेगी। प्रमुख एजेंडों में जातिगत जनगणना, पिछड़ा, किसान, अजा, अजजा, महिला अत्याचार, जबरन भूमि अधिग्रहण, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार शामिल हैं। देश के ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस सत्ता से बाहर हैं। ऐसे में समाज के बड़े वर्ग को साधने के लिए एजेंडे केंद्र से तय होंगे। इन्हीं एजेंडों के आधार पर पार्टी अलग-अलग वर्ग से जुड़ेगी और जनआंदोलन खड़ा करेगी।

9 साल बाद होंगे कर्मचारियों के प्रमोशन

मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रमोशन में बनी बाधा को हटाने का रास्ता निकाल लिया है। जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। इससे मप्र के चार लाख से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारियों को प्रमोशन मिलेगा। बता दें कि मप्र में अप्रैल 2016 यानी पिछले 9 साल से अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रमोशन अटके हुए हैं। इस दौरान 1 लाख से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। अब सरकार ने इसका फॉर्मूला तय कर लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने भी सभी विभागों को कहा है कि कैबिनेट से प्रमोशन के नियमों को मंजूरी मिलने के बाद विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक कर आदेश जारी करें।

मप्र के चार लाख अधिकारी-कर्मचारियों को जल्द ही प्रमोशन मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पदोन्नति में बनी बाधा को हटाने का रास्ता निकाल लिया है। जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। 8 साल से ज्यादा समय से कर्मचारियों को प्रमोशन का इंतजार था। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि 8 साल से अधिक समय से कर्मचारियों, अधिकारियों की पदोन्नति का मसला उलझा हुआ है। अब सरकार ने उनके प्रमोशन करने का फैसला लिया है। अधिकारी-कर्मचारी लंबे अरसे से प्रमोशन से वंचित रहे हैं। हजारों अधिकारी-कर्मचारी प्रमोशन के बिना रिटायर भी हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकार ने अलग-अलग स्तर पर चर्चा के बाद समस्या का समाधान निकाला है। उन्होंने कहा कि हमने मंत्रियों, उपमुख्यमंत्री और सभी वर्गों के साथ मिलकर प्रमोशन का रास्ता तलाशा है। धीरे-धीरे प्रमोशन के नजदीक आ गए हैं। जल्दी ही प्रमोशन के लिए कैबिनेट से मंजूरी देकर प्रमोशन करने का काम करेंगे।

मप्र हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को मप्र लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 की पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान खत्म कर दिया था। शिवराज सरकार ने 12 मई 2016 को हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, तभी से मप्र में पदोन्नति पर रोक लगी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की प्रमोशन के संबंध में की गई घोषणा के बाद मंत्रालय कर्मचारी संघ और शीघ्र लेखक संघ के पदाधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने शाम को उनसे मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि 9 वर्ष बाद यह एक बड़ा निर्णय लिया जा रहा है जो कर्मचारी वर्ग के हित में रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास में शासकीय सेवकों का महत्वपूर्ण योगदान है। शासन द्वारा समय-समय पर शासकीय सेवकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। पदोन्नति पर रोक लगे 8 साल 11 माह हो गए हैं। इस अवधि में 1 लाख 50 हजार से अधिक कर्मचारी रिटायर हुए हैं, इनमें से करीब 1 लाख कर्मचारियों को इन्हीं 8 साल 11 माह में पदोन्नति मिलनी थी। बता दें कि हर माह प्रदेश में लगभग 3000 कर्मचारी रिटायर होते हैं। 2018 का चुनाव हारने के बाद 2020 में फिर से सत्ता में आई शिवराज सरकार ने पदोन्नति का हल निकालने की रणनीति बनाई थी। इसके लिए उप मंत्री परिषद समिति बनाई गई थी। जिसने सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से केस लड़ रहे अधिवक्ताओं के परामर्श से पदोन्नति के नए नियम बनाए थे, जो अनारक्षित वर्ग के कर्मचारियों ने नहीं माने। उनका कहना था कि कमेटी ने पुराने नियमों को नए कलेवर में परोस दिया। प्रदेश में पदोन्नति पर रोक के बावजूद विभिन्न विभागों के 500 से अधिक कर्मचारियों को प्रमोशन मिला है। दरअसल, इस रोक के खिलाफ सबसे पहले स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी धीरेंद्र चतुर्वेदी हाईकोर्ट गए थे। कोर्ट ने प्रकरण सुनने के बाद पदोन्नति के आदेश सरकार को दिए थे और चतुर्वेदी को पदोन्नति दी गई। इसके बाद अलग-अलग विभागों के कर्मचारी कोर्ट जाते रहे और कोर्ट के आदेश पर पदोन्नति दी जाती रही है।

साल 2002 में तत्कालीन सरकार ने प्रमोशन के नियम बनाते हुए प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान कर दिया था। ऐसे में आरक्षित वर्ग के कर्मचारी प्रमोशन पाते गए, लेकिन अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी पिछड़ गए। जब इस मामले में विवाद बढ़ा तो कर्मचारी कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कोर्ट से प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने का आग्रह किया। कोर्ट को तर्क दिया कि प्रमोशन का फायदा सिर्फ एक बार मिलना चाहिए। इन तर्कों के आधार पर मप्र हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को मप्र लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 खारिज कर दिया। सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। शीर्ष कोर्ट ने यथास्थिति रखने का आदेश दिया। तभी से प्रमोशन पर रोक लगी है। मप्र में प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कुल संख्या 6 लाख 6 हजार 876 हैं। इनमें से क्लास वन अधिकारियों की संख्या 8 हजार 286, क्लास टू अधिकारियों की संख्या 40 हजार 20 और क्लास थ्री कर्मचारियों की संख्या 5 लाख 48 हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या 58 हजार 522 हैं। इन चारों कैटेगरी में 31 मार्च 2024 की स्थिति में 60 से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों की संख्या 27 हजार 921 हैं, यानी 2026 में ये सभी रिटायरमेंट की उम्र 62 तक पहुंच जाएंगे। ये आंकड़ा कुल कर्मचारियों का 5 फीसदी है।

● नवीन रघुवंशी

क्या होगा प्रमोशन का फॉर्मूला

मंत्रालयीन सूत्रों के अनुसार कर्मचारियों का वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन किया जाएगा। प्रमोशन पाने वाले कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से आर्थिक लाभ दिए जाने की उम्मीद है। वहीं सूत्रों का कहना है कि वरिष्ठ पद का आर्थिक लाभ देने के लिए कार्यवाहक पदों पर दी गई अस्थायी पदोन्नति देने के लिए फिर से डीपीसी होगी। सूत्रों के मुताबिक, सरकार 2002 से अब तक एससी-एसटी वर्ग के 60 हजार से ज्यादा कर्मचारियों का प्रमोशन कर चुकी है। हाईकोर्ट ने 31 मार्च 2024 को अपने 35 पन्नों के फैसले में कहा था कि 2002 के नियम के आधार पर एससी-एसटी वर्ग के जिन कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ दिया गया, उन सभी का 2002 की स्थिति में डिमोशन किया जाए। मगर, सरकार ने तय किया है कि इन कर्मचारियों का डिमोशन नहीं किया जाएगा।

म प्र में एक मई से सितंबर के बीच पांच चरणों में सहकारी समितियों के चुनाव कराए जाएंगे। राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी एमबी ओझा ने 4500 सहकारी समितियों के चुनावों का शेड्यूल जारी किया है। भले ही सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी ने सहकारी समितियों के चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया हो, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के सहकारी नेताओं को इस बात का भरोसा नहीं हैं कि सरकार वास्तव में चुनाव कराएगी। अपेक्स बैंक के पूर्व अध्यक्ष और बदनावर से कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत कहते हैं- भाजपा सरकार की मंशा चुनाव कराने की है ही नहीं। करीब 17-18 सालों से को-ऑपरेटिव के चुनाव नहीं हुए। बीज निगम जब से बना तब से अब तक चुनाव नहीं कराया। मंडी समितियों के चुनाव नहीं करा रहे। अभी हाल ही में सरकार ने सहकारिता के कानून में संशोधन कर दिया है कि प्रशासक अनंत काल तक रह सकता है। हमने विधानसभा में इस मामले को उठाया और हाईकोर्ट को भी जब ये समझ आ गया तो सरकार को दबाव में चुनाव कार्यक्रम जारी करना पड़ा। हमें अब भी भरोसा नहीं कि सरकार वास्तव में चुनाव कराएगी।

जबलपुर जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष और सहकार भारती के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी नारायण सिंह कहते हैं कि ये चुनाव कार्यक्रम का पत्र हाईकोर्ट में सरकार को बचाने के लिए जारी किया है। सहकारिता के चुनाव होंगे इस पर संदेह है। उन्होंने कहा कि ऐसे पत्र पहले भी तीन-चार बार निकाले जा चुके हैं। अभी हाल ही में हाईकोर्ट ने **सरकार पर सहकारिता** के चुनाव न कराने को लेकर 20 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई है। कोर्ट ने पूछा है कि आखिर चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? सहकारी नेताओं की आशंकाओं को लेकर राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी एमबी ओझा का कहना है कि हमने जिलों से सदस्यता सूची मांगी है। सूची मिल जाएगी तो चुनाव हो जाएंगे। मप्र में 4500 सहकारी समितियां हैं। 38 जिला सहकारी बैंक और प्रदेश स्तर पर एक अपेक्स बैंक है। इन 4500 सहकारी समितियों में करीब 53 हजार सदस्य बनेंगे। सबसे अहम 38 जिला सहकारी बैंकों में अध्यक्ष और संचालक मंडल के चुनाव होंगे। यानी 55 हजार से ज्यादा लोगों को इन समितियों में एडजस्ट करने का मौका मिलेगा।

सहकारी समितियों के चुनावों के लिए हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने अब चुनाव कार्यक्रम जारी किया है। महाधिवक्ता कार्यालय ने इन चुनावों को अति आवश्यक बताते हुए पांच चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया है। समितियों के बाद जिला सहकारी बैंक और अपेक्स बैंक के संचालक मंडल के चुनाव भी कराए जाएंगे। हाल ही में विधानसभा के बजट सत्र में मप्र सरकार ने सहकारी अधिनियम में संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद यह पहला चुनाव होगा।

सहकारी समितियों के चुनाव का बजा बिगुल

निगम-मंडलों में नियुक्ति का फॉर्मूला तय!

मप्र भाजपा संगठन चुनाव के तहत मंडल और जिलाध्यक्षों के चुनाव संपन्न होने के बाद अब सबकी नजर प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव पर है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि निगम-मंडल में राजनीतिक नियुक्ति के लिए जो फॉर्मला तय किया गया है उसके अनुसार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही नियुक्तियां की जाएंगी। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इस महीने के अंत में निगम-मंडला में राजनीतिक नियुक्तियां शुरू हो गई हैं। प्रदेश सरकार निगम, मंडल, प्राधिकरणों में अध्यक्ष, उपाध्यक्षों के खाली पड़े पदों पर वरिष्ठ नेताओं को एडजस्ट करेगी। सरकार में एडजस्ट होने वाले नेताओं में पूर्व मंत्री रामनिवास रावत, पूर्व सांसद केपी सिंह यादव और पूर्व मंत्री इमरती देवी के नाम प्रमुखता से शामिल हैं। इमरती पिछली सरकार में भी निगम में अध्यक्ष रह चुकी हैं, इस बार फिर से उनका नाम है। गौरतलब है कि मप्र में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति का फैसला पिछले दो महीने आगे खिसकता जा रहा है। अब जल्द ही अध्यक्ष तय होने की संभावना है। प्रदेश में मोहन सरकार 16 महीने का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। अभी तक निगम, मंडलों में नियुक्तियां नहीं हुई हैं। जिसकी वजह संगठन चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं होना है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति का फैसला तीन महीने से केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष विचाराधीन है।

प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के चुनाव आखिरी बार 2013 में हुए थे। इन समितियों का कार्यकाल 2018 में खत्म हो चुका है। कार्यकाल खत्म होने के छह महीने पहले ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। चुनाव न होने की स्थिति में अधिकतम छह महीने तक कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। लेकिन, करीब तीन सालों से चुनाव टलते जा रहे हैं। सहकारी समितियों में प्रशासकों के भरोसे काम चल रहा है। को-ऑपरेटिव चुनाव न होने से असंतोष बढ़ा और जबलपुर हाईकोर्ट के साथ ग्वालियर खंडपीठ में कई याचिकाएं दायर हुईं। मार्च में महाधिवक्ता कार्यालय ने सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव और सहकारिता विभाग को सुझाव दिया कि चुनाव जल्द कराना जरूरी है। इसके बाद राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी ने कार्यक्रम घोषित किया। चुनाव कार्यक्रम के तहत पहले चरण में उन समितियों को शामिल किया जाएगा, जो **पुनर्गठित** हो चुकी हैं। भारत सरकार के सहकारिता क्षेत्र के विस्तार के निर्देशों के कारण पहले पुनर्गठन पर जोर दिया गया, लेकिन अब हाईकोर्ट के दबाव में प्रक्रिया तेज की गई है।

निर्वाचन प्राधिकारी ने स्पष्ट किया कि सभी चरणों में व्यवस्थित ढंग से मतदान होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रीकरण व निर्वाचन अधिकारी को सदस्यता सूची सौंपी जाएगी, जिसके बाद दावा-आपत्ति का निराकरण कर अंतिम सूची जारी होगी। महिलाओं के लिए संचालक मंडल में पद आरक्षित होंगे। आमसभा की सूचना के साथ नामांकन और चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए सदस्यता सूची प्रकाशन के बाद विशेष साधारण सम्मेलन बुलाकर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जिला प्रतिनिधियों का चयन होगा।

● **धर्मेंद्र कथूरिया**

नौकरशाही के भ्रष्टाचार जांच एजेंसियां हैरान

शासन-प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार कई स्तरों पर प्रयास कर रही हैं। इन्हीं में से एक है हर साल नौकरशाहों को अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा देना। लेकिन हर साल कई अधिकारी ऐसे होते हैं जो अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मप्र के एक आईएएस सहित देश के 91 आईएएस अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। इसे कार्मिक, लोक शिकायत, कानून एवं न्याय संबंधी संसदीय समिति ने गंभीरता से लिया है और कहा है कि ऐसे अफसरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। लेकिन जानकारों का कहना है कि उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसमें संदेह है कि ऐसे किसी प्रविधान से आईएएस अफसर भय खाएंगे। इसकी वजह यह है कि नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार से जांच एजेंसियां पहले से हैरान परेशान हैं।

यदि ऐसा कोई प्रविधान बन भी जाता है तो ये अफसर उसमें आसानी से छेद तलाश लेंगे। बहुत संभव है कि शीर्ष नौकरशाह प्रविधान ही ऐसे तैयार कराएं, जिससे अपनी संपत्ति का विवरण न देने वाले आईएएस अफसरों के खिलाफ ठोस कार्रवाई संभव न हो सके। आखिर यह एक तथ्य है कि नियम-कानून बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी का लाभ उठाकर वह ऐसी व्यवस्था नहीं बनने दे रहे हैं, जिससे उन्हें जवाबदेह बनाया जा सके अथवा उन्हें उनके भ्रष्टाचार से रोका जा सके या फिर उन्हें इसके लिए दंडित किया जा सके। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार का एक कारण नौकरशाहों का रवैया है। यदि वे चाह लें तो प्रशासनिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार पर प्रभावी ढंग से अंकुश लग सकता है।

ध्यान रहे कि यदि नेता भ्रष्टाचार करने में समर्थ रहते हैं तो नौकरशाहों की मदद से ही। नौकरशाह न केवल नेताओं के भ्रष्टाचार में मददगार बनते हैं, बल्कि ऐसे जतन भी करते हैं, जिससे खुद उनके भ्रष्ट तौर-तरीकों का पर्दाफाश न हो सके। यही कारण है कि रह-रहकर ऐसे भ्रष्ट नौकरशाहों का मामला सामने आता रहता है, जिनके पास अकूत चल-अचल संपत्ति होने का पता चलता है। यदि यह सोचा जा रहा है कि नौकरशाहों की ओर से अपनी संपत्ति का विवरण सार्वजनिक करने से उनके भ्रष्टाचार पर अंकुश लग जाएगा तो यह एक दिवास्वप्न ही है। अच्छा हो कि इससे आगे कुछ सोचा जाए। सबसे पहला काम तो प्रशासनिक सुधार का किया जाना चाहिए। यह निराशाजनक है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के तमाम दावों के बाद भी मोदी सरकार प्रशासनिक सुधारों को इस तरह आगे नहीं बढ़ा सकी है, जिससे नौकरशाही के भ्रष्टाचार पर रोक लग सके। समस्या केवल यह नहीं है कि आईएएस अफसरों के भ्रष्टाचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। समस्या यह भी है कि अन्य सरकारी अधिकारियों और यहां तक कि कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के किस्से खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि केंद्र सरकार की शीर्ष नौकरशाही के भ्रष्टाचार पर एक बड़ी हद तक लगाम लगी है, क्योंकि निचले स्तर पर पहले की ही तरह भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस भ्रष्टाचार के चलते न केवल विकास एवं जनकल्याण की योजनाएं प्रभावित होती हैं, बल्कि आम लोगों को सरकारी विभागों से अपने छोटे-मोटे काम कराने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

उधर, मप्र की बात की जाए तो मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सुशासन की दिशा में जो कदम उठाया है उसको देखते हुए जांच एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। जहां एक तरफ लोकायुक्त भ्रष्टों को ट्रेप करने में लगा हुआ है, वहीं आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) भी सख्ती पर उतर आया है। भ्रष्टाचार एवं आर्थिक अनियमितता संबंधी प्रकरणों की जांच के लिए गठित एजेंसी ईओडब्ल्यू में इन दिनों फटाफट अपराधिक प्रकरण (एफआईआर) दर्ज हो रहे हैं। जिससे भ्रष्टाचारियों में हड़कंप मचा है। पिछले तीन महीने के भीतर ही ईओडब्ल्यू में 78 आपराधिक प्रकरण दर्ज किए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर **नकेल कसने** के लिए मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अफसरों के साथ ही विभागों को भी निर्देश दे रखा है। इसी कड़ी में ईओडब्ल्यू ने शिकायतों की जांच के बाद आपराधिक प्रकरण दर्ज करना शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि एफआईआर का यह आंकड़ा पिछले साल से डेढ़ गुना ज्यादा है। जांच एजेंसी के इतिहास में किसी भी साल में इतने मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। ईओडब्ल्यू के महानिदेशक उपेंद्र जैन का कहना है कि ईओडब्ल्यू स्वतंत्र एजेंसी है। शिकायतों की जांच के बाद कार्रवाई होती है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है।

● **जितेंद्र तिवारी**

जबलपुर जोन में सबसे अधिक प्रकरण दर्ज

ईओडब्ल्यू के रिकॉर्ड के अनुसार चालू साल में 9 जनवरी से लेकर 1 अप्रैल तक 78 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इनमें से ज्यादा 34 मामले जबलपुर जोन के दर्ज किए गए हैं। भोपाल, इंदौर और उज्जैन में महज 4-4 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा रीवा में 20 मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले साल 2024 में 49 प्रकरण और 2023 में 63 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। खास बात यह है कि ईओडब्ल्यू में किसी भी शिकायत पर एफआईआर दर्ज भोपाल स्थित मुख्यालय में होती है। पिछले तीन महीने के भीतर जांच एजेंसी में ताबड़तोड़ प्रकरण दर्ज होने से भ्रष्टाचारियों में हड़कंप मचा है। हाल ही में आजीविका मिशन, अनाज के उपार्जन कार्य से जुड़ी सहकारी संस्थाओं के खिलाफ एफआईआर होने से गड़बड़ी करने वालों में डर का माहौल है। अभी तक एजेंसी में मामले सालों लंबित होने की वजह से आरोपी बेपरवाह होते थे। एजेंसी के रिकॉर्ड के अनुसार ईओडब्ल्यू महानिदेशक उपेंद्र जैन के आने के बाद प्राथमिकी की संख्या बढ़ी है। बता दें कि राज्य शासन ने पिछले साल दिसंबर में जैन को ईओडब्ल्यू महानिदेशक की कमान सौंपी थी। ईओडब्ल्यू में भ्रष्टाचार एवं आर्थिक अनियमिताओं से जुड़ी शिकायतों पर सीधे एफआईआर दर्ज न होकर, तथ्यों जांच के बाद प्रकरण दर्ज किया जाता है। इसके लिए ईओडब्ल्यू के 7 संभागीय मुख्यालय भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर और सागर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय हैं।

जल संरक्षण के लिए मप्र सरकार जल गंगा संवर्धन अभियान चला रही है। यह अभियान जल संरक्षण का ऐसा अभियान बन गया है, जिससे प्रदेश के जलस्रोतों की स्थिति बदल रही है। सरकार के साथ ही सामाजिक, धार्मिक संस्थाएं, स्वयंसेवी संगठन, शिक्षण संस्थाएं अभियान में भागीदारी निभा रही हैं।

जल गंगा संवर्धन अभियान बना जन आंदोलन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महाकाल की नगरी उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट से जिस जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ किया, वह अभियान आज पूरे प्रदेश में सक्रिय हो गया है। इसमें जल संरक्षण, रेनोवेशन, जलसंरचनाओं का पुनर्जीवन और जनजागरण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मप्र में जल संरक्षण को लेकर राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया महत्वाकांक्षी जल गंगा संवर्धन अभियान जन आंदोलन का रूप ले चुका है। यह अभियान जल संरक्षण की दिशा में एक कदम है। इसमें हर नागरिक को जोड़ने का उद्देश्य है, जिससे हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित बना सकें और भावी पीढ़ी को जल संकट से मुक्ति दिला सकें। यह अभियान जल संरचनाओं के सतत् संरक्षण और भविष्य की जल आवश्यकतों की पूर्ति के लिए एक सशक्त कदम है।

राज्य में अभियान अंतर्गत स्थानीय जनप्रतिनिधियों, आमजनों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जल बचाव के लिए विभिन्न गतिविधियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर प्रदेश में 30 मार्च से जल गंगा संवर्धन अभियान की राज्य स्तरीय शुरूआत की गई है। जन सहयोग के साथ-साथ प्रशासनिक अमला भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में जल संरक्षण और जल संवर्धन के कार्यों में अपार जन सहयोग मिल रहा है। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देश पर जिले के इटौरा ग्राम की भेड़ौरा नदी के पुनर्जीवन के उद्देश्य से जल संवाद आयोजित किया गया। संवाद में जल संरक्षण के महत्व के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी गई। ग्रामीणों ने भेड़ौरा नदी को आदर्श नदी के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया। अब नदी पर प्रतिदिन श्रमदान हो रहा है। नदी की सफाई और गहरीकरण के कार्य को पूरी लगन के साथ किया जा रहा है। मंदसौर जिले में तालाबों, नदी और पुरानी बावड़ी को चिन्हित किया गया है। जन अभियान परिषद के कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों को पानी चौपाल में जल के महत्व और दिन पर दिन बढ़ते जल संकट के बारे में जानकारी दी। ग्रामीणों को सघन पौध-रोपण के लिए अभी से तैयारी करने की समझाइश दी गई। ग्राम रोज्या में तालाब की सफाई और गहरीकरण के लिए ग्रामीणों ने श्रमदान किया। छिंदवाड़ा जिले में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के मार्ग दर्शन में जल गंगा संवर्धन अभियान में नवदुर्गा महिला मंडल द्वारा जल कलश यात्रा निकाली गई। जल यात्रा में महिलाओं ने पानी के महत्व से जुड़े नारे लगाए और जल संरक्षण की शपथ ली। जिले के परासिया विकासखंड के पर्यटन स्थल देवरानी दाई की घटामाली नदी में श्रमदान कर कचरा एवं पॉलीथिन की सफाई की गई। महिलाओं ने सार्वजनिक मंदिर प्रांगण को भी साफ किया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बादल भोई की जन्मस्थली डुगरिया तितरा में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। जिले में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए दीवार लेखन का कार्य भी पूरे उत्साह के साथ किया जा रहा है।

धार जिले के विकासखंड मनावर के ग्राम देवरा में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक श्रमदान किया गया। स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर 60 बोरियों का बोरी बांध बनाया। ग्राम देवरा के स्कूल फलिये के पास बहते पानी को रोकने के लिए 25 से अधिक ग्रामीणों ने श्रमदान किया। श्रमदान में नवांकुर संस्था के पदाधिकारी भी शामिल हुए। ग्रामीणों को बताया गया कि गांव में मौजूद कुएं, बावड़ी, स्टॉप डैम और तालाब आदि की नियमित सफाई की और जल स्त्रोतों उसके महत्व के बारे में समझाइश दी गई। बुरहानपुर जिले में जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं बारिश के पानी को सहेजने के लिए चल रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत छोटे-छोटे प्रयासों से कार्यों को गति दी जा रही है। जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के संचालन के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। शहर की अमरावती नदी पर जन भागीदारी से सफाई का

समाज के हर वर्ग का सहयोग

जल गंगा संवर्धन अभियान के जरिए कुओं, नदियों, तालाबों, बावड़ियों के साथ स्टॉप डैम के आसपास साफ-सफाई और गहरीकरण के कार्य को प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। जन-भागीदारी के कार्यों में प्रशासनिक अमला भी कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रहा है। छिंदवाड़ा में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के निर्देशन में जन-अभियान परिषद ने छोटा तालाब के कुंड की साफ-सफाई का कार्य शुरू किया। कार्य में नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर विनोद तिवारी, विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों और वॉलेंटियर्स ने श्रमदान किया। कुंड में पॉलिथीन और बेकार सामग्री को हटाया गया। सफाई कार्य के दौरान नागरिकों को शहर के खूबसूरत छोटे तालाब को साफ रखने का संकल्प दिलाया गया। जन-अभियान परिषद के जिला समन्वयक अखिलेश जैन ने बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान 30 जून तक निरंतर जारी रहेगा। परिषद के सहयोग से जिलेभर में नुक्कड़ नाटक एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए जन-सामान्य में जल-स्रोतों को साफ रखने के प्रति जन-जागरूकता लाई जाएगी।

कार्य शुरू हुआ। नदी के किनारे जमी हरी काई और झाड़ियों को हटाया गया। कचरे को ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से उचित स्थान पर पहुंचाया गया। शहरी क्षेत्र में मोहल्लों में पानी चौपाल लगाई गई। देवास जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान में जागरूकता के कार्यक्रम गांव-गांव में किए जा रहे हैं। मप्र जन अभियान परिषद की चयनित नवांकुर संस्था ने खजुरिया बीना में जल चौपाल ग्रामीणों की उपस्थिति में लगाई। ग्रामीणों को जल संरचनाओं की सफाई और गहरीकरण के संबंध में जानकारी दी गई। समिति के सदस्यों ने खेतों में पहुंचकर स्वयं के खर्चे पर बनाए गए तालाबों का अवलोकन किया। ग्रामीणों को व्यापक पौध-रोपण की अभी से तैयारी करने की समझाइश दी गई। ग्रामीणों ने गांव में पानी की बर्बादी पर पूरी तरह से रोक लगाने की शपथ ली।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अक्सर कहते हैं कि प्राचीन काल में भारत में पारस पत्थर हुआ करता था, जिसके स्पर्श से लोहा सोना हो जाता था। इस पारस पत्थर का काम पानी करता है जब वह सूखे खेतों पर पहुंचता है। जल के स्पर्श से खेतों में सुनहरी फसलें लहलहाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश की धरती को शस्य श्यामला बनाने के संकल्प से ही जुड़ा हुआ है मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का संकल्प, हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाना जिससे हर खेत में सुनहरी फसलें लहलहाएं और किसान समृद्धशाली बने। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए वे निरंतर जुटे हुए हैं और इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश ने गत 1 वर्ष में सिंचाई के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेई ने दो दशक पहले देश की नदियों को जोड़कर हर खेत तक पानी पहुंचाने का सपना देखा था, जो राज्यों के बीच जल विवाद के चलते दो दशकों से अधिक समय से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल जैसी महत्वाकांक्षी अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजनाएं मप्र, उप्र और राजस्थान के बीच सहमति न बन पाने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही थीं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्र सरकार और राज्यों से निरंतर चर्चा कर इन परियोजनाओं के गतिरोध को समाप्त किया और प्रदेश ने दो बड़ी परियोजनाओं के रूप में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई की 100वीं जयंती पर मप्र आकर देश की पहली नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना केन-बेतवा का शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि अब महाराष्ट्र सरकार के साथ वार्ता के बाद विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड वॉटर रिचार्ज अंतर्राज्यीय संयुक्त परियोजना ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना का अवरोध दूर हो गया है। मप्र शीघ्र ही महाराष्ट्र सरकार के साथ इस संबंध में करार करने की ओर बढ़ रहा है। जल्द ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भोपाल आमंत्रित कर करार की कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कहना है कि ताप्ती मेगा रिचार्ज योजना के जरिए हम महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर ताप्ती नदी की तीन धाराएं बनाकर राष्ट्रहित में नदी जल की बूंद-बूंद का उपयोग सुनिश्चित कर कृषि भूमि का कोना-कोना सिंचित करेंगे। केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय परियोजना है, जिसमें केन नदी पर दौधन बांध एवं लिंक नहर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। 44 हजार 605 करोड़ रुपए लागत की इस परियोजना के पूर्ण होने पर मप्र के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र के 8 लाख 11 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा और प्रदेश की 44 लाख आबादी को पेयजल सुविधा प्राप्त होगी। साथ ही परियोजना से 103 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा, जिसका पूर्ण उपयोग मप्र करेगा। इस परियोजना से मप्र के 10 जिले-छतरपुर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा एवं सागर के लगभग 2 हजार ग्रामों के लगभग 7 लाख 25 हजार किसान परिवार लाभांवित होंगे। परियोजना से सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में भू-जल स्तर की स्थिति सुधरेगी। औद्योगिकीकरण, निवेश एवं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। इससे स्थानीय स्तर पर लोगों में आत्मनिर्भरता आएगी तथा लोगों का पलायन रुकेगा। परियोजना के साकार रूप लेने पर मप्र के बुंदेलखंड क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी। संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए मप्र और राजस्थान राज्यों एवं केंद्र के मध्य 28.01.2024 को त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ और दोनों राज्यों एवं केंद्र के मध्य 05.12.2024 को जयपुर में अनुबंध सहमति पत्र (मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट) हस्ताक्षरित किया गया।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

एक लाख कुओं को रिचार्ज करने का लक्ष्य

जल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश सरकार ने जल गंगा संवर्धन अभियान में भूजल पुनर्भरण के लिए डगवेल रिचार्ज विधि अपनाने का निर्णय लिया है। इसमें राज्य में एक लाख कुओं को रिचार्ज करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह पहल विशेष रूप से कृषकों को रबी की फसलों की सिंचाई हेतु स्थायी जल स्रोत उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगी। डगवेल रिचार्ज विधि उथले जलभृत के पुनर्भरण का एक सरल और सुलभ उपाय है। इस विधि में वर्षा जल को रिचार्ज पिट/फिल्टर के माध्यम से कुओं में प्रवाहित किया जाता है, जिससे भूगर्भीय जल स्तर में वृद्धि होती है। यह विधि भूजल स्तर बनाए रखने में मदद करती है और लंबे समय तक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। इस योजना में उन कुओं का चयन किया जाएगा, जिनमें जल स्तर 10 मीटर से अधिक है और जो बरसात के बाद दिसंबर-जनवरी तक जल युक्त रहते हैं। मनरेगा अंतर्गत निर्मित कपिलधारा कुओं को भी इस योजना में सम्मिलित किया जा सकता है, यदि उनमें पूर्व में रिचार्ज पिट का निर्माण नहीं हुआ है।

लाइन लॉस का भार ईमानदार उपभोक्ताओं पर

मप्र में देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे महंगी बिजली उपभोक्ताओं को मिल रही है। इसके बाद भी बिजली कंपनियां उसकी दरों को कम करने के उपायों पर काम करने की जगह लगातार बिजली की दरों में वृद्धि पर जोर देती रहती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है, लाइन लॉस को कम करने में बिजली कंपनियों का असफल रहना। इस मामले में तीनों कंपनियां विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय मानकों तक पर भी खरा नहीं उतर रही हैं। हालत यह है कि ट्रांसमिशन लॉस आयोग द्वारा तय किए गए लॉस से अधिक हो रहा है। यही वजह है कि बिजली कंपनियों को अधिक बिजली खरीदनी पड़ रही है। अतिरिक्त बिजली खरीदी से कंपनियों को 3 हजार करोड़ से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा है। दरअसल शहर हो या गांव सभी जगह झुग्गियों में जमकर अवैध रूप से बिजली का उपयोग किया जा रहा है। इसके बाद भी बिजली कंपनियों का अमला उन पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं दिखाता है। इसके उलट ईमानदार उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्ती दिखाकर अपनी पीठ जरूर थपथपा लेता है।

अगर राजधानी की ही बात की जाए तो दो दर्जन से अधिक ऐसी बस्तियां हैं, जहां पर खंभों या फिर ट्रांसफार्मर से सीधे बिजली के तार डालकर दिन-रात बिजली चोरी की जाती है। इस मामले में पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने जरूर अपने लॉस को कम किया है, जिससे कंपनी ने 861.28 मिलियन यूनिट बिजली की बचत की है। गौरतलब है कि तीनों बिजली कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिजली के वास्तविक आंकड़ों से संबंधित याचिका मप्र विद्युत विनियामक आयोग में लगाई है। इसमें बिजली कंपनियों ने अपना ट्रांसमिशन लॉस की जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि ट्रांसमिशन लॉस की वजह से मध्य और पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को अतिरिक्त बिजली खरीदना पड़ी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयोग ने पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के लिए 15.5 प्रतिशत, मध्य क्षेत्र के लिए 16.5 प्रतिशत और पश्चिमी क्षेत्र के लिए 14.5 प्रतिशत घाटे की अनुमति दी थी। इसके उलट वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूर्व क्षेत्र ने 28.04 प्रतिशत और मध्य क्षेत्र ने 25.7 प्रतिशत वितरण घाटा होने की जानकारी आयोग को दी है। पूर्व और मध्य क्षेत्र का वितरण घाटा तय लक्ष्य ये अधिक हुआ है। इस मामले में पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी ने ही बेहतर काम किया है। उसका लॉस 12.33 फीसदी ही हुआ है।

आयोग में दायर याचिका में बिजली कंपनियों ने बिजली खरीदी के आंकड़े भी उपलब्ध कराए हैं। घाटे की वजह से पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी 4,277.76 एमयू और मध्य क्षेत्र ने 3,711.57 एमयू अतिरिक्त मात्रा में बिजली खरीदी है। वितरण घाटा अधिक होने की वजह से बिजली कंपनियों को यह बिजली खरीदना पड़ी। वहीं, पश्चिम क्षेत्र ने 861.28 एमयू की बचत की है, क्योंकि उनका घाटा मानकों से कम है। इससे साफ होता है कि मध्य क्षेत्र को 4277.76 मिलियन यूनिट और पूर्व क्षेत्र को 3711.75 मिलियन यूनिट बिजली खरीदना पड़ी। कुल मिलाकर लगभग 800 करोड़ यूनिट ऊर्जा अतिरिक्त खरीदनी पड़ी और यदि इसकी लागत की गणना की जाए तो 4 रुपए प्रति यूनिट की दर पर लगभग 3200 करोड़ रुपए की खरीदी हुई। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर कंपनियां अपना यह घाटा कम कर लें, तो बिजली कंपनियों को घाटा नहीं होगा और बिजली का टैरिफ बढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ट्रांसमिशन लॉस आपूर्ति की गई बिजली और बिल किए गए बिजली के बीच का अंतर है, उदाहरण के लिए यदि 10 यूनिट ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है, और बिल केवल 8 यूनिट का बनता है, यानी केवल 8 यूनिट उपभोक्ताओं के मीटर तक पहुंचती है। उपभोक्ता तक पहुंचने में 2 यूनिट बिजली नष्ट हो जाती है। यह वितरण घाटा कहलाता है। वितरण घाटे के लिए मुख्य रूप से बिजली चोरी और बिजली के ट्रांसमिशन में टूट-फूट को जिम्मेदार ठहराया जाता है।

ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन (टीएंडडी) से होने वाली हानि को रोकने में देश में सफलता मिली है, लेकिन मप्र में बिजली कंपनियों का लाइन लॉस कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसको देखते हुए मप्र विद्युत विनियामक आयोग ने अब लाइन लॉस कम करने के दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। अगले चार साल में बिजली कंपनियों को 10 से 12 फीसदी तक लाइन लॉस कम करना होगा। कंपनियां लाइन लॉस में एक वित्तीय वर्ष में 3 फीसदी तक की कमी लाती हैं, तो उन्हें मरम्मत कार्य और रखरखाव के लिए 0.5 फीसदी अतिरिक्त राशि प्राप्त करने की पात्रता भी होगी। यह निर्देश भी विद्युत विनियामक आयोग ने जारी किए हैं। गौरतलब है कि टीएंडडी से होने वाली हानि को भारत के बिजली सेक्टर में सुधार की राह में सबसे बड़े अड़चन के तौर पर देखा जाता रहा है। हालांकि जो आंकड़े अब सामने आ रहे हैं, उससे साफ है कि इस समस्या पर काबू पाने में सफलता मिलने लगी है।

● **लोकेश शर्मा**

12 फीसदी तक कम करना होगा लाइन लॉस

मप्र विद्युत विनियामक आयोग ने साल 2023-24 से 2026-27 तक की गाइडलाइन बिजली कंपनियों के लिए जारी की है। इसके तहत आयोग ने अब लाइन लॉस कम करने के दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। अगले चार साल में बिजली कंपनियों को 10 से 12 फीसदी तक लाइन लॉस कम करना होगा। अगर बिजली कंपनियां अपना लाइन लॉस कम कर दें, तो कंपनियों को हर साल बिजली का टैरिफ बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बढ़ाने की जगह टैरिफ कम भी किया जा सकता है। आयोग ने बिजली कंपनियों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का लाइन लॉस सबसे ज्यादा रहता है। पिछले कई सालों से बिजली कंपनियां अपना लाइन लॉस कम नहीं कर पा रही हैं। साल 2021-22 में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का लाइन लॉस 27.40 फीसदी रहा था। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का लाइन लॉस सबसे कम 11.61 फीसदी रहा था। वहीं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का लाइन लॉस 24.67 फीसदी रहा था। गौरतलब है कि मप्र की तीनों बिजली कंपनियां हर साल घाटा दिखाकर बिजली की दरें बढ़ाने की मांग करती है। एक बार फिर बिजली प्रदेश के लोगों को झटका मारेगी, लेकिन प्रदेश के बाहर राहत देगी। यह कमाल नए टैरिफ में हुआ है।

अब पूरा होगा सूचना आयोग का कोरम

मप्र राज्य सूचना आयोग में खाली पड़े सूचना आयुक्तों के पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति हो सकती है। आयोग के सूत्रों ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद सरकार ने इस संबंध में पत्राचार किया है। हालांकि अभी नियुक्ति जैसी कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है। गौरतलब है कि मप्र में मुख्य सूचना आयुक्त समेत आयुक्त के 10 पद हैं। इन पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार ने पिछले साल मार्च एवं अप्रैल में आवेदन बुलाए थे। सरकार ने सितंबर 2024 में मुख्य सूचना आयुक्त एवं 3 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कर दी। इसके बावजूद मप्र सूचना आयोग में आयुक्तों के 7 पद खाली हैं।

गौरतलब है कि पिछले साल सितंबर में 5 महीने से खाली पड़े मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के पद पर सरकार ने चार नियुक्तियां कर दी हैं। सेवानिवृत्त डीजी विजय यादव को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। वहीं, शिक्षाविद् डॉ. उमाशंकर पचौरी, समाजसेवी डॉ. वंदना गांधी और सेवानिवृत्त जज ओमकार नाथ को सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। डॉ. पचौरी और डॉ. गांधी आरएसएस के सक्रिय स्वयंसेवक हैं। डॉ. पचौरी का नाता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी रहा है। बता दें कि मप्र सूचना आयोग करीब 160 दिन से खाली है। मार्च माह में ही सूचना आयुक्त के 10 पदों के लिए 185 और मुख्य सूचना आयुक्त के लिए 59 आवेदन आए थे। हालांकि इन चार पद के भरे जाने के बाद भी अभी 7 सूचना आयुक्त के पद रिक्त हैं। अभी यहां करीब 20 हजार आवेदन पेंडिंग हैं। कुछ आरटीआई कार्यकर्ताओं ने आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोर्ट में भी याचिका लगाई थी।

जानकारी के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में सूचना आयोगों में नियुक्तियों को लेकर आदेश जारी किया है। जिसमें सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से अगली सुनवाई से पहले सूचना आयोगों में नियुक्तियों को लेकर शपथ पत्र मांगा है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड सूचना आयोग में नियुक्तियों को लेकर लगाई गई याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया है। लेकिन इससे अन्य राज्य भी प्रभावित होंगे। अगली सुनवाई 4 मार्च को होना है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और विभिन्न राज्य सूचना आयोगों (एसआईसी) में रिक्त पदों की स्थिति का संज्ञान लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को पर्याप्त संख्या में आयुक्तों की नियुक्ति करने के लिए विशिष्ट और समयबद्ध निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने मुख्य सूचना आयुक्त के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के संयुक्त सचिव को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें कहा है कि चयन प्रक्रिया पूरी करने की समयसीमा बताई जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि जिन उम्मीदवारों ने आवेदन नहीं किया है, उन्हें नियुक्ति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा न्यायालय ने केंद्र सरकार को सर्च कमेटी के सदस्यों और उन उम्मीदवारों की सूची का खुलासा करने का निर्देश दिया है, जिन्होंने पूर्व के निर्देशों के अनुसार आवेदन किया है।

दरअसल न्यायालय ने झारखंड सूचना आयोग को लेकर सुनवाई की थी। झारखंड सूचना आयोग के 4 वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय रहने पर चिंता व्यक्त करते हुए न्यायालय ने विधानसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल को निर्देश दिया है कि वह अपने निर्वाचित सदस्यों में से किसी एक को मुख्य और सूचना आयुक्तों के पद पर चयन के लिए चयन समिति के सदस्य के रूप में नामित करे। कोर्ट ने सूचना आयुक्तों का चयन 9 सप्ताह के भीतर करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व प्रशांत भूषण और राहुल गुप्ता ने किया। अदालत ने आदेश दिया है कि मुख्य सूचना आयुक्त और आयुक्त पद के आवेदकों की सूची एक सप्ताह के भीतर अधिसूचित की जाए। आवेदकों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए निर्धारित मानदंडों के साथ खोज समिति की संरचना एक सप्ताह के भीतर अधिसूचित की जाए। साक्षात्कार पूरा करने की समयसीमा अधिसूचित की जाए। यह प्रक्रिया अधिसूचना की तारीख से छह सप्ताह से अधिक नहीं होगी। सिफारिशें प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी दो सप्ताह के भीतर जांच करके नियुक्तियां करेगा। साथ ही न्यायालय ने मुख्य सचिवों को अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने सभी राज्यों को रिक्त पदों का विवरण और प्रत्येक आयोग के समक्ष लंबित मामलों की संख्या का खुलासा करने का निर्देश दिया है।

● प्रवीण सक्सेना

शिकायतों का लगा अंबार

सूचना का अधिकार के अंतर्गत सूचनाएं न मिलने पर की जाने वाली अपीलों का निराकरण मप्र में धीमी गति से हो रहा है। आयोग में 15 हजार से अधिक अपील और शिकायतें लंबित हो गई हैं। दरअसल, सूचना आयुक्तों के 7 पद खाली हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आयोग में नियुक्तियां जल्द होंगी। इसके लिए प्रक्रिया चल रही है। बता दें कि नियुक्ति नहीं होने से आयोग में लगातार लंबित अपील और शिकायतों की संख्या बढ़ती जा रही है। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि प्रतिमाह 500 से अधिक अपील आती हैं। आयोग में द्वितीय अपील पर सुनवाई कर निर्णय होता है। वहीं, शिकायतों पर सीधे कार्रवाई की जाती है। आरटीआई एक्ट के मुताबिक राज्य और केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्त होते हैं, जो लोगों की शिकायतों और अपीलों पर फैसला सुनाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में मई 2020 से अब तक किसी भी सूचना आयुक्त की तैनाती नहीं की गई है। वहीं त्रिपुरा में तीन साल, तेलंगाना में 19 महीने और गोवा में सात महीने से सूचना आयुक्त नहीं है। यही हाल केंद्रीय सूचना आयोग का है। यहां भी मुख्य सूचना आयुक्त समेत सूचना आयुक्त हैं। इसके चलते सूचना आयोगों का काम प्रभावित हो रहा है।

आग से अन्नदाता हुए कंगाल

अशोकनगर में 1500 बीघा, श्योपुर में 300 बीघा, विदिशा में 200 बीघा, सिहोरा में 500 एकड़ आदि ये उन खेतों के आंकड़े हैं जिन पर लगी फसल एक चिंगारी से खाक हो गई। केवल इन्हीं जगहों पर नहीं बल्कि प्रदेश के सभी 55 जिलों में एक माह के अंदर करीब 5,430 आगजनी की वे घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें किसानों की हजारों एकड़ फसलें जल गई हैं। खेतों में खड़ी और पड़ी फसलों के जलने से अन्नदाता कंगाल हो गए हैं। अब वे सरकार से मुआवजे की आस लगाए बैठे हैं। अगर विगत वर्षों में आगजनी के बाद किसानों को मिले मुआवजे का आंकलन किया जाए तो मुआवजा किसानों का घाव और बढ़ा देता है।

गौरतलब है कि मप्र के अन्नदाता पर कभी प्राकृतिक आपदा तो कभी प्रशासनिक लापरवाही की मार पड़ रही है। इस समय प्रदेश में गेहूं की कटाई का मौसम है, लेकिन किसानों की खड़ी फसल पर एक बड़े संकट के रूप में आग का संकट मंडरा रहा है। प्रदेशभर में खड़ी फसल में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और किसानों के लिए यह किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। मप्र का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां आग लगने की घटनाएं सामने नहीं आई हैं। कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में पिछले एक माह के दौरान आगजनी की करीब 5,430 घटनाओं से किसानों की हजारों एकड़ फसल खाक हो गई है। इससे किसानों को करोड़ों रुपए की हानि हुई है। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार घटना होने पर राजस्व टीम मौके पर जाकर मुआयना करती है, पंचनामा तैयार कर, राजस्व गाइडलाइन के हिसाब से मुआवजा दिया जाता है।

प्रदेशभर में आगजनी से फसलें जलने के जो आंकड़े आ रहे हैं, वे चिंता बढ़ा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि पिछले एक दशक के दौरान पहली बार ऐसा हो रहा है, जब खेतों में आग लगने की घटनाएं इतनी अधिक हो रही हैं। राजधानी के सीमावर्ती सीहोर में मार्च महीने में आगजनी की 140 छोटी-बड़ी घटनाएं घटी हैं। इस दौरान किसानों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। ये आंकड़े जिले दमकल विभाग के अधिकारियों से मिले हैं। प्रदेश में इन दिनों रबी फसल की कटाई, गहाई का काम जोरों से चल रहा है। वहीं, अभी-अभी अधिकांश खेतों में किसानों की फसल पकी खड़ी है। ऐसे में बिजली लाइन से निकलने वाली एक चिंगारी पल भर में भीषण आग का रूप धारण कर लेती है। खेत के खेत मिनटों में जलकर राख हो जाते हैं। वहीं जिलेभर में मार्च महीने में 430 आगजनी की घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं में सबसे ज्यादा फसलों को क्षति पहुंची हैं। इसके साथ आवास, गृहस्थी, कृषि यंत्र, मवेशी आदि जलने से करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। प्रदेश में अग्नि सुरक्षा और राहत को लेकर कोई स्पष्ट नीति ही अब तक नहीं बनाई हैं। यदि किसान के खेत में आग लग जाए, तो फसल जलने पर लाखों रुपयों का नुकसान होता है। लेकिन किसान को फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पाता। इसकी वजह फसल बीमा की इकाई हल्का क्षेत्र होना है। जब पूरे पटवारी हल्के में आग से फसल जलेगी, तब प्रभावित किसानों को फसल का मुआवजा मिलेगा। अभी प्रशासन स्तर पर राजस्व अधिनियम के तहत राहत राशि दी जाती है, जो बहुत ही कम होती है।

प्रदेश के शहरों में तो सरकार ने फायर ब्रिगेड की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन गांवों में आग बुझाने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। जब आग लगती है तो जिला मुख्यालय पर सूचित किया जाता है, उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घटनास्थल की ओर रवाना होती हैं। अधिकांश अवसरों पर देखा गया है कि जब तक दमकल की गाड़ियां पहुंचती हैं, तब तक पूरी फसल नष्ट हो जाती हैं। विगत दिनों अशोकनगर में आग ने तांडव मचाया। बहादुरपुर तहसील इलाके में झागर बमुरिया, अमोदा कुकावली, हारूखेड़ी सहित 4 गांव के खेतों की फसल में आग लग गई। आग की लपटें धीरे-धीरे बढ़ती चली गई। ग्रामीणों ने शुरुआत में ही आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते आग भड़क गई। फिर लगभग 3 घंटे तक लोगों ने मशक्कत की और आग पर काबू पाया। इस आग ने 1500 बीघा की फसल को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उस इलाके में खड़ी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। पूरे इलाके में आग और धुएं का गुबार ही देखने को मिला। आग देखते ही 4 गांव के लोगों में चीख-पुकार मची हुई थी। लोगों ने भगवान से प्रार्थना की कि किसी तरह से उनकी फसल में लगी आग बुझ जाए, लेकिन आग लगातार बढ़ती गई। लोगों के पास जो भी संसाधन था, उन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आखिरी में अपने आप को बचाने की जद्दोजहद मच गई। फिर प्रशासन से मदद मांगी गई। काफी देर बाद धीरे-धीरे फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचने लगी। आग को बुझाते-बुझाते शाम हो गई, लेकिन तब तक किसानों ने जो 6 महीने मेहनत करके अपनी फसल तैयार की थी वह पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी।

● **विकास दुबे**

नरवाई जलाने वालों पर एफआईआर

जानकारों का कहना है कि खेतों में अधिकतर आग नरवाई जलाने के कारण लग रही है। ऐसे में नरवाई जलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। नरवाई की आग से फसल जलने के मामले में सागर जिले में पहली एफआईआर रहली थाने में दर्ज की गई है। जिले में गेहूं की कटाई चल रही है। खेत में कटाई के बाद लगी नरवाई जलाने के लिए किसान आग लगा रहे हैं। नरवाई की आग से आसपास के किसानों की फसलें जल रही हैं। जिसको लेकर प्रशासन एक्शन में आया है। दरअसल, 5 अप्रैल को जूना गांव में रामअवतार ने अपने खेत में फसल अवशेष (नरवाई) नष्ट करने के लिए आग लगाई थी। हवा चलने से आग फैली और आसपास के खेतों में खड़ी और कटी रखी गेहूं की फसल को चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण हुई कि जूना गांव से मंडला गांव तक पहुंच गई। जिससे करीब 20 एकड़ की गेहूं फसल जल गई। किसानों ने फायर फाइटर की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन आगजनी में फसल के साथ ही कृषि सामग्री जलकर नष्ट हो गई थी।

राजधानी भोपाल में मादक पदार्थों की तस्करी और सेवन के बारे में पुलिस के आंकड़ों से दो बेहद चिंताजनक पैटर्न सामने आए हैं। यहां नशे का कारोबार और युवाओं में नशा करने की लत बढ़ रही है। खासकर कॉलेज के छात्रों में गांजा नशे की लत लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी वजह है कि गांजा आसानी से और कम दाम में मिल जाता है। वहीं, गरीब और स्लम एरिया में रहने वाले लोग गांजा तस्करी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। भोपाल पुलिस लगभग हर दिन ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर रही है। इसके साथ ही पुलिस बड़ी मात्रा में गांजा जब्त कर रही है। सीनियर पुलिस अधिकारियों ने कहा कि झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले कई लोग गांजा तस्करी की ओर रुख कर रहे हैं। इसकी वजह है कि इसमें कम पैसा लगाना पड़ता है और आठ से दस गुना अधिक लाभ मिलता है। इसके साथ ही युवाओं के बीच गांजे की मांग भी बहुत ज्यादा है, जो एक बड़ी समस्या है।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि भोपाल में गांजा कई जगहों पर आसानी से मिल जाता है। गौतम नगर, इतवारा, पिपलानी, हबीबगंज, कोलार, बरखेड़ी, पंचशील नगर, सतनामी नगर, निशातपुरा, हनुमानगंज, छोला और कई अन्य झुग्गी-झोपड़ियों सहित कई इलाकों में गांजा आसानी से उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि शहर में गांजा तस्करी का धंधा बहुत बढ़ गया है। शहर में कई पान की दुकानों पर खाली सिगरेट की ट्यूब आसानी से मिल जाती है। उन्होंने कहा कि युवा इन खाली सिगरेट की ट्यूब का इस्तेमाल गांजा पीने के लिए करते हैं। पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्रा ने कहा कि ज्यादातर मामलों में गांजा ओडिशा और तेलंगाना से तस्करी करके लाया जाता है। उन्होंने कहा कि छात्रों को गांजा आसानी से और कम दाम में मिल जाता है। उन्होंने यह भी माना कि गांजे की आसानी से उपलब्धता और कम कीमत के कारण कई युवा इसकी लत का शिकार हो रहे हैं। कई कॉलेज छात्र नींद से बचने और पढ़ाई के दौरान अपना ध्यान बढ़ाने के लिए गांजा पीते हैं। वे आसानी से पकड़े नहीं जाते और इसके हानिकारक प्रभावों को नहीं समझते, बल्कि इसके तुरंत मिलने वाले आनंद पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह अन्य नशीले पदार्थों का एक आसान विकल्प बन जाता है और उनके लिए नशे से निपटने का एक तरीका बन जाता है।

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि एमडीएमए, एम-कैट, एक्स्टसी, एलएसडी, स्मैक, हेरोइन, ब्राउन शुगर और अन्य जैसे केमिकल ड्रग्स बहुत महंगे होते हैं। इसलिए इनमें से अधिकांश युवा इन्हें खरीद नहीं पाते। इसकी जगह कफ सिरप और अल्प्राजोलम, नाइट्रावेट जैसी साइकोट्रोपिक गोलियां भी अवैध रूप से मेडिकल स्टोर्स के माध्यम से बेची जा रही है। कई मामलों में पाया गया कि अपराधी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते समय नाइट्रावेट गोलियों के नशे में थे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ड्रग्स बेचने वाले अब एनडीपीएस कानून के बारे में भी जान गए हैं। एनडीपीएस कानून ड्रग्स से जुड़े अपराधों के लिए बनाया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ड्रग्स बेचने वाले अब 1 किलो से ज्यादा गांजा नहीं रखते। वे जानते हैं कि अगर उनसे कम मात्रा में गांजा बरामद होगा तो उन्हें आसानी से जमानत मिल जाएगी। पुलिस ने बताया कि पिछले कुछ सालों में कार्रवाई के कारण कई पुराने ड्रग्स बेचने वालों ने यह काम छोड़ दिया था। लेकिन अब कई नए लोग आसानी से पैसा कमाने के लिए उनकी जगह आ गए हैं। पुलिस का कहना है कि ये लोग ज्यादातर गरीब परिवारों से हैं और झुग्गी-बस्तियों में रहते हैं। पुलिस का मानना है कि बार, पब और देर रात तक चलने वाली पार्टियों के कारण भी ड्रग्स का सेवन बढ़ रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पहले गांजा बेचने वालों की संख्या लगभग एक दर्जन थी। लेकिन अब यह संख्या बहुत बढ़ गई है। पब और रेस्टोरेंट में देर रात तक चलने वाली पार्टियों में केमिकल ड्रग्स जैसे एमडीएमए का सेवन बढ़ गया है। युवा ऐसी पार्टियों में ड्रग्स बेचने वालों के शिकार हो जाते हैं। उन्हें मुफ्त में या कम दाम पर ड्रग्स दिए जाते हैं। जब उन्हें लत लग जाती है, तो उन्हें या तो ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। इसके अलावा वे अपने दोस्तों को भी ड्रग्स लेने के लिए मनाना पड़ता है ताकि उन्हें कम दाम पर ड्रग्स मिल सके।

केमिकल ड्रग्स का नेटवर्क बहुत गुप्त होता है और इन ड्रग्स की तस्करी कम मात्रा में की जाती है। इसलिए पुलिस के लिए इन मामलों को सुलझाना मुश्किल हो जाता है। पुलिस ड्रग्स बेचने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और ड्रग्स की सप्लाई चेन को तोड़ने पर ध्यान दे रही है। सप्लाई चेन का मतलब है ड्रग्स कहां से आ रहा है और कैसे बेचा जा रहा है, इस पूरे नेटवर्क को तोड़ना। पुलिस ने बताया कि पहले गांजा तस्करों की संख्या करीब एक दर्जन थी, लेकिन अब इनकी संख्या में काफी वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि पब और रेस्टोरेंट में देर रात तक चलने वाली पार्टियों की बढ़ती संस्कृति ने एमडीएमए और अन्य रासायनिक दवाओं की खपत को बढ़ा दिया है।

● **बृजेश साहू**

तस्करों के जाल में ऐसे फंस रहे युवा

युवा ऐसी पार्टियों में ड्रग तस्करों के झांसे में आ जाते हैं और उन्हें मुफ्त या कम दरों पर ड्रग्स की खुराक दी जाती है। जब वे नशे के आदी हो जाते हैं, तो उन्हें या तो अधिक कीमत चुकाने के लिए मजबूर किया जाता है या अपने दोस्तों को इन दवाओं के सेवन की आदत में फंसाया जाता है ताकि उन्हें कम दरों पर ड्रग्स की आपूर्ति की जा सके। कमिश्नर ने कहा कि रासायनिक ड्रग नेटवर्क बहुत ही करीबी सर्किट में आपूर्ति किए जाते हैं और इन दवाओं की तस्करी कम मात्रा में की जाती है, जिससे पुलिस के लिए उनके मामलों को सुलझाना और भी मुश्किल हो जाता है। पुलिस ड्रग तस्करों के खिलाफ नियमित कार्रवाई कर रही है, जिसमें सप्लाई चेन को तोड़ने पर ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि शहर में ड्रग्स का कारोबार बंद हो। इसके लिए लोगों को भी जागरूक होना होगा और अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा। अगर किसी को ड्रग्स से जुड़ी कोई जानकारी मिलती है, तो उसे तुरंत पुलिस को बताना चाहिए। साथ मिलकर ही इस समस्या से निपटा जा सकता है।

मानव छीन रहा मादा चीता के मुंह से शिकार

क्या मानव को प्रकृति में बाधक बनना चाहिए? क्या वन्य जीवों के जीवन में व्यवधान पैदा करना चाहिए? संभवत: सभी का उत्तर नहीं होगा, लेकिन मानव वन्य जीवों के जीवन में निरंतर व्यवधान पैदा कर रहे हैं। ताजा उदाहरण मप्र के श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क का है, जहां ग्रामीणों ने मादा चीता ज्वाला को दो बार शिकार करने से रोका। मादा चीता अपने चार शावकों को लेकर निकली थी, हालांकि कुछ लोग यह बेतुका तर्क दे सकते हैं कि ग्रामीणों ने दो पालतू जानवरों की जान बचाई, लेकिन यदि शिकार न मिलने के कारण भूख से मादा चीता और उसके शावक मर जाएं तो उसका दोषी कौन होगा? वैसे भी चीता के लिए शिकार पकड़ना आसान नहीं होता है।

कुछ साल पहले उप्र के सहारनपुर में एक सड़क पर अजगर ने एक हिरण को जकड़ लिया था। एक युवा ने झाड़ी मार-मारकर अजगर को हिरण छोड़ने के लिए विवश कर दिया था। तब भी एक बहस चली थी कि क्या हमें प्रकृति और वन्यजीवों के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए? अजगर भी उन प्राणियों में शामिल है, जिसे बेहद मुश्किल से शिकार मिलता है, लेकिन अक्सर सोशल मीडिया पर हम ऐसे वीडियो देखते हैं, जहां अजगर को पकड़कर उसके शिकार को पेट से बाहर तक निकाल दिया जाता है। कूनो नेशनल पार्क में भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चीता चल रहा है। अफ्रीका से लाकर यहां पर चीते छोड़े गए हैं। भारत सरकार की कोशिश है कि देश में साल 1948 में ही विलुप्त हो चुके इस दुर्लभ जीव को पुनर्स्थापित किया जाए, लेकिन क्या हम ऐसा होने देने के इच्छुक हैं?

श्योपुर की घटना को ही ले लें। मादा चीता ज्वाला अपने चार शावकों के साथ कूनो नेशनल पार्क से निकलकर 30 किलोमीटर दूर वीरपुर क्षेत्र में पहुंच गई थी। वहां पर उसने एक बार बछड़े को दबोचा तो दूसरी बार भैंस के पाड़े को पकड़ने का प्रयास किया। दोनों बार ग्रामीणों ने लाठियों के बल पर मादा चीता ज्वाला को विवश किया कि वो शिकार को छोड़कर भाग जाए। ग्रामीणों ने इतना शोर मचाया कि मादा चीता और शावकों को लेकर जंगल में भागना पड़ा। हद तो यह थी कि कुछ ग्रामीणों ने वन्यजीवों पर पथराव तक कर दिया। कूनो नेशनल पार्क से जुड़े वन्य अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि चीता कभी मानव पर हमला नहीं करता है। फिर भी श्योपुर में लोग न जाने क्यों घबराए हुए हैं? लगता है, उन्हें यह तथ्य पता नहीं है। वो तो गनीमत रही कि मादा चीता और शावकों को ग्रामीण ने लाठी-डंडों से मार नहीं डाला। मानव और वन्यजीवों का द्वंद्व नया नहीं है। यह आदिकाल से चला आ रहा है। अब तो स्थिति यह हो गई है कि हमने जंगल खत्म कर डाले हैं। वन्यजीवों को बचाने के लिए सरकार को जंगल बनाने पड़ रहे हैं। इन जंगलों में भी मानव का हस्तक्षेप खत्म नहीं हो रहा है। जंगल में वन्यजीवों को शिकार नहीं मिलता तो वो मानव बस्तियों में आ जाते हैं।

हम भले वन्यजीवों से किसी शिकार को छुड़ाकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करें, लेकिन उस वन्यजीव का भी सोचिए, जिसको भोजन से वंचित किया गया है। विशेष कर यदि वन्यजीव मांसाहारी है तो उसे भोजन कहां से मिलेगा? वन्यजीव से शिकार को छुड़ाकर मानव कोई उपकार या पुण्य का कार्य तो कर नहीं रहा है, बल्कि वो प्रकृति के नियम को तोड़ रहा है। देश में वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर कानून बने हुए हैं, जिनमें सजा का प्रावधान है, लेकिन वन्यजीवों से शिकार छुड़ाने का जिक्र अभी कानून में नहीं है। सरकार को कानून में संशोधन कर इस विषय को भी जोड़ना चाहिए। साथ ही, सरकार को जन-जागरूकता निरंतर लाने की आवश्यकता है। पाठ्यक्रम में शुरुआत से वन्यजीवों को लेकर पढ़ाया जाए और बच्चों को यह सिखाया जाए कि प्रकृति वन्यजीवों के बिना अधूरी है। फिर चीता तो एक दुर्लभ वन्यजीव है। पूरी दुनिया में इनकी संख्या 7000 के करीब ही बची है। भारत में तो यह 77 साल पहले ही समाप्त हो गए थे। एक बार पुन: इन्हें भारत में स्थापित करने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन जो घटना श्योपुर में हुई है, वो चिंताजनक है। सरकार को ऐसी घटनाओं को लेकर सख्त कदम उठाने चाहिए, ताकि मानव वन्य जीवों के जीवन में व्यवधान पैदा न कर सके।

मप्र के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में चीतों की संख्या बढ़ने के साथ ही उनके आहार के लिए चीतलों की व्यवस्था उनका प्रजनन बढ़ाकर की जाएगी। इसके लिए कूनो क्षेत्र के बागचा गांव में 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल में चीतल का ब्रीडिंग एन्क्लोजर (प्रजनन के लिए बाड़ा) तैयार किया जा रहा है। कूनो प्रबंधन के अनुसार, इसका 70 प्रतिशत से ज्यादा काम पूरा हो गया है। इसमें इतने अधिक संख्या में चीतल का प्रजनन कराने की तैयारी है, जितने चीतों के लिए वर्षभर पर्याप्त आहार का इंतजाम हो जाए। दरअसल, कूनो पार्क में चीतों की संख्या 26 हो गई है। इसमें से 17 चीते जंगल में विचरण कर रहे हैं, लेकिन कूनो में आहार की पर्याप्त उपलब्धता न होने की वजह से वे भटककर आबादी क्षेत्र में जा पहुंचते हैं। पिछले 15 दिन में ही दो बार ऐसा हुआ है। ऐसे में, चीतों को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कूनो पार्क में घूम रहे 17 चीतों में शामिल ज्वाला चीता अपने चार शावकों के साथ विजयपुर स्थित श्यामपुर गांव पहुंच गई है। उसने किसान के खेत में बंधी छह बकरियों का शिकार किया। इससे कुछ दिन पहले भी चीता ने गांव में बछड़े का शिकार करने का प्रयास किया था, हालांकि ग्रामीणों द्वारा पथराव करने पर चीते भाग गए।

● **धर्मेंद्र कथूरिया**

ब्रीडिंग एन्क्लोजर का अधिकांश काम पूरा

सिंह परियोजना के निदेशक उत्तम कुमार शर्मा के अनुसार, चीता प्रोजेक्ट के तहत 2023 में विस्थापित किए गए बागचा गांव के 50 हेक्टेयर क्षेत्र में चीतल के ब्रीडिंग एन्क्लोजर का अधिकांश काम पूरा हो चुका है। इससे छह माह के ब्रीडिंग सीजन में काफी संख्या में चीतल जंगल में छोड़े जा सकेंगे। बता दें कि कूनो में चीतों के अलावा तेंदुए व अन्य वन्यजीव भी चीतल का शिकार करते हैं। खुले जंगल में घूम रहे चीतों के आए दिन आबादी क्षेत्र में पहुंच जाने से न सिर्फ उनकी सुरक्षा को खतरा है, बल्कि ग्रामीण भी इनसे भयभीत होते हैं। इस बीच, श्योपुर जिले के विजयपुर तहसील क्षेत्र स्थित डोब गांव का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक ग्रामीण सत्या गुर्जर चीतों को पानी पिलाता दिख रहा है।

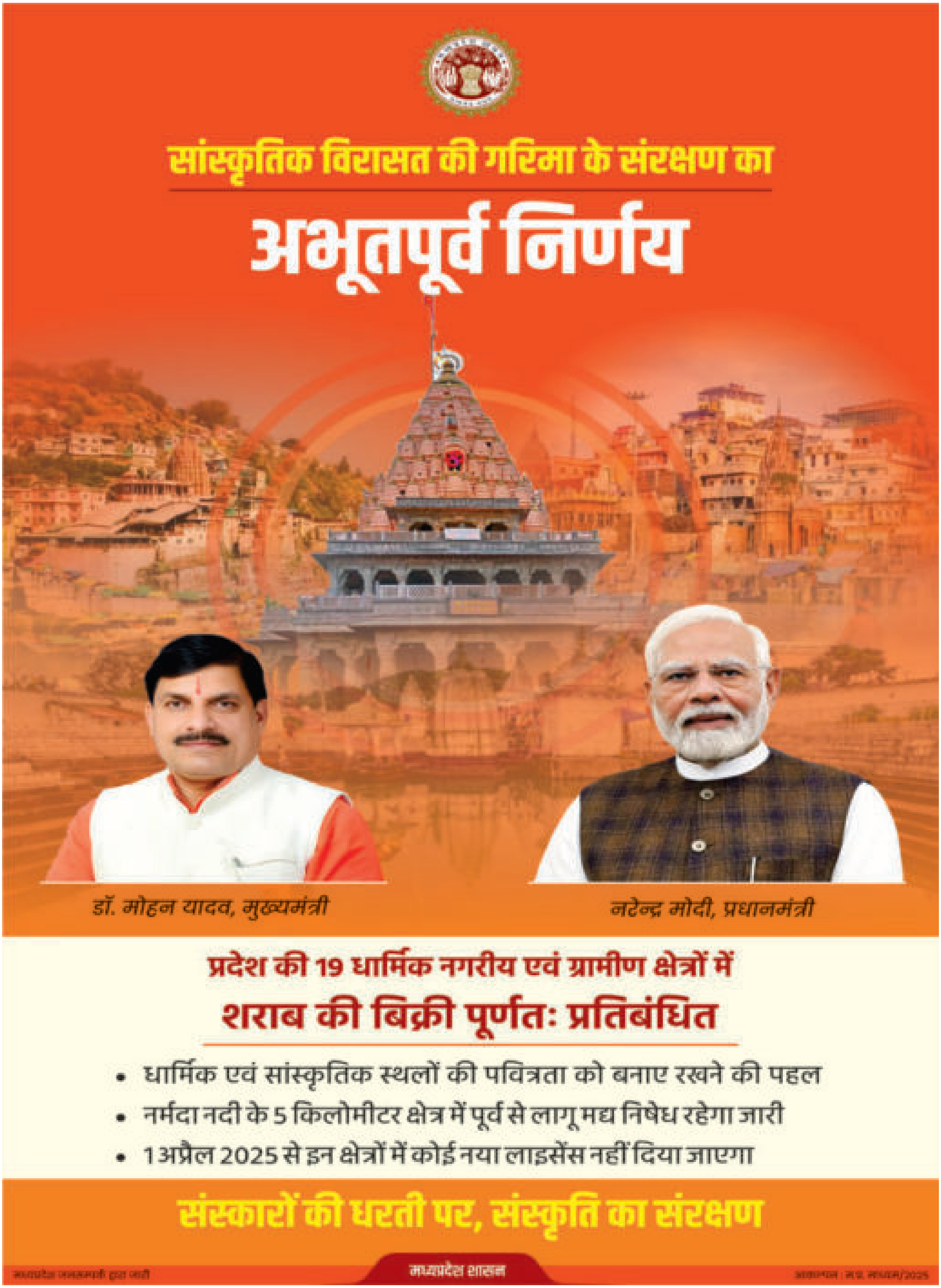
सांस्कृतिक विरासत की गरिमा के संरक्षण का
अभूतपूर्व निर्णय
डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री
नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री
प्रदेश की 19 धार्मिक नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में
शराब की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित
• धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों की पवित्रता को बनाए रखने की पहल
• नर्मदा नदी के 5 किलोमीटर क्षेत्र में पूर्व से लागू मद्य निषेध रहेगा जारी
• 1 अप्रैल 2025 से इन क्षेत्रों में कोई नया लाइसेंस नहीं दिया जाएगा
संस्कारों की धरती पर, संस्कृति का संरक्षण
मध्यप्रदेश शासन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की रणनीतिक कूटनीति के कारण आज भारत की पूरे विश्व में तूती बोल रही है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विश्व के शक्तिशाली देश अमेरिका हो या रूस या अन्य कोई देश, सबकी कोशिश यही रहती है कि भारत से उसके संबंध मधुर रहें। यही नहीं अमेरिका में तो प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप जबसे राष्ट्रपति बने हैं, तबसे इंडिया और पावरफुल हुआ है। इंडिया की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने मुंबई हमलों में वांछित पाकिस्तानी मूल के कनाडाई आतंकी तहव्वुर राणा को भारत को सौंपने में तनिक भी देरी नहीं की।

● राजेंद्र आगाल

कुशल रणनीति, सार्थक नीति और कूटनीति को हथियार बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह विश्व समुदाय को साध रहे हैं, उससे भारत विश्व में शांति, सद्भाव और संगठित नेतृत्व की ऐसी ताकत बन गया है, जिसका लोहा आज पूरा विश्व मान रहा है। विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका हो या भारत के पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या म्यांमार, सब भारत की ओर अपेक्षा की नजर से देख रहे हैं। इसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कूटनीति से विश्व की सारी ताकतों को साध लिया है। इसी का परिणाम अभी हाल ही में देखने को मिला, जब मोदी सरकार की पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण के मामले में बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले के 17 साल बाद आखिरकार वो वक्त मोदी सरकार के दौरान ही आया, जब हमले का मास्टरमाइंड अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद भारत लाया गया है।

अगर मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल को देखें तो भारत अपनी कूटनीति के कारण विश्व में एक ताकतवर देश के रूप में उभरा है। आज भारत विश्वभर में एक पोषक राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है। रूस-यूक्रेन युद्ध हो, या इजराइल-हमास युद्ध हो, या फिर किसी देश में आया कोई संकट, हर मोर्चे पर भारत ने अपनी छाप छोड़ी है। मोदी की कूटनीति का ही नतीजा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अपनी प्राथमिकता में रखा है और प्रधानमंत्री मोदी को अपना सबसे करीबी दोस्त माना है। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जुगलबंदी का ही नतीजा है कि अमेरिका के ट्रैरिफ वॉर से आज चीन की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। जब वर्तमान में पूरा विश्व अमेरिका के टैरिफ वॉर से परेशान है, ऐसी स्थिति में अमेरिका से वांछित पाकिस्तानी मूल के कनाडाई आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाने में कामयाबी मिली है।

17 साल बाद कैद में दोषी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण के मामले में बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। मुंबई के 26/11 आतंकी हमले के 17 साल बाद आखिरकार वो वक्त मोदी सरकार के दौरान ही आया, जबकि हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद भारत लाया गया है। मुंबई हमलों में 175 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। यह भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। 64 वर्षीय राणा मुंबई हमले के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली का करीबी सहयोगी रहा है। पाकिस्तानी आतंकी तहव्वुर राणा दुबई के रास्ते मुंबई आया था और 11 नवंबर 2008 से 21 नवंबर 2008 तक पवई के होटल रिनैसां में ठहरा था। इस दौरान उसने हमले से जुड़े सारे ठिकानों और इंतजामों का जायजा लिया। हर टारगेट स्थल की बारीकी से रेकी की। और उसके जाने के ठीक 5 दिन बाद 26 नवंबर को मुंबई में आतंकी हमला हो गया। तहव्वुर राणा के भारत आने से अब पाकिस्तान की परेशानी बढ़ जाएगी। हालांकि तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की राह आसान नहीं थी और मुंबई हमले के साजिशकर्ता राणा ने अपना प्रत्यर्पण रोकने की हरचंद कोशिशें कीं, लेकिन भारत की मोदी सरकार के कूटनीतिक प्रयासों के सामने उसकी एक न चली। यही वजह है कि तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को देश की कूटनीति की बड़ी जीत माना जा रहा है। न्यूज एजेंसी एनआईए ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि तहव्वुर राणा को भारत लाना काफी मुश्किल था, लेकिन दो तथ्यों ने आतंकी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को आसान बना दिया।

तहव्वुर राणा एक पाकिस्तानी-कनाडाई नागरिक है, जो पाकिस्तानी सेना में भी काम कर चुका है। तहव्वुर राणा को आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करने के लिए दोषी पाया गया था। वह साल 2009 से अमेरिका की जेल में बंद था। अब भारत लाकर उसे 2008 के मुंबई हमले के मामले में न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। केंद्र सरकार ने नरेंद्र मान को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है, जो एनआईए की तरफ से सुनवाई में शामिल होंगे।

प्रधानमंत्री मोदी के ट्रंप से अच्छे रिश्ते काम आए

तहव्वुर राणा का भारत प्रत्यर्पण भारत की बढ़ती हुई कूटनीतिक पहुंच, इसके अमेरिका के साथ मजबूत संबंधों का सबूत है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूर्व की बाइडन सरकार या मौजूदा ट्रंप सरकार दोनों ने ही तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी। ट्रंप ने तो अपने एक बयान में साफ कर दिया था कि तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा। तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण में कई बार मुश्किलें भी आईं, लेकिन भारत ने अमेरिका के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों का फायदा उठाते हुए उन मुश्किलों को समाप्त कर दिया। पहला फैक्टर है कानूनी दांव-पेच, दरअसल तहव्वुर राणा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दोहरे खतरे सिद्धांत का हवाला दिया था। इसके तहत किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। तहव्वुर राणा ने तर्क दिया कि मुंबई आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में वह अमेरिका में सजा काट चुका है। ऐसे में उसे अब भारत प्रत्यर्पित करना दोहरे खतरे के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। हालांकि भारत का प्रतिनिधित्व मोदी सरकार की एक मजबूत कानूनी टीम कर रही थी, जिसने अपने तर्कों से तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण से बचने की हर कोशिश को नाकाम कर दिया। मुंबई आतंकी हमले के दौरान ऑपरेशन का हिस्सा रहे पूर्व एनएसजी कमांडो और अब भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह ने कहा कि यह देश के लिए बड़ा दिन है। मैं प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति और इस प्रत्यर्पण प्रक्रिया में शामिल एजेंसियों को धन्यवाद देता हूं। जब उसे फांसी दी जाएगी, तो यह न केवल आतंकवाद पर बल्कि पाकिस्तान पर भी करारा तमाचा होगा।

यह मोदी का नया भारत है

मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण पर भाजपा नेता तरुण चुघ ने कहा, यह एक स्वागत योग्य कदम है। यह भारत और भारत की सोच की जीत है। अब यह दुनिया भी मानने लगी है कि भारत के नागरिकों पर हमला करने वाले लोग विश्व के किसी भी कोने में छिप जाएं, उन्हें पकड़ कर लाया जाएगा और कानून संगत सजा भी दी जाएगी। यह प्रधानमंत्री मोदी का नया भारत है। आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने भी इसे स्वागत योग्य कदम बताया। उन्होंने कहा कि देश उस बर्बर हिंसा को भूला नहीं है। इसलिए मुंबई हमलों में मारे गए लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी, जब हमले में शामिल आतंकी तहव्वुर राणा को कड़ी सजा मिलेगी।

फांसी के फंदे तक पहुंचाएंगे!

मुंबई हमले में सबसे बड़ा सबूत खुद आतंकी डेविड हेडली बन गया था। वह अमेरिका कोर्ट में इस मामले में अपने जुर्म को स्वीकार कर चुका है। भारत ने पड़ताल में यह साबित कर दिया है कि तहव्वुर राणा उसी मास्टरमाइंड डेविड हेडली का खास सहयोगी है। भारतीय जांच एजेंसियों की ओर से जुटाए गए सबूत तहव्वुर राणा के गले

पूरी दुनिया में सुनाई दे रही भारत की धमक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की धमक पूरी दुनिया में सुनाइ पड़ रही है। मोदी सरकार के कूटनीतिक दबावों का असर है कि पाकिस्तान अब मुंबई हमले के आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार हुआ है। कुछ समय पहले पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने पहली बार स्वीकार किया कि मुंबई में हुए 26/11 हमले में पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ था। अब तहव्वुर राणा के पाकिस्तान कनेक्शन एक बार फिर खुलकर सामने आएंगे। ऐसे में आतंक के आका पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एफआईए ने माना है कि ताज होटल पर हुए हमले लश्कर-ए-तैयबा के 11 आतंकवादियों ने योजनाबद्ध तरीके से किए थे। पाकिस्तान ने इन आतंकवादियों को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया है और इनकी नई सूची तैयार की है। साथ ही कड़ी कार्रवाई का फैसला लिया है। एफआईए के मुताबिक हमले के लिए बोट खरीदने वाले आतंकवादी मुल्तान के मोहम्मद अमजद खान के अब भी देश में होने की बात को पाकिस्तान ने स्वीकार लिया है। इसे भी तब भारत की बड़ी कामयाबी माना गया था। इसके अलावा मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली के भी मुंबई अटैक से जुड़े होने के सबूत मिले थे। नई सूची में 26/11 हमलों को लेकर जानकारी दी गई है कि नाव में 9 आतंकवादी सवार थे। इनके नाम हैं साहिवाल जिले के मोहम्मद उस्मान, लाहौर जिले के अतीक-उर-रहमान, हाफिजाबाद के रियाज अहमद, गुजरांवाला जिले के मुहम्मद मुश्ताक, डेरा गाजीपुर जिले के मुहम्मद नईम, सरगोधा जिले के अब्दुल शकूर, मुल्तान के मुहम्मद साबिर, लोधरान जिले का मोहम्मद उस्मान, रहीम यार खान जिले के शकील अहमद है। इन सभी का नाम संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध किए गए आतंकी ग्रुप में शामिल हैं जो कि लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी हैं।

में ऐसा फंदा बनकर फंसे कि उसे भारत तक खींच लाए। भारत में उसे तिहाड़ जेल में रखा जा सकता है। यहां पर उससे मुंबई हमले को लेकर पूछताछ होगी और पाकिस्तान का आतंकवाद वाला राज फिर सामने आ सकता है। इस जांच के दौरान जो अहम सबूत जांच एजेंसियों के हाथ लगे, इन्हें देखकर एक बारगी तो खुद आरोपी और अमेरिकी अदालत दोनों हिल गए। दरअसल, तहव्वुर राणा पाकिस्तान फौज में डॉक्टर रह चुका है। फौज से निकलने के बाद भी वह लगातार बड़े अधिकारियों, आतंकियों और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का करीबी बना हुआ था। इतना ही नहीं तहव्वुर राणा मुंबई हमले को अंजाम देने वाले गुनहगारों के संपर्क में भी काफी समय से था। इन सबूतों में वो ईमेल भी शामिल थे, जिन्हें गुनहगार राणा ने भारत और अन्य जगहों से पाकिस्तान भेजे थे। यह ऐसा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस था, जिसका कोई तोड़ इस आतंकवादी के पास नहीं है। दस्तावेज की सबूतों में जांच एजेंसियों के पास तहव्वुर राणा के आठ बार भारत आने के सबूत हैं। साथ ही वह कोच्चि, अहमदाबाद, दिल्ली, आगरा और मुंबई गया था। जिन जगहों पर रुका था उसके भी सबूत हैं। इसमें सबसे बड़ा सबूत मुंबई के ताज होटल का था, जिसमें हमले के कुछ दिन पहले वह रुका था। तहव्वुर राणा ने ताज होटल की पूरी रेकी की थी। जिन जगहों के फोटो खींचकर उसने आतंकवादियों तक पहुंचाए थे, वह ईमेल भी जांच एजेंसी के हाथ लगा है। जांच एजेंसी वह दस्तावेज भी खोज चुकी है, जिसमें तहव्वुर राणा जब आठ बार भारत आया तो उसने 231 बार इस मामले के दूसरे आरोपी डेविड हेडली से बात की थी। अब भारत के दबाव में आतंक के आका पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ेंगी।

टैरिफ वॉर में भारत सेफ

अमेरिका में जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली थी, तभी यह स्पष्ट हो गया था कि वह राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाएंगे, जो विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेंगे। पहले उन्होंने तमाम सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, फिर यूएसएड के तहत दी जाने वाली सहायता रोकी। इससे अमेरिका में चल रही फिजूलखर्ची और भ्रष्टाचार का पता चला। इसके बाद उन्होंने विभिन्न देशों पर टैरिफ यानी आयात शुल्क लगाना शुरू किया। पहले उन्होंने कनाडा, मेक्सिको, चीन पर टैरिफ बढाया, फिर भारत समेत बाकी सब देशों पर। बढ़ी हुई टैरिफ दरें 9 अप्रैल से लागू करने की घोषणा कर उन्होंने विश्व अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल मचा दी। उन्होंने किसी देश पर 10 तो किसी पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया। उनके इस मनमाने फैसले के जवाब में चीन ने भी अमेरिका पर टैरिफ बढ़ा दिया। इस पर ट्रंप ने चीन पर टैरिफ और बढ़ा दिया। इसी के साथ बाकी देशों पर लगाए टैरिफ को 90 दिनों के लिए स्थगित करते हुए सभी को 10 प्रतिशत टैरिफ के दायरे में ले आए। टैरिफ को लेकर अमेरिका-चीन के बीच वार-पलटवार का बचकाना और हास्यास्पद सिलसिला अब भी कायम है। टैरिफ पर 90 दिनों की राहत के ट्रंप के फैसले के पहले ही दुनियाभर के शेयर बाजार लड़खड़ा चुके थे। ट्रंप की मानें तो तमाम देशों ने टैरिफ पर उनसे बात करने की गुहार लगाई है। वह जहां अन्य देशों से टैरिफ पर बात करने को तैयार दिख रहे, वहीं चीन को सबक सिखाने पर आमादा हैं, लेकिन अब चीन एक बड़ी आर्थिक ताकत बन चुका है। उसका सामान अमेरिका समेत दुनियाभर में निर्यात होता है। इसीलिए उसे विश्व का कारखाना कहा जाता है। यह हैरानी की बात है कि ट्रंप एक कारोबारी हैं और फिर भी यह समझने को तैयार नहीं कि यदि पिछले वर्षों में अमेरिका के कारखाने अन्यत्र स्थानांतरित हो गए तो उसका कारण अमिरका में श्रम का महंगा होना था। खुद अमेरिकी कारोबारी ज्यादा मुनाफे के लिए अपने कारखाने अन्य देशों में ले गए। इससे अमेरिका के लोगों को सस्ता सामान मिलने लगा। भले ही ट्रंप यह मानकर चल रहे हों कि अब वे सब कारखाने अमेरिका ले आएंगे, जो बाहर चले गए थे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। कारखाने रातोंरात नहीं लगते और यदि कुछ छोटे कारखाने लग भी जाएं तो महंगे श्रम के कारण उनमें तैयार वस्तुएं अन्य देशों में उत्पादित वस्तुओं के मुकाबले मंहगी होंगी। आखिर जो सामान विश्व के अन्य देशों में सस्ते में बन सकता है, उसे अमेरिका में महंगा बनाकर वहां के कारोबारी क्या हासिल कर लेंगे। पता नहीं किस अर्थशास्त्री ने ट्रंप को यह समझाया कि वह टैरिफ बढ़ाकर राजकोषीय घाटा कम कर लेंगे?

60 और अपराधियों का प्रत्यर्पण

आतंकी तहव्वुर राणा ही नहीं, मोदी सरकार के पिछले पांच साल के कार्यकाल में ही राणा समेत 24 खूंखार अपराधी और भगोड़ों को प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया है। दरअसल, भारत की दुनिया के 48 देशों से प्रत्यर्पण संधि है। इन देशों से भारत ने 178 वांछित अपराधियों को प्रत्यर्पित करने का अनुरोध कर रखा है जिनमें 60 मामले तो अकेले अमेरिका के ही हैं। वर्ष 2015 से 2024 तक 60 और भगोड़ों को प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया है। कराची में रह रहा 1993 के मुंबई बम विस्फोट का आरोपी डॉन दाऊद इब्राहिम भारत में वांछित है। पाक से प्रत्यर्पण संधि नहीं होने से उसे लाने की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पाई है। आतंकवाद और आतंकियों के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुरू से ही जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। जिसमें तहव्वुर राणा को उनके प्रधानमंत्रित्व काल में प्रत्यर्पण करके लाया गया है। नरेंद्र मोदी के रडार पर तो राणा तभी से था, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण और रिमांड पर भेजे जाने के बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साल 2011 का पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री ने तत्कालीन यूपीए सरकार की विदेश नीति की आलोचना करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (तब ट्विटर) पर पोस्ट कर लिखा था, अमेरिका द्वारा मुंबई हमले में तहव्वुर राणा को निर्दोष घोषित करना भारत की संप्रभुता का अपमान है और यह विदेश नीति के लिए बड़ा झटका है। प्रधानमंत्री बनने के बाद वे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के खिलाफ पूरी कूटनीति से सख्ती बरत रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी सरकार के पिछले पांच साल में ही विभिन्न देशों से कुल 23 भगोड़ों और अपराधियों को सफलतापूर्वक प्रत्यर्पित कराया गया है। इस बात का खुलासा केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में किया था कि पिछले 2019 से 2024 तक के पांच वर्ष के दौरान आतंकवादी गतिविधियों में शामिल अपराधियों सहित विभिन्न भगोड़ों के प्रत्यर्पण के लिए 178 अनुरोध किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप 23 भगोड़ों को प्रत्यर्पित कराया गया है। विदेश मंत्रालय से प्राप्त रिकॉर्ड के अनुसार, भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए भारत की ओर से 65 अनुरोध अमेरिका को भेजे गए हैं, जो वहां विचाराधीन हैं। विदेश मंत्रालय प्रत्यर्पण मामलों के लिए नोडल प्राधिकरण है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए कूटनीतिक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, सरकार की नीति अधिक से अधिक देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियां करने की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भगोड़े अपराधी बच न सकें। भारत ने जिन देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं, उनमें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड आदि शामिल हैं। इसने एक दर्जन देशों के साथ प्रत्यर्पण व्यवस्था भी की है, जिसमें एंटीगुआ और बारबुडा, इटली, पेरू, श्रीलंका, सिंगापुर, स्वीडन और तंजानिया आदि शामिल हैं।

पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी बेल्जियम में गिरफ्तार

पंजाब नेशनल बैंक से लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को पुलिस ने बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारतीय जांच एजेंसियों के प्रत्यर्पण की अपील पर 12 अप्रैल को उसकी गिरफ्तारी हुई, फिलहाल वह जेल में है। भारत ने बेल्जियम के साथ चोकसी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस ने चोकसी को गिरफ्तार करते समय दो गिरफ्तारी वारंट का हवाला दिया। ये मुंबई की एक अदालत ने जारी किए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि वारंट 23 मई 2018 और 15 जून 2021 के थे। ऐसा माना जा रहा है कि चोकसी अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए जमानत और तत्काल रिहाई की मांग कर सकता है। बेल्जियम में गिरफ्तारी के बाद मेहुल चोकसी ने अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए कोर्ट में जमानत मांगी है। उसकी ओर से कहा गया है कि इलाज कराने के लिए बेल्जियम आया था और अपनी पत्नी के साथ एंटवर्प में रह रहा था। चोकसी पर 13,850 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। पिछले महीने खुलासा हुआ था कि मेहुल चोकसी बेल्जियम में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेहुल पत्नी प्रीति चोकसी के साथ रह रहा है, जिन्हें बेल्जियम की नागरिकता मिली है। बेल्जियम के विदेश मंत्रालय ने ही चोकसी की मौजूदगी की जानकारी दी थी। सूत्रों के मुताबिक, मेहुल चोकसी बेल्जियम से स्विट्जरलैंड भागने की कोशिश कर रहा था। चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि उनका मुवक्किल जमानत के लिए अपील दायर करेगा।

छोटा राजन को इंडोनेशिया से प्रत्यर्पण कर लाया गया था

अंतर्राष्ट्रीय अपराधी छोटा राजन कभी दाऊद इब्राहिम का जिगरी दोस्त रहा था। एक समय बाद दाऊद इब्राहिम की तरह ही खुद कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया था। छोटा राजन पर भारत में कई मुकदमे दर्ज थे। जिनमें मर्डर से लेकर किडनैपिंग तक जैसे खूंखार अपराध शामिल थे। साल 2015 में सीबीआई की टीम ने इंडोनेशिया में छोटा राजन को गिरफ्तार किया। बता दें छोटा राजन पर इंटरपोल की ओर से रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। इंडोनेशिया में गिरफ्तारी के बाद छोटा राजन को प्रत्यर्पण करके भारत लाया गया था। इसके अलावा 2018 में क्रिश्चियन मिशेल यूएई से प्रत्यर्पण करके और 2020 में रवि पुजारी सेनेगल से प्रत्यर्पण करके लाया गया था। ये तीनों अपराधी अब भारतीय जेलों में बंद हैं। इसके अलावा बात की जाए तो विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक साल 2015 तक भारत में कुल 60 अपराधियों को प्रत्यर्पण करके लाया जा चुका है। इनमें यूएई, नाइजीरिया, यूएसए, हांगकांग, कनाडा, जर्मनी,

बुल्गारिया, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, थाईलैंड, बेल्जियम, मॉरीशस, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, मोरक्को, इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे देशों से अपराधियों को लाया गया है। पिछले 16 वर्षों में प्रत्यर्पण के मामलों को देखें तो पता चलता है कि सरकार इस दौरान सिर्फ 66 भगोड़ों को भारत लाई है। जबकि 100 से ज्यादा के प्रत्यर्पण के लिए अर्जी दी है। इनमें से 13 आर्थिक मामलों में अपराधी थे।

17 भगोड़ों के प्रत्यर्पण का प्रयास

ब्रिटेन से 17 लोगों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही थी। इनमें विजय माल्या, ललित मोदी, गुलशन कुमार हत्याकांड में आरोपी और संगीतकार नदीम सैफी, गुजरात में 1993 में हुए धमाकों का आरोपी टाइगर हनीफ भी शामिल हैं। इनके अलावा सरकार को 24 देशों से करीब 121 भगोड़ों को प्रत्यर्पण कर भारत लाने का इंतजार है। भारत और ब्रिटेन के बीच 1993 में प्रत्यर्पण संधि हुई थी। तब से लेकर अब तक पहले आरोपी को भारत लाने में 23 साल लग गए। वह भी मोदी सरकार के कार्यकाल में ही हो पाया। इसके तहत मर्डर के मामले में समीरभाई वीनूभाई पटेल का 19 अक्टूबर 2016 को प्रत्यर्पण किया जा सका है। सरकार अपराध कर भागने वाले तीन ब्रिटिश नागरिकों को भी भारत लाई है, लेकिन इन्हें अमेरिका और तंजानिया से लाया गया। अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले में आरोपी बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को यूएई से लाया गया।

विजय माल्या– 9 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन डिफॉल्ट मामले में भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को वापस लाने के लिए भी सरकार तेजी से काम कर रही है। 2016 में भारत छोड़कर भागा माल्या फिलहाल ब्रिटेन में है। किंगफिशर एयरलाइंस के बंद होने के बाद धोखाधड़ी के मामले में माल्या वांटेड है। माल्या को 2019 में भगोड़ा घोषित किया गया था। भारत माल्या की हिरासत के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, जिसके जल्द खत्म होने की संभावना है। बुधवार (9 अप्रैल) को भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में भारतीय बैंकों के एक संघ ने उनके खिलाफ दिवालियापन आदेश को बरकरार रखने के लिए लंदन में अपनी अदालती अपील जीत ली। 69 वर्षीय व्यवसायी को जुलाई 2021 में दिवालिया घोषित कर दिया गया था। वह ब्रिटेन में फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।

नीरव मोदी– हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी 14,000 करोड़ रुपए के पीएनबी लोन धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी हैं। भारत में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करने के लिए प्रत्यर्पण की लड़ाई हारने के बाद नीरव मोदी लगभग छह साल से लंदन की जेल में है। भारत में उसके खिलाफ तीन तरह की आपराधिक कार्यवाही चल रही है। उसे 19 मार्च, 2019 को प्रत्यर्पण वारंट पर गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त तत्कालीन ब्रिटिश गृह सचिव प्रीति पटेल ने अप्रैल 2021 में उसके प्रत्यर्पण का आदेश दिया था। तब से उसने मामले में सुप्रीम कोर्ट तक अपनी कानूनी अपीलें पूरी कर ली हैं। उसने कई जमानत याचिकाएं दायर की हैं। जिनमें से कई मामलों को खारिज कर दिया गया है।

अनमोल बिश्नोई– अनमोल बिश्नोई गुजरात की जेल से खूंखार गैंग चलाने वाला लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। लॉरेंस पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला और राजनेता बाबा सिद्दीकी की हत्याओं सहित कई हाई-प्रोफाइल मामलों में वांटेड है। बिना वैध दस्तावेजों के देश में प्रवेश करने के कारण अनमोल को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, उसे प्रत्यर्पित किए जाने की कवायद चल रही है।

अर्श दल्ला– खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श दल्ला प्रतिबंधित संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स का नेता है। अर्श कनाडा में रहता है और उस पर हत्या, हत्या के प्रयास, जबरन वसूली और आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के 50 से अधिक मामले दर्ज हैं। उसे जनवरी 2004 में आतंकवादी घोषित किया गया था। ये भी कहा जाता है कि अर्श दल्ला पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी आईएसआई के संपर्क में है। पिछले अक्टूबर में एक हमले में घायल होने के बाद दल्ला को गिरफ्तार किया गया था। तब से भारत उसे प्रत्यर्पित करने की कोशिश कर रहा है।

अब हर तरफ से एक ही आवाज... तहव्वुर राणा को फांसी दो

मुंबई पर आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों और अन्य लोगों ने तहव्वुर राणा को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। मुंबई हमले के दौरान मौके पर आतंकी कसाब को जिंदा पकड़ने में मुख्य भूमिका निभाने वाले शहीद एएसआई तुकाराम ओम्बले के भाई एकनाथ ओम्बले ने कहा कि राणा को सार्वजनिक रूप से फांसी की सजा देनी चाहिए। हमले के दौरान पीड़ितों-घायलों की जान बचाने वाले छोटू चाय वाला के नाम से चर्चित मोहम्मद तौफीक ने कहा कि राणा को सुविधाएं और बिरयानी देने की जरूरत नहीं। ऐसे लोगों के लिए अलग कानून बनाकर जल्द से जल्द फांसी दी जाए। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में आतंकी हमले में घायल हुए सदाशिव कालोके ने कहा कि जल्दी मुकदमा चलाकर राणा को फांसी की सजा दी जाए। हमले में हथगोले से अपने पति को खो चुकी और खुद घायल हुईं वाराणसी की सुनीता यादव ने कहा कि हम उस दिन का मंजर आज भी नहीं भूलते। अमेरिका से लाए गए अपराधी को फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए।

न्यायपालिका पर जनता कैसे करे भरोसा?

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास में आग लगने के दौरान मिले अधजले नोटों ने एक बार फिर न्यायपालिका को कठघरे में खड़ा करने का काम किया। इस मामले से न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का प्रश्न फिर से सतह पर आ गया है और वह व्यापक चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके पहले भी कई बार उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों के भ्रष्टाचार के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन विडंबना यह है कि किसी भी मामले की नीर-क्षीर ढंग से जांच नहीं हो सकी और न ही आरोपित न्यायाधीश को महाभियोग के जरिये हटाया जा सका।

आम जनता उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों को इस निगाह से देखती है कि वे संविधान और साथ ही सामान्य जन के अधिकारों के रखवाले हैं। जब-जब न्यायाधीशों के भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है, तब-तब आम जनता का न्यायपालिका पर से भरोसा डिगता है। समय के साथ यह धारणा आम होती जा रही है कि न्यायपालिका अपना काम सही तरह नहीं कर रही है। अदालतों से जिन लोगों का वास्ता पड़ता है, उनमें तो यह धारणा कहीं अधिक प्रबल है, क्योंकि उन्हें समय पर न्याय नहीं मिलता। निचली अदालतों की दयनीय दशा से आम लोग कहीं अधिक अवगत हैं, जहां तारीख पर तारीख का सिलसिला कायम रहता है और लंबित मामलों की संख्या करोड़ों में है। उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय के हालात भी उन लोगों से छिपे नहीं, जिनके मामले वहां चल रहे हैं। चूंकि जनता का एक छोटा प्रतिशत ही न्याय पाने के लिए उच्चतर न्यायपालिका के दरवाजे पहुंचता है, लिहाजा शेष जनता यह मानकर चलती है कि नेताओं और नौकरशाहों के मुकाबले उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीश उसकी समस्याओं का समाधान करने में कहीं अधिक तत्पर हैं, पर अब ऐसा कहना कठिन होता जा रहा है। जस्टिस वर्मा के मामले के बाद ऐसा कहना और कठिन होगा। उच्चतम न्यायालय ने जस्टिस वर्मा के मामले की जांच के लिए तीन न्यायाधीशों की एक समिति गठित कर दी है। वह यह पता लगा रही है कि जस्टिस वर्मा के घर मिले अधजले नोट किसके थे और कहां से आए? इसकी जांच इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि जस्टिस वर्मा कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि अधजले नोट किसके हैं और कहां से आए? वे खुद को फंसाए जाने की साजिश की ओर संकेत करते हुए यह भी कह रहे हैं कि उनके आवास के जिस आउटहाउस में आग लगी, वहां उनका या उनके परिवार के सदस्यों का आना-जाना नहीं था। उनका यह भी कहना है कि आउटहाउस में आग लगने के दौरान नोट जले, इसकी जानकारी उन्हें नहीं दी गई। पता नहीं सच क्या है, लेकिन इस मामले की जांच रपट शीघ्र सामने आनी चाहिए, अन्यथा पहले के मामलों की तरह यह भी लोगों की स्मृति से ओझल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया है और फिलहाल उनके मामले में एफआईआर दर्ज करने की जरूरत से इनकार कर दिया है। कॉलेजियम की ओर से जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजे जाने के फैसले को लेकर कई सवाल उठे हैं।

नैतिकता का तकाजा यह कहता था कि मामले की जांच होने तक जस्टिस वर्मा को छुट्टी पर भेजा जाता। इसके बजाय उन्हें वापस उनके पैतृक हाईकोर्ट भेजा गया। हालांकि उन्हें कोई न्यायिक काम नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कॉलेजियम के फैसले से इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन समेत अन्य उच्च न्यायालयों की बार एसोसिएशन सहमत नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने तो जस्टिस वर्मा के शपथग्रहण समारोह का बहिष्कार करने की घोषणा भी कर दी है। वैसे यह भी एक तथ्य है कि कई बार न्यायाधीश एवं वकील मिलकर ही ऐसे काम करते हैं, जिनसे तारीख पर तारीख का सिलसिला कायम होता है अथवा न्याय नहीं मिलता। जस्टिस वर्मा के आवास में **अधजले नोट** मिलने के मामले में इस पर आश्चर्य होता है कि आखिर पुलिस ने इस गंभीर प्रकरण की जांच तत्काल क्यों नहीं शुरू की? इसके साथ ही सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियां क्यों नहीं सक्रिय हुईं? क्या कारण रहा कि नोट जलने की घटना की भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई? यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि यदि ऐसे ही अधजले नोट किसी कारोबारी, नौकरशाह अथवा अन्य किसी के यहां मिलते तो क्या वैसा ही होता, जैसा जस्टिस वर्मा को लेकर हुआ? क्या तब भी पुलिस और न्यायपालिका इसी तरह व्यवहार करती?

न्यायपालिका की स्थिति किसी से छिपी नहीं। सभी यह स्वीकार करते हैं कि लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल रहा है, पर ऐसी व्यवस्था नहीं की जा पा रही है कि जिससे न्याय मिलना सुगम हो सके। इसका एक कारण यह है कि सरकार यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच इस पर सामंजस्य नहीं बन पा रहा है कि लोगों को समय पर न्याय मिलना कैसे सुनिश्चित किया जाए? यदि सरकार कुछ करती है तो उसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता में दखल मान लिया जाता है और न्याय में देरी का ठीकरा भी उस पर फोड़ दिया जाता है।

● **रजनीकांत पारे**

कॉलेजियम व्यवस्था में खामियां

एक विडंबना यह है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति वाली कॉलेजियम व्यवस्था में खामियों को तो मानता है, पर उसे बदलने के लिए तैयार नहीं। उसने कॉलेजियम व्यवस्था की जगह लाई गई वैकल्पिक व्यवस्था को असंवैधानिक बताकर खारिज कर दिया था। न्याय में देरी के लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका की ओर से एक-दूसरे पर ठीकरा फोड़ने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और उलटे आम जनता का नुकसान हो रहा है। आज जब यह कहा जा रहा है कि भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा, तब इसे अनदेखा नहीं कर सकते कि विकसित राष्ट्र बनने में एक बड़ा रोड़ा न्याय में देरी है। न्याय में देरी के जो तमाम कारण हैं, उनमें एक न्यायपालिका का भ्रष्टाचार भी है। बेहतर होगा कि न्यायपालिका अपने तंत्र में आमूल-चूल परिवर्तन की रूपरेखा तैयार करे और उसे लेकर सरकार के साथ विचार-विमर्श करे, अन्यथा न तो उसकी साख बढ़ने वाली है और न ही लोगों को समय पर न्याय मिलने वाला है।

क्या राहुल बदल पाएंगे कांग्रेस...?

करीब 6 दशक बाद अहमदाबाद में कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ। कहा जा रहा है कि कांग्रेस को बदलने के लिए राहुल गांधी ने इस अधिवेशन में नई रणनीति बनाई है।

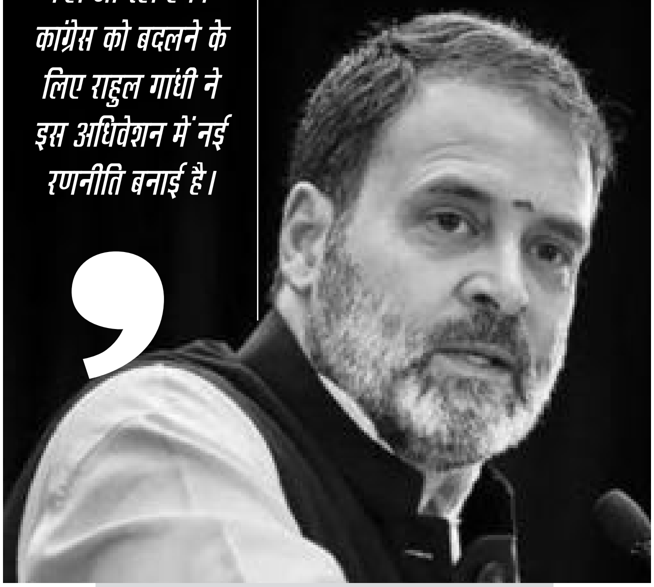

भाजपा से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने खाका तैयार कर लिया है। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी सीडब्ल्यूसी की बैठक में पार्टी के भविष्य की दिशा तय कर ली गई है। कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करने और भाजपा के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने के साथ-साथ सामाजिक न्याय से लेकर सामाजिक सद्भावना और राष्ट्रवाद के एजेंडा पर आगे बढ़ने की प्लानिंग की है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस को बदल पाएंगे। राहुल गांधी कई बार अच्छी बातें कह जाते हैं पर उनको अमली जामा पहनाने में चूक जाते है। अभी पिछले महीने ही कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुजरात के अहमदाबाद में अपने निकाय स्तर से नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस पूरे भाषण में राहुल गांधी ने खुलकर अपनी बात कही। असल में राहुल गांधी ने वह बात खुलकर कही है जो कांग्रेस का बड़ा नेता कभी नहीं कह पाया। चाहे वह जवाहरलाल नेहरू हों या इंदिरा गांधी या फिर राजीव गांधी ही क्यों न रहे हों। कांग्रेस का जब से गठन हुआ उसमें पौराणिकवाद को मानने वालों की बड़ी संख्या रही है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉ. राजेंद्र कुमार जैसे नेता पौराणिकवाद की सोच के थे।

देश के आजाद होने के बाद जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो कई ऐसे मसले आए जहां जवाहरलाल नेहरू के विचार इन कांग्रेस के नेताओं से नहीं मिलते थे। खासतौर पर धर्म को लेकर जैसे राममंदिर का मसला था। जब अयोध्या के राममंदिर में मूर्तियां प्रगट होने की घटना हुई तो उप्र के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने प्रधानमंत्री नेहरू की बात मानने से इनकार कर दिया। नेहरू चाहते थे कि मंदिर में रखी गई मूर्तियों को हटाया जाए। कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने इस बात से इंकार कर दिया।

सोमनाथ के मंदिर के जीर्णोधार को लेकर भी नेहरू के विचार अलग थे। वह इस बात से खुश नहीं थे कि राष्ट्रपति राजेंद्र कुमार वहां गए थे। हिंदू विवाह अधिनियम जिसके आधार पर आज सवर्ण महिलाएं आजादी का अनुभव कर रही हैं उसको लागू करते समय नेहरू का विरोध हुआ था। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को पौराणिकवाद की सोच रखने वाले नेताओं के दवाब में तमाम काम करने पड़े। नेहरू, इंदिरा और राजीव का राजनीतिक कद इतना बड़ा था कि पौराणिक सोच वाले नेता प्रभावी नहीं हो पाते थे।

राहुल गांधी ने जब से राजनीति में कदम रखा है कांग्रेस पहले जैसी ताकत में नहीं रही है। 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार थी। जिसकी अगुवा कांग्रेस भले ही थी, लेकिन वह सहयोगी दलों के सहारे सरकार चला रही थी। 2014 से 2025 में कांग्रेस विपक्ष में है और उसकी खराब हालत है। 2014 और 2019 के दो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास नेता विपक्ष बनने लायक भी सांसद नहीं थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को थोड़ी सफलता मिली। राहुल गांधी नेता पतिपक्ष बन गए। इसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार ने पार्टी के मनोबल को तोड़ दिया है।

राहुल गांधी कितना भी कहें कि उन पर चुनावी हार-जीत का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन राजनीतिक दल होने के नाते कांग्रेस को हर चुनाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे में राहुल गांधी चाहे या न चाहे उनके हर कदम हर फैसले को चुनावी कसौटी से गुजरना ही पड़ेगा। गुजरात में राहुल गांधी ने जो कहा वह अपनी पार्टी के बीच कहने में नेता संकोच करते हैं। राहुल गांधी यह कहने का साहस कर सके इससे पार्टी कार्यकर्ता बेहद खुश हैं। गुजरात में 2 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता खुश हैं, उनको लग रहा है कि अब पार्टी में बदलाव होगा।

कांग्रेस नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने कहा है कि राहुल गांधी को ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए। ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, पार्टी में आरामदायक पोजिशन पर बैठे हैं वो लोग नहीं चाहते कि नए लोग, नए चेहरे आगे आएं। अंदर से भी महसूस होता है कि हमें रोका जा रहा है। राहुल गांधी पार्टी के भीतर ऐसे लोगों की पहचान करेंगे जो दूसरों को काम करने का मौका नहीं देते। मैं राहुल गांधी से आग्रह करती हूं कि वो पहचानें, कौन ऐसे लोग हैं जो सही लोगों को आपकी पार्टी के साथ जुड़ने नहीं देते हैं, जो ईमानदार लोगों को जुड़ने नहीं देते हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि ऐसे लोगों को पहचानेंगे और कांग्रेस से उनको बाहर करेंगे।

विरोधियों ने बनाया मुद्दा

भाजपा नैरेटिव गढ़ने में माहिर है। वह राहुल गांधी के पूरे बयान से एक लाइन निकालकर उस पर बहस को केंद्रित करने में सफल रही। आज राजनीति विचारधारा से दूर लाभ-हानि को देखकर की जाती है। पहले यह समाजसेवा होती थी अब यह कैरियर है। इसमें पूंजी का निवेश किया जा रहा है। पैसे का प्रभाव तो बढ़ा ही है, पैसे वालो का भी प्रभाव बढ़ गया है। यह पूरी दुनिया में हो रहा है। भारत में नरेंद्र मोदी के पीछे अडानी और अंबानी की ताकत है तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के पीछे एलन मस्क जैसे पैसे वाले लोग हैं। नेताओं को अब सत्ता चाहिए। सत्ता के लिए वह पार्टी और विचारधारा को दरकिनार करने में नहीं चूकते हैं। राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जो चुनावी नफा-नुकसान नहीं देखते हैं। वह पार्टी की विचारधारा को सबसे ऊपर मानते हैं। वह चाहते हैं कि कांग्रेस सही मायनों में भाजपा का विकल्प बनी रहे। वह खुद को भाजपा या उसके नेताओं की आलोचना तक सीमित नहीं रखते हैं। वह सावरकर बनाम गांधी और कांग्रेस बनाम संघ की बात करते हैं। विपक्ष के नेता अपनी सीमित सोच तक केवल भाजपा का विरोध ही कर पा रहे हैं। अब यह देखना है कि राहुल गांधी ने जो कहा उस हिसाब से वह कितना काम करते हैं। इसके लिए कांग्रेस कितनी तैयार है।

कहां चूक रहे हैं राहुल गांधी?

राहुल गांधी सोचते तो बहुत अच्छा हैं। उस दिशा पर वह काम भी करते हैं। इसके बाद भी उनकी दिशा में भटकाव है। कभी वह सनातनी बन मंदिर-मंदिर भटकने लगते हैं। अपना जनेउ दिखाने और गौत्र बताने लगते हैं। कभी पूरी तरह से वामपंथी बन जाते हैं। इसके बाद वह महाकुंभ और राममंदिर भी नहीं जाते हैं। राहुल गांधी को एक रास्ता तय करना होगा। राजनीति दो धाराओं के बीच फंसी है- एक तरफ धर्म ग्रंथ है तो दूसरी तरफ संविधान। 2024 के चुनाव में राहुल गांधी ने संविधान का हाथ पकड़ा तो उनको सफलता भी मिली। वह भाजपा को 400 पार से रोकने में सफल रहे। संसद भवन में फिर वह शंकर की फोटो लहराने लगे। एससी, ओबीसी और महिलाएं राहुल गांधी के बेहद करीब खुद हो पाते हैं। वह लोग राहुल गांधी की सबसे बड़ी ताकत हैं। राहुल गांधी के पास वोट है पर नेता नहीं हैं। 12-15 सालों में कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर चले गए। राहुल गांधी इन्हीं के बारे में कह रहे थे। राहुल गांधी को एससी, ओबीसी और महिलाओं को समझाना पड़ेगा कि उनको जो मिल रहा है वह केवल संविधान के कारण ही मिल रहा है। राहुल इनके लिए कुछ करना चाहते हैं। भाजपा इनको आगे दिखा तो सकती है लेकिन असल ताकत वह अपने हाथ में ही रखेंगे। पौराणिकवाद में फंसकर कांग्रेसियों का विचार भाजपाई होता जा रहा है। गुजरात कांग्रेस के नेता इस पर कितना खरे उतरते हैं यह देखने वाली बात है। राहुल गांधी ने जो कहा है उसे करके दिखाना पड़ेगा।

राहुल गांधी गुजरात के अहमदाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं और निकाय चुनाव के पूर्व उम्मीदवारों की एक सभा को संबोधित कर रहे थे। राहुल गांधी ने गुजरात में कहा कि यहां कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए। गुजरात में कांग्रेस का नेतृत्व बंटा हुआ है और वो गुजरात को रास्ता दिखा नहीं पा रहा। यहां के नेतृत्व में दो तरह के लोग हैं, कुछ वो हैं जो जनता के साथ खड़े हैं और जिनके दिल में कांग्रेस की विचारधारा है और दूसरे वो हैं जो जनता से कटे हुए हैं और इसमें से आधे भाजपा से मिले हुए हैं। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है और बारात के घोड़े को रेस में भेज देती है। पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है लेकिन वे बंधे हुए हैं। अगर सख्त कार्रवाई करनी पड़े और 30 से 40 लोगों को निकालना पड़े तो, निकाल देना चाहिए। कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सीधे जनता से जुड़ना पड़ेगा, तभी जनता उन पर यकीन करेगी।

राहुल कहते हैं कि गुजरात में 30 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकी है, इस बार उनका इरादा इस स्थिति को बदलने का है। यहां विपक्ष के पास 40 फीसदी वोट हैं यहां विपक्ष छोटा नहीं है। अगर गुजरात के किसी भी कोने में दो लोगों को आप खड़ा कर देंगे तो उसमें से एक भाजपा का और दूसरा कांग्रेस का निकलेगा। यानी दो में से एक हमारा, एक उनका होगा। लेकिन हमारे मन में है कि कांग्रेस के पास दम नहीं है। अगर गुजरात में हमारा वोट पांच फीसदी बढ़ जाएगा तो भाजपा वहीं खत्म हो जाएगी। तेलंगाना में हमने 22 फीसदी वोट बढ़ाया है, यहां तो सिर्फ 5 फीसदी की जरूरत है।

वे आगे कहते हैं, गुजरात की जनता को पार्टी नेतृत्व नया विकल्प नहीं दे पा रही है। कांग्रेस को उसका ओरिजिनल नेतृत्व गुजरात ने दिया है और उस नेतृत्व ने हमें सोचने का तरीका, लड़ने का तरीका और जीने तरीका दिया। गुजरात नया विकल्प चाह रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसे दिशा नहीं दिखा पा रही है। चाहे हमारे जनरल सेक्रेटरी हों, चाहे हमारे पीसीसी अध्यक्ष हों, कांग्रेस पार्टी जनता को दिशा नहीं दिखा पा रही है। यह सच्चाई है, और इसे कहने में मुझे कोई शर्म या डर नहीं है। गुजरात के नेतृत्व में दो तरह के लोग हैं, इसमें बंटवारा है। एक तरह के लोग हैं जो जनता के साथ खड़े हैं और जिनके दिल में कांग्रेस की विचारधारा है। और दूसरे वो हैं जो जनता से कटे हुए हैं, इनमें से आधे भाजपा से मिले हुए हैं।

कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, सीनियर लेवल नेता हैं, बब्बर शेर हैं। मगर पीछे से चेन लगी हुई है और बब्बर शेर बंधे हुए हैं सब। एक बार मेरी मीटिंग हो रही थी। शायद मप्र का डेलिगेशन था एक। वहां पर एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ और कहा कि राहुलजी आप एक काम कर दीजिए। उसने कहा दो तरह के घोड़े होते हैं। एक होता है रेस का और एक होता है शादी का। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। अब गुजरात की जनता देख रही है। कह रही है कि भैया कांग्रेस पार्टी ने रेस में बारात का घोड़ा डाल दिया। अगर हमें रिश्ता बनाना है तो हमें दो काम करने हैं। पहला काम, जो दो ग्रुप हैं हमें उन्हें अलग करना पड़ेगा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़े और 30 से 40 लोगों को निकालना पड़े, तो निकाल देना चाहिए। भाजपा के लिए अंदर से जो लोग काम कर रहे हैं, बाहर से काम करने दीजिए। जीतने-हारने की बात छोड़ दीजिए, जो हमारे नेता हैं, अगर उनका हाथ कटे तो उसमें से कांग्रेस का खून निकलना चाहिए। ऐसे लोगों के हाथ में संगठन का कंट्रोल होना चाहिए। जैसे ही हम यह करेंगे जनता हमसे जुड़ेगी और हमें उनके लिए दरवाजे खोलने होंगे। कांग्रेस की उसी विचारधारा पर लौटना होगा, जो गुजरात की विचारधारा है। वही विचारधारा जो गुजरात की जनता, महात्मा गांधीजी और सरदार पटेल ने कांग्रेस को सिखाई है।

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं, भाजपा से लड़ना है तो बिना समझौते के लड़ना है। राहुल गांधी विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने पूरी मुस्तैदी से कहा है कि अगर हमें भाजपा से लड़ना है तो बिना संशय के लड़ना है, बिना समझौते के लड़ना है, जिस निडरता से वो लड़ते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप के मन में जरा सा भी संशय है या भय है तो आप इस लड़ाई में उनके सिपाहसालार नहीं हो सकते। वो सही कह रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत कहते हैं कि राहुल गांधी ने कभी सत्ता की राजनीति नहीं की। वह विचारधारा की राजनीति करते हैं। कट्टरवाद के खिलाफ जो काम वह कर रहे हैं उसे दूसरा नेता नहीं कर सकता। इस वजह से भाजपा ही नहीं संघ भी राहुल गांधी से डरता है। भाजपा को कोई सत्ता से हटा सकता है तो वह केवल कांग्रेस ही है। राहुल से डरकर ही भाजपा उनके खिलाफ नैरेटिव चलाती है।

● **विपिन कंधारी**

विकास की लड़ाई

प्रधानमंत्री मोदी का दृष्टिकोण जिला स्तर पर विकसित भारत के निर्माण की संकल्पना को बल देने का आधार बनेगा। इस कार्य में तेजी लाने की जरूरत है क्योंकि अगले 20 वर्षों में हमारी जनसंख्या की संरचना भी बदलने लगेगी और भारत की आबादी में वृद्धों की संख्या ज्यादा होने लगेगी। यही सबसे सुनहरा और अंतिम अवसर है जब हम एक विकसित राष्ट्र के निर्माण में जुट जाएं।

प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में छोटे जिले आदर्श केंद्र बिंदु बन सकते हैं। जैसे-जैसे हमारा देश सामाजिक, आर्थिक, जनसांख्यिकीय और राजनीतिक रूप से विकसित और परिवर्तित हो रहा है, हमारे टियर-2 और टियर-3 जिले इस परिवर्तन के केंद्र में आ रहे हैं। इन्हीं 240 जिलों में भारत की अधिकांश आबादी यानी 80 करोड़ लोगों का घर है। यह आबादी न तो बहुत अमीर है और न ही बहुत गरीब। इस वर्ग को मिडिल ऑफ द डायमंड इंडिया कहा जा सकता है।

बतौर उदाहरण उप्र में लोकसभा क्षेत्र देवरिया में 20 लाख मतदाता और 28 लाख नागरिक हैं, जो जार्डन जैसे देश से भी बड़ी आबादी है। यह संसदीय सीट 2,500 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, जो एनसीआर क्षेत्र से भी बड़ी है, लेकिन चुनावों के बाद अक्सर टियर-3 जिले हाशिये पर धकेल दिए जाते हैं। विकसित भारत का सपना तभी पूरा हो सकता है जब विकास की लड़ाई इन्हीं जिलों से लड़ी जाए।

देवरिया संसदीय क्षेत्र की जीडीपी पिछले दशक में लगभग छह प्रतिशत की दर से बढ़ी है। अब यह 17,000 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। अगर यही दर बनी रही तो वर्ष 2035 तक यह 30,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी, लेकिन विकसित देवरिया के संकल्प को प्राप्त करने के लिए इससे अधिक तेज वृद्धि दर की जरूरत है। इसके लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए स्थानीय रोजगार का सृजन करना होगा, मानवीय संसाधनों को पूरी क्षमता से विकसित करना होगा।

यह महत्वाकांक्षी आर्थिक बदलाव नागरिकों, निजी क्षेत्र और सरकार के संयुक्त प्रयास से ही संभव होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत और जल जीवन मिशन जैसे अभियानों को सफलतापूर्वक लागू किया है। चूंकि इन 240 जिलों में उभरता हुआ मध्यम वर्ग बसता है, इसलिए तेज और समान विकास सक्षम सरकार और लोकतांत्रिक प्रयासों के जरिये संभव है। सबका प्रयास का यह दृष्टिकोण कांग्रेस सरकारों के समाजवादी मॉडल से अलग है।

पिछली सरकारों में जिलों के विकास के लिए पूरी तरह से सरकार पर निर्भरता थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार की भूमिका अहम होती है। प्रधानमंत्री मोदी के सबका प्रयास का मंत्र इन छोटे जिलों के लिए सबसे अहम है। अगर हम इनकी विकास दर को 9 प्रतिशत तक ले जाना चाहते हैं, तो हमें कृषि, कम कुशलता वाले निर्माण उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, शहरीकरण, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल नेटवर्क में निवेश करना होगा। ऐसा विकास नागरिकों को उपभोक्ता के रूप में नहीं, बल्कि निर्माता के रूप में भी देखता है। स्थानीय संस्कृति, प्रेरक कहानियों, आदर्श व्यक्तित्व और हमारे इतिहास की विरासत से विकास की इस मुहिम को गति मिलेगी।

पूर्वांचल 1857 की क्रांति का केंद्र था। तब मंगल पांडे ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया और एक साल बाद रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजों का सामना किया और वीरगति को प्राप्त हुईं। पूर्वांचल से उठी इस क्रांति के कारण इस क्षेत्र को अगले 90 वर्षों तक अंग्रेजों ने हाशिये पर डाल दिया और इसे आर्थिक रूप से शोषित करने के लिए विभाजनकारी नीतियां अपनाईं। इसके परिणामस्वरूप पूर्वांचल में अविश्वास और निषेध का माहौल बना। उस समय सेना में भर्ती रोक दी गई, नागरिक और सार्वजनिक सहयोग को संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा। देश में ऐसे और भी अनेक क्षेत्र हैं, जो अंग्रेजों की इसी नीति के शिकार हुए। 1900 में बिरसा मुंडा के विद्रोह के बाद झारखंड, संथाल विद्रोह के बाद बंगाल और कई अन्य क्षेत्र इसी तरह पीछे छूट गए।

स्वतंत्र भारत की कड़वी विडंबना यह है कि जिन क्षेत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम में सबसे अधिक योगदान दिया, वे आज सबसे अधिक पिछड़े हुए हैं और इनमें से अधिकतर उत्तर और पूर्व भारत में स्थित हैं। इसलिए विकसित भारत मिशन को एक क्रांतिकारी क्षेत्र निवेश कार्यक्रम भी बनाना चाहिए, जो इन क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करे। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रस्तुत पूर्वोदय के सपने को साकार कर सकता है। इसी

वैश्विक अर्थव्यवस्था की ग्रोथ में 15 फीसदी रहा भारत का योगदान

दुनिया के अर्थव्यवस्था में भारत की योगदान की चर्चा करें तो अकेला भारत 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की ग्रोथ में 15 फीसदी का योगदान करेगा। साथ ही भारत ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के ग्रोथ रेट के मामले में मोदी सरकार के कार्यकाल में पिछले 9 वर्षों के दौरान पांच बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ा है। वैश्विक स्तर पर जहां सकल घरेलू उत्पाद 3 से 3.5 प्रतिशत के बीच बढ़ रहा है, वहीं भारत में यह सात प्रतिशत से अधिक की गति से आगे बढ़ रहा है। जानकारों का मानना है कि यह आर्थिक विकास दर आगे आने वाले लंबे समय तक बने रहने की भरपूर संभावना है। भाजपा के युवा नेता मनोज यादव का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार विकास कर रही है। इसका प्रमुख कारण प्रधानमंत्री मोदी की विकास केंद्रित नीति के साथ करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। मनोज कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने पीएलआई स्कीम की शुरुआत की, जिसका फायदा उद्योग जगत और अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक तौर पर पड़ा।

तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है।

इसके लिए लोकसभा क्षेत्रों में 10-वर्षीय विकास रणनीति तैयार की गई है। इस तरह जनता को एक नई और सकारात्मक क्रांति के माध्यम से राष्ट्र-निर्माण की ओर प्रेरित किया जा रहा है। यह सबके प्रयास से सबका विकास करना है। प्रधानमंत्री मोदी का यह आह्वान राजनीतिक दृष्टिकोण से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को आगे बढ़ाता है, जो हर वर्ग, जाति या पंथ की सीमाओं को तोड़कर सभी को एकजुट करता है। यह पूरी तरह से विपक्ष की जातिगत जनगणना की राजनीति से भिन्न है, जो समाज को बांटने के लिए एक नए हथियार के रूप में प्रयोग कर रहा है। यह नया दृष्टिकोण 'खटाखट' की राजनीति का मुकाबला करेगा, देश की आर्थिकी को मजबूत करेगा और आत्मनिर्भर नागरिकों का निर्माण करेगा। यह दृष्टिकोण जिला स्तर पर विकसित भारत के निर्माण की संकल्पना को बल देने का आधार बनेगा। इस कार्य में तेजी लाने की जरूरत है, क्योंकि अगले 20 वर्षों में हमारी जनसंख्या की संरचना भी बदलने लगेगी और भारत की आबादी में वृद्धों की संख्या ज्यादा होने लगेगी। यही सबसे सुनहरा और अंतिम अवसर है, जब हम एक विकसित राष्ट्र के निर्माण में जुट जाएं।

विश्व बैंक ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार आगे भी बनी रहेगी। विश्व बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि अगले वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की विकास दर 6.7 प्रतिशत रहेगी। विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स में चालू वित्त वर्ष 2024-25 की विकास दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्विस सेक्टर में वृद्धि, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में इसे मजबूती मिलेगी। विश्व बैंक ने यह भी कहा है कि अमेरिका, चीन को पीछे छोड़ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। विश्व बैंक के अनुसार चीन की विकास दर चालू वित्त वर्ष में 4.5 प्रतिशत से घटकर अगले साल 4 प्रतिशत रह जाएगी। जबकि अमेरिका की विकास दर इस साल की 2.3 प्रतिशत से घटकर अगले वर्ष 2 प्रतिशत रहेगी। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा है कि भारत 2026 तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उद्योग मंडल पीएचडीसीसीआई ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मौजूदा वित्त वर्ष में 6.8 प्रतिशत और अगले वित्त वर्ष में 7.7 प्रतिशत की रफ्तार से आगे बढ़ सकती है। पीएचडीसीसीआई के अध्यक्ष हेमंत जैन ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती से प्रगति की है और 2026 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पीएचडीसीसीआई ने यह भी कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में देश की जीडीपी 6.8 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ी है।

मोदी सरकार पर अपना भरोसा और मजबूत करते हुए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने साफ कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी सात प्रतिशत की ही रफ्तार से आगे बढ़ेगी। एडीबी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी की वृद्धि के अनुमान में कोई बदलाव न करते हुए इसे 7 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। एडीबी ने यह भी कहा कि भारत की राजकोषीय स्थिति उम्मीद से ज्यादा मजबूत रहने के कारण वृद्धि को बल मिल सकता है। एडीबी ने कहा है कि सामान्य से बेहतर मानसून के कारण कृषि क्षेत्र में सुधार की उम्मीद है। इसके साथ ही भारत के औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि दर तेज बने रहने का अनुमान है और इसे आवास क्षेत्र के नेतृत्व में निर्माण क्षेत्र की जोरदार मांग से बल मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में एक रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जो अनुमान व्यक्त किया, उसके मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था, जो अभी लगभग 3.75 ट्रिलियन डॉलर की है, वित्त वर्ष 2027-28 तक 5 ट्रिलियन डॉलर को पार कर जाएगी। भारत 5.2 ट्रिलियन डॉलर के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसकी वैश्विक अर्थव्यवस्था में 4 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। इस दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था 31 ट्रिलियन डॉलर के साथ शीर्ष पर रहेगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसकी हिस्सेदारी 24 प्रतिशत होगी। इसके बाद चीन 25.7 ट्रिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर रहेगा और वैश्विक जीडीपी में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।

भारत आने वाले समय में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। आईएमएफ के अनुमान के अनुसार रूस-यूक्रेन संकट, कोरोना महामारी और महंगाई जैसी चुनौतियों के बाद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहेगी। आईएमएफ ने कहा है कि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में भारत की हिस्सेदारी 2028 तक फ्रांस और ब्रिटेन को पार कर जाने की उम्मीद है। इससे भारत वैश्विक आर्थिक विकास को चलाने में एक प्रमुख देश बन जाएगा। आईएमएफ का कहना कि भारत की अगुवाई में दक्षिण एशिया वैश्विक वृद्धि का केंद्र बनने की दिशा में बढ़ रहा है और 2040 तक वृद्धि में इसका अकेले एक-तिहाई योगदान हो सकता है। आईएमएफ के हालिया शोध दस्तावेज में कहा गया कि बुनियादी ढांचे में सुधार और युवा कार्यबल का सफलतापूर्वक लाभ उठाकर यह 2040 तक वैश्विक वृद्धि में एक तिहाई योगदान दे सकता है।

● इन्द्र कुमार

क्षेत्रीय संकीर्णता की राजनीति

श्रीलंका की यात्रा से लौटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रामनवमीं के अवसर पर रामेश्वरम द्वीप को तमिलनाडु की मुख्य भूमि और रेलवे नेटवर्क से जोड़ने वाले पंबन पुल का उद्घाटन राज्य के साथ ही देश को मिलने वाली एक सौगात है। अपनी तरह के इस अनोखे समुद्री पुल का निर्माण तमिलनाडु के लिए बड़ी उपलब्धि और गर्व का विषय है। यह देखना दुखद रहा कि इस अवसर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करना आवश्यक नहीं समझा। यह ठीक है कि राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर उनके एक मंत्री उपस्थित थे, लेकिन कोई भी समझ सकता है कि उन्होंने संकीर्ण राजनीतिक कारणों से ही इस कार्यक्रम से दूरी बनाई। यह और कुछ नहीं, सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार का उल्लंघन ही है। स्टालिन ने केवल प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में अनुपस्थित रहना ही उचित नहीं समझा, बल्कि उन्होंने इस मौके पर परिसीमन का अपना पुराना राग भी फिर से छेड़ा।

नक्सलवाद के खात्मे का काउंटडाउन

छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के सफाए को लेकर जिस तरीके की चर्चा और निर्णय पिछले एक सप्ताह में हुए हैं वो 2026 तक नक्सलियों के खात्मे के लिए चलाए जा रहे अभियान में बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा बना है। 8 अप्रैल से लेकर अब तक देश में नक्सलियों के खिलाफ चल रही मुहिम को और मजबूत करने का बल मिला है। बात चाहे सुप्रीम कोर्ट की हो या फिर केंद्र सरकार के दावों की या फिर राज्य में चल रहे ग्राउंड जीरो पर नक्सलियों से निपटने के अभियान की, पूरा देश अब नक्सल मुक्त भारत की कल्पना को साकार करने में जुट गया है। इसमें सिर्फ बंदूक ही नहीं पुनर्वास की सिफारिश भी है। शांति के प्रयास के लिए चल रहे ग्राउंड जीरो पर होने वाले काम को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का भी। जो अपने आप में बताती है कि देश नक्सली के नासूर से बाहर निकालने के लिए कृत संकल्पित हो चुका है।

छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल अभियान और उसको लेकर राजनीतिक रोटी सेकने की कवायत में कुछ लोग कोर्ट में सहानुभूति की प्रक्रिया लेकर पहुंच जाते हैं। जिसमें सुरक्षा एजेंसियों पर कई आरोप भी लगा दिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सलियों के खिलाफ अभियान में 2018 में सुकमा में सुरक्षा बलों के साथ हुए एनकाउंटर में जो लोग मारे गए थे उसको लेकर एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। 9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में इस पीआईएल पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच जिसे जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की अदालत में सुना गया। इसमें सुनवाई के दौरान आरोप लगाया गया था कि सुरक्षा बल ने एनकाउंटर में 15 आदिवासियों की हत्या की है जिस पर मुकदमा चलाया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने यह पक्ष रखा कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वह निराधार हैं। सुरक्षा एजेंसियों के साथ जो लोग मुठभेड़ में मारे गए हैं वह सभी ईनामी नक्सली थे। जो भी दावा किया गया है वह झूठा है।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में शांति बहाली की प्रक्रिया चल रही है। लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ऐसे में शांति के लिए चल रही प्रक्रिया में हम अनावश्यक रूप से दखल नहीं देंगे। इस तरह के मुकदमे शांति व्यवस्था के लिए चलाई जा रही प्रक्रिया में बाधा पैदा करते हैं। इलाके में शांति आ रही है ऐसे में इस तरह की अनावश्यक रूप से चीजों को करने का कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल खारिज कर दी। मामला साफ है नक्सल के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में अब वैसे लोगों को भी बहुत राहत नहीं मिलने जा रही है जो राजनीतिक या फिर अपने फायदे की रोटी सेकते थे।

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि देश से हर हाल में नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चल नहीं सरकार ने नक्सलियों के खात्मे की समय सीमा तय कर दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग समाज की मुख्यधारा से भटक गए हैं हम उनसे यह निवेदन कर रहे हैं कि वह समाज की मुख्यधारा से जुड़ें। देश के विकास में अपनी महिती भूमिका अदा करें। क्योंकि बंदूक से किसी देश या समाज का विकास नहीं होता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ बंदूक ही नक्सल समस्या का समाधान नहीं है। पूरे देश में नक्सलियों के पुनर्वास की नीति भी चलाई जा रही है। राज्य सरकारें उस पर काम भी कर रही हैं। हम समाज की मुख्यधारा से भटके हुए लोगों से अपील कर रहे हैं कि देश की मुख्यधारा में शामिल होकर देश का विकास करें। लेकिन यह भी तय है जो लोग बंदूक नहीं छोड़ेंगे उनको बंदूक से ही जवाब दिया जाएगा। लेकिन नक्सलवाद से किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा।

11 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि जो नक्सली सरकार से बातचीत करना चाहते हैं उनके लिए सीधी और सटीक बात ये है कि सबसे पहले बंदूक छोड़कर आत्मसमर्पण करें। उसके बाद हम उनसे बात करने को तैयार हैं। देश और समाज के विकास में उनके जो भी सुझाव होंगे हम उसे हर हाल में स्वीकार करेंगे। वास्तव में नक्सली संगठन ने एक पत्र भेजकर विजय शर्मा से अपील की थी कि वह बातचीत करना चाहते हैं। इसी बात को लेकर के विजय शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए संवाददाताओं से यह साफ कहा कि वह समय अब निकल गया है। पहले की तरह आइए, बैठिए और चाय पीजिए वाली कहानी चलती थी वह अब नहीं होगा। अब कोई भी बात तभी होगी जब नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे। समाज की मुख्यधारा से जुड़ेंगे, उसके बाद उनकी जो भी मांग होगी हम चर्चा करने को तैयार हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलियों के पुनर्वास की नीति को चल रही है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकार सुविधा भी दे रही है। ऐसे में वह निवेदन करते हैं कि बंदूक छोड़कर वह समाज की मुख्यधारा से जुड़ें। सरकार उन्हें हर सहायता देने को तैयार है। हालांकि विजय शर्मा ने यह भी कहा कि जब तक बंदूक छोड़ने पर अमल नहीं होगा, सरकार किसी तरह की बात नहीं करेगी।

● रायपुर से टीपी सिंह

हथियार डालो, लाखों पाओ

12 अप्रैल को छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 को लेकर ऐलान किया। जिसमें नई नीति के साथ हथियारों को लेकर आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को लाखों रुपए सहायता राशि का प्रावधान किया गया है। इसके तहत लाइट मशीन गन के साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को 5 लाख का मुआवजा मिलेगा। एके-47 त्रिची एसॉल्ट राइफल पर 4 लाख दिया जाएगा। मोर्टार के साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को ढाई लाख रुपए, एसएलआर और इंसास राइफल पर 2 लाख दिए जाएंगे। वहीं एक्स 95 एसॉल्ट राइफल एमपी 9 टेक्टील पर डेढ़ लाख रुपए दिए जाएंगे। थ्री नॉट थ्री राइफल पर एक लाख रुपए, एक्स कैलिबर पर 75 हजार और यूबीजीएल अटैचमेंट पर 40 हजार रुपए दिए जाएंगे। 315 और 312 बोर के बंदूक पर 30 हजार मिलेंगे। गलोक पिस्टल पर 30 हजार के साथ अन्य छोटे हथियार जैसे कारबाइन, वाल्वर, वायरलेस, डेटोनेटर के साथ आत्मसमर्पण करने वाले को सरकार प्रोत्साहन की राशि देगी। इसके अलावा आत्मसमर्पणकर्ता नक्सली भले ही उसके पास हथियार हों या न हों, उसे 50 हजार रुपए की नगद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

अब हिंदी-मराठी के बीच विवाद

महाराष्ट्र में भाषाई राजनीति एक बार फिर से भड़क गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के वरिष्ठ नेता सुरेश भैयाजी जोशी ने हाल ही में एक सार्वजनिक सभा में यह बयान दिया था कि मुंबई आने वाले लोगों के लिए राज्य की आधिकारिक भाषा मराठी को सीखना जरूरी नहीं है। मुंबई, पुणे, ठाणे और नासिक में स्थानीय नगरीय निकायों के चुनाव नजदीक होने के बीच भाजपा को इस बयान से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले को संभालने की कोशिश में कह दिया कि राज्य के सभी निवासियों को मराठी सीखनी चाहिए। जय महाराष्ट्रा, ए हिस्ट्री ऑफ शिवसेना के लेखक प्रकाश अकोलकर का मानना है कि जोशी का यह कहना कि मुंबई की भाषा एक नहीं है जानबूझकर माहौल को नापने के लिए दिया गया बयान था। उन्होंने कहा, आरएसएस और भाजपा का एक राष्ट्र, एक भाषा लागू करने का एजेंडा स्पष्ट रूप से परिभाषित है। मुंबई का उदाहरण देकर वे हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बनाने से पहले राजनीतिक प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं।

जोशी खुद मराठीभाषी हैं। उनका कहना था कि शहर के विभिन्न हिस्सों ने वहां की प्रमुख आबादी के आधार पर अलग-अलग भाषाएं बोली जाती हैं। घाटकोपर में गुजराती ज्यादा हैं जबकि गिरगांव में महाराष्ट्रियन ज्यादा हैं। इस भाषाई वास्तविकता को मुंबई से ही समझा जा सकता है। राज्य की आधिकारिक भाषा मराठी, वैसे तो देशभर में 12 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है, लेकिन मुंबई में कोई भी मराठी का एक शब्द भी बोले बिना शहर में अपना काम-धंधा कर सकता है। ऐतिहासिक रूप से मुंबई का चरित्र महानगरीय रहा है जिसने कई भाषाओं, संस्कृतियों और जातीयताओं के लोगों को खुद में समेटा है। देश की वित्तीय राजधानी के रूप में मुंबई की आर्थिक बागडोर गैर-मराठीभाषी व्यापारिक और व्यापारिक समुदाय द्वारा नियंत्रित की जाती है, जो मराठी मूल निवासियों को रोजगार देते हैं। मुंबई भले ही महाराष्ट्र का अभिन्न अंग है, लेकिन वह मराठी संस्कृति का केंद्र नहीं है। इस बहुसांस्कृतिकता से इतर, मुंबई भाषाई अंध राष्ट्रवाद का केंद्र भी रहा है। मराठी भाषा महाराष्ट्रियन पहचान का महत्वपूर्ण संकेतक है और इसकी राजनीतिक प्रतिध्वनि भी मजबूत है। शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भाषाई क्षेत्रवाद पर जोर देकर और स्थानीय मराठियों के गुस्से को आवाज देकर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया है।

केंद्र की मोदी सरकार इस समय हिंदी भाषा को थोपे जाने को लेकर गैर-भाजपा शासित राज्यों के विरोध का सामना कर रही है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के त्रिभाषा (अंग्रेजी, हिंदी और राज्य भाषा) फॉर्मूले के हिस्से के रूप में हिंदी भाषा को शामिल करने का विरोध किया है। महाराष्ट्र में शिवसेना (उद्धव गुट) और मनसे की संकीर्ण राजनीति ने भाषाई राजनीति को जटिल बना दिया है। महाराष्ट्र में प्रमुख पार्टी के रूप में अपने पदचिह्न का विस्तार करने के लिए उत्सुक भाजपा ने मराठी को बढ़ावा देने का काम किया है। विधानसभा चुनावों से कुछ हफ्ते पहले बीते अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समृद्ध और प्राचीन साहित्यिक परंपरा के लिए मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया था। राज्य की सत्ता में आने के बाद देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों के लिए सभी संचार और निर्देश पट्टिकाओं को मराठी में अनिवार्य कर दिया था। राज्य योजना विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में मराठी में नहीं बोलने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

प्रतिष्ठित लेखक और साहित्य अकादमी विजेता रंगनाथ पठारे ने कहा कि दस साल की देरी के बाद मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का कदम राजनीतिक के अलावा कुछ नहीं था, जिसका मकसद भाजपा के लिए मराठी वोट पाना था। पठारे को 2013 में कांग्रेस सरकार द्वारा यह पता लगाने के लिए नियुक्त किया गया था कि मराठी शास्त्रीय भाषा के दर्जे के मानदंडों को पूरा करती है या नहीं। वे बताते हैं, मराठी की समृद्ध प्राचीन परंपरा है जो 2000 साल पुरानी है। मराठा साम्राज्य के 400 साल के शासन में कराची से लेकर कर्नाटक तक यह भाषा बोली जाती थी। हमने 2015 में भाषा की उत्पत्ति को दर्शाने वाले सभी दस्तावेजी और साहित्य प्रमाणों के साथ 500 पन्नों की रिपोर्ट प्रस्तुत की, फिर भी केंद्र सरकार ने तत्काल दर्जा देने से इनकार कर दिया। भाजपा का उद्देश्य मराठी भाषा और संस्कृति को आगे बढ़ाने के नाम पर अपनी प्रतिद्वंद्वी शिवसेना (ठाकरे गुट) से मराठी एजेंडे का नियंत्रण हासिल करना है, जिसकी पहचान राजनीतिक क्षेत्र में मराठी समर्थक पार्टी के रूप में निहित है।

● बिन्दु माथुर

मराठी मूल निवासियों को नौकरियों में प्राथमिकता

शिवसेना ने नौकरियों में स्थानीय मराठी मूल निवासियों को प्राथमिकता देने के लिए हिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया और यहां तक कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसरों से वंचित करने के लिए शहर में दक्षिण भारतीय प्रवासियों पर हमला किया। समय के साथ पार्टी ने स्कूलों में मराठी भाषा को अनिवार्य रूप से लागू करवाने, राज्यभर के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर मराठी साइनबोर्ड लगाने और मराठी भाषियों के आरक्षण के लिए अपने आक्रामक अभियानों के राज्य में अपनी पैठ बनाई। दूसरी ओर, पिछले महीने दिल्ली में हुए 98वें मराठी साहित्य महोत्सव में मोदी ने संघ के मराठी कनेक्शन का जिक्र किया था। उन्होंने मराठी भाषा और संस्कृति से परिचित कराने के लिए आरएसएस की प्रशंसा की, लेकिन अपने 100 वर्षों के सफर में संघ ने कभी भी मराठी भाषा के प्रचार के लिए वकालत नहीं की है। आरएसएस ने हमेशा हिंदी को एकजुट करने वाली भाषा के रूप में देखा है और हिंदी और संस्कृत को राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रचार किया है। मूल पार्टी में विभाजन और भाजपा के हाथों अपने नेताओं के नुकसान के बाद पीड़ित शिवसेना (ठाकरे गुट) को भाषा विवाद ने नया औजार दे दिया है।

जकात के पैसों से आतंकी कैंप

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने राजस्थान में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 120 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। एनआईए की चार्जशीट में प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। इसके मुताबिक पीएफआई के दफ्तर में आतंकियों को तैयार किया जा रहा था। यहां चाकूबाजी से लेकर आत्मरक्षा तक की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इतना ही नहीं आतंकी कैंपों में गुजरात दंगों और मॉब लिंचिंग के वीडियो दिखाकर मुस्लिम लड़के-लड़कियों का ब्रेनवॉश किया जा रहा था। जांच के बाद एनआईए ने चार्जशीट में पीएफआई को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। पीएफआई से जुड़े सदस्यों को अपने-अपने शहरों में कैंप चलाने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन इन ट्रेनिंग कैंपों की आड़ में युवकों को हथियार चलाने और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि पीएफआई के आतंकी ट्रेनिंग कैंप जकात के नाम पर जुटाए गए पैसों से चलाए जा रहे थे। पीएफआई की पाठशाला में युवाओं को भड़काऊ वीडियो दिखाकर 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने पर जोर दिया जाता था। इसके अलावा फोन से कई और फोटो और वीडियो भी बरामद हुए हैं। जिसमें पुरुष और महिलाएं एयरगन थामे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक और फोटो बरामद हुई है जिसमें पुरुष और महिलाओं को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। बैकग्राउंड में पीएफआई का झंडा और आजादी महोत्सव का पोस्टर देखा जा सकता है।

राजस्थान में पीएफआई का मास्टरमाइंड आसिफ था। वो लंबे समय से पीएफआई से जुड़ा हुआ था। पीएफआई का सबसे भरोसेमंद मेंबर। कोटा के कांशियों के मोहल्ले का रहने वाला है। दुनिया को दिखाने के लिए कोटा में सैलून चलाता था। हकीकत में पीएफआई के लिए जकात के नाम पर फंड जुटाता था। मोहम्मद आसिफ सोशल मीडिया और वॉट्सऐप ग्रुप के साथ-साथ लोकल नेटवर्क से ऐसे युवाओं को ढूंढ़ता, जो मजहब के लिए कट्टर हों। उन्हें अपने साथ जोड़कर उनका ब्रेनवॉश करता। ट्रेनिंग कैंप से ही कट्टर युवकों की पहचान कर उन्हें अलग-अलग काम सौंपता।

सादिक बारां के तलाबपाड़ा का रहने वाला है। आसिफ और सादिक दोनों अच्छे दोस्त हैं। दोनों साथ मिलकर पीएफआई के लिए काम कर रहे थे। दोनों जकात के नाम पर समाज के लोगों से पैसे जुटाते। बाद में उन पैसों से ट्रेनिंग कैंप लगाते, जहां युवाओं को गोधरा और केरल के प्रोपेगेंडा वीडियो दिखाकर उनके मन में जहर घोलते थे। मोहम्मद सोहेल उदयपुर के मुर्शिद नगर का रहने वाला है। उदयपुर में पीएफआई के लिए कैंपेन चलाता था। मजहब के लिए कट्टर युवाओं को पीएफआई में भर्ती करता। खुद अच्छा निशानेबाज है। उदयपुर और कोटा में युवकों को ट्रेनिंग कैंप में हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता था। कन्हैयालाल हत्याकांड से पहले उदयपुर में पीएफआई की रैली निकाली गई थी। इसमें मोहम्मद सोहेल शामिल हुआ था। वाजिद कोटा के कुन्हाड़ी का रहने वाला है। पीएफआई का सक्रिय मेंबर था। पीएफआई के लिए सदस्यों की भर्ती करता था। कैंप ट्रेनर था। कैंप में युवकों को हथियार चलाने से लेकर फिजिकल ट्रेनिंग देता था। जो युवा अच्छा परफॉर्म करते, उन्हें आगे के काम के लिए सिलेक्ट कर लेता था। मुबारिक अली कोटा के मवासा गांव का रहने वाला है। ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट में ट्रेंड है। कैंप में युवकों को ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देता था। मुबारिक के मोबाइल से कई आपत्तिजनक वीडियो मिले थे। बैंक अकाउंट से भी पीएफआई से रुपए के लेनदेन के सबूत मिले थे। वाजिद अली, मुबारिक अली के साथ एक अन्य युवक शमशेर भी था, जो अब तक फरार है। एनआईए उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। शमशेर ट्रेनिंग कैंप में हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता था।

पीएफआई की पाठशाला में युवाओं को भड़काऊ वीडियो दिखाकर 2047 में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने पर जोर दिया जाता। इसके लिए उन्हें अपनी जान भी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटने के लिए तैयार किया जाता था। जयपुर के पीएफआई मॉड्यूल में गिरफ्तार पांच आरोपियों में से एक मोहम्मद आसिफ के मोबाइल से एक फाइल बरामद हुई थी। इस फाइल में लिखा था कि शारीरिक फिटनेस कार्यक्रम- युवाओं को स्वस्थ रखने के लिए पीएफपी के तहत कई एनजीओ और संस्थाओं द्वारा कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे- जैसे योग, मार्शल आर्ट, खेल, संगीत कार्यक्रम।

पीएफआई के सदस्यों को अपने-अपने शहरों में कैंप चलाने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन योगशाला और अखाड़े की आड़ में इन ट्रेनिंग कैंपों में युवाओं को हथियार चलाने और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इसके साथ ही युवाओं का ब्रेनवॉश करके उन्हें खतरनाक इरादों के लिए तैयार किया जा रहा था। ब्रेनवॉश करने के बाद कैडर को दो हिस्सों में शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता था। पहला बेसिक- जिसमें सदस्यों को मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग, एयरगन से शूटिंग आदि सिखाई जाती है। प्रशिक्षण के दूसरे हिस्से यानी कुल्हाड़ी-2 में तलवार, चाकू या हथियार का इस्तेमाल करके व्यक्ति के सिर, छाती, कंधे और अन्य कमजोर हिस्सों पर हमला करने की तकनीक सिखाई जाती।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

मुसलमानों से जकात के नाम पर लिए पैसे

एनआई की जांच के दौरान पीएफआई सदस्यों के जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बूंदी समेत 120 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान चाकू, एयरगन, कुल्हाड़ी, आपत्तिजनक डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज जब्त किए गए, जिन्हें डेटा विस्तार और रिपोर्ट के लिए सीएफएसएल नई दिल्ली सी-डेक तिरुवनंतपुरम भेजा गया। इन तलाशियों के दौरान बरामद आपत्तिजनक दस्तावेजों से पीएफआई कैडरों के एडवांस ट्रेनिंग कोर्स का पता चला। चार्जशीट के मुताबिक, पीएफआई द्वारा जयपुर के पंजाब नेशनल बैंक में खोले गए बैंक खाते की भी जांच की गई। पाया गया कि साल 2011 से 2022 के दौरान 2,98,47,916.99 रुपए जमा किए गए, जिनमें से 2,96,12,429.50 रुपए निकाले गए। चार्जशीट से पता चला है कि ये करोड़ों रुपए देश के निर्दोष मुसलमानों से जकात के नाम पर एकत्र किए गए थे, जिनका इस्तेमाल बाद में हथियार खरीदने, हथियार प्रशिक्षण शिविर चलाने और चुनिंदा लोगों को निशाना बनाने के लिए किया गया।

गहरा जख्म न दे दे 'गद्दार'

करीब 8 साल से उप्र की सत्ता से बाहर अखिलेश यादव को 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत मिली। इसके बाद से समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर उम्मीदों से भरी दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव अपनी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाली पीडीए पॉलिटिक्स पर और आक्रामक हो रहे हैं। लेकिन इस बीच अबू आजमी का औरंगजेब पर बयान और समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन का राणा सांगा को गद्दार और देशद्रोही बताने वाले बयान पर हंगामा खड़ा हो गया है। मामले में राजपूत समाज से तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं।

अबू आजमी के औरंगजेब को लेकर दिए बयान पर बात करें तो उप्र में इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को ज्यादा नहीं होगा। उप्र में मुस्लिम वोटबैंक करीब 19 फीसदी के करीब है। 2017 के बाद से जितने भी चुनाव हुए, उसमें साफ दिखता है कि मुस्लिम आबादी अब सिर्फ समाजवादी पार्टी को सीधा समर्थन देती है। जाहिर है सपा को सियासी नुकसान नहीं होता दिख रहा लेकिन भाजपा को इसका लाभ जरूर मिलेगा। उसकी हिंदुत्व पॉलिटिक्स के लिए औरंगजेब एक अहम मुद्दा है। योगी आदित्यनाथ के ताजा बयानों से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वे लगातार इसका जिक्र अपने भाषणों में करने भी लगे हैं। पिछले दिनों बहराइच के दौरे पर गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग भारत के महापुरुषों को अपमानित करते हैं। उन आक्रांताओं का महिमामंडन करते हैं, जिन्होंने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने और हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उन्हें उसे आज का यह नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। आक्रांता के महिमामंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना है और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। अब बात रामजीलाल सुमन के बयान की। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा को गद्दार और देशद्रोही बताने वाले बयान पर हंगामा खड़ा हो गया है। मामले में राजपूत समाज से तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं।

उप्र के बड़े क्षत्रिय नेता और जनसत्ता दल के सर्वेसर्वा राजा भैया ने एक्स पर लंबी पोस्ट लिखी। उन्होंने लिखा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा के विषय में जो अभद्र टिप्पणी की है, वो सत्य से परे तो है ही, हर देशभक्त, हर राष्ट्रवादी के लिए बहुत ही कष्टप्रद है। तुष्टिकरण के चलते हमारे महानायकों को खलनायक और गद्दार कहा जा रहा है। देश का दुर्भाग्य है कि औरंगजेब जैसे आततायी और बर्बर शासक का महिमामंडन करने के लिए कुछ लोग अपने ही महानायकों को छोटा दिखाने की होड़ में लगे हैं। इतिहास के सत्य पुनर्लेखन का युग आ चुका है। वहीं एक और क्षत्रिय नेता बृजभूषण शरण सिंह, जो हैं तो भाजपा के पूर्व सांसद लेकिन राजपूत समाज में इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के शरीर में दैत्यगुरू शुक्राचार्य की आत्मा बसी हुई है। सुमन जी को अपना बयान वापस लेना चाहिए वरना इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि रामजीलाल सुमन के बयान से राजपूत समाज की नाराजगी का सपा को वाकई नुकसान होगा?

अगर सीटों की बात करें तो गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हमीरपुर, फतेहपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिले ऐसे हैं जहां राजपूत बिरादरी का खासा दबदबा है। इसके अलावा वाराणसी, बलिया, गोरखपुर जैसे कई जिले हैं, जहां ये जीत-हार तय करने का माद्दा रखते हैं। अब सवाल यह है कि क्या रामजीलाल सुमन के बयान से नुकसान होगा? चलिए आपको 2024 का लोकसभा चुनाव की याद दिलाते हैं। उस समय गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद चीजें भाजपा के पक्ष में नहीं रहीं। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने हम पर राज किया। राजा भी उनके आगे झुक गए। उन्होंने उनके साथ रोटियां तोड़ीं और अपनी बेटियों की शादी उनसे की। दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ लेकिन वे झुके नहीं। रूपाला के इस बयान के बाद गुजरात से लेकर उप्र तक बवाल मच गया। राजपूत समाज से विरोध शुरू हो गया। बाद में हालांकि रूपाला ने अपने बयान के लिए माफी भी मांग ली लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इस दौरान उप्र तक इसकी आंच पहुंच चुकी थी। यहां इसी तरह के कई और बयान जिसमें सम्राट मिहिर भोज को गुर्जर, सम्राट पृथ्वी राज चौहान को गुर्जर, सम्राट अनंगपाल तोमर को जाट या कभी गुर्जर, राजा पोरस को जाट तो कभी अहीर, राणा पुंजा सोलंकी को भील, सुहेलदेव बैस को राजभर, आल्हा और उदल आदि विवाद में जुड़ते चले गए और स्थितियां बिगड़ती चली गईं। इसका असर ये हुआ कि लोकसभा चुनाव आते-आते उप्र में राजपूत बिरादरी ने कई जगह भाजपा प्रत्याशी का खुला विरोध करना शुरू कर दिया।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

उप्र में क्षत्रिय वोट बैंक करीब 6 से 7 फीसदी

उप्र में क्षत्रिय वोटबैंक करीब 6 से 7 फीसदी का माना जाता है। संख्या के लिहाज से भले ही ये प्रतिशत ज्यादा नहीं दिखता, लेकिन रसूख के मामले में क्षत्रिय हमेशा ही सत्ता के केंद्र में रहे। उप्र में क्षत्रिय बिरादरी ने अभी तक 5 मुख्यमंत्री दिए हैं। इनमें त्रिभुवन नारायण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीर बहादुर सिंह, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ हैं। इनमें योगी आदित्यनाथ अकेले क्षत्रिय नेता हैं, जिन्होंने 5 साल सरकार चलाई और अब दोबारा सत्ता पर काबिज हैं। इससे पहले गठबंधन की जोड़-तोड़ की राजनीति के चलते कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। वहीं उप्र से दो ठाकुर प्रधानमंत्री भी बने। इनमें चंद्रशेखर और वीपी सिंह का नाम है। वीपी सिंह हालांकि बाद में मंडल आरक्षण लागू करने के चलते अपनी ही बिरादरी में हाशिए पर चले गए। लेकिन चंद्रशेखर हमेशा सिरमौर रहे। यही नहीं मुलायम सिंह यादव ने भी क्षत्रियों के रसूख को हमेशा तरजीह दी और राजपूत बिरादरी से उन्हें हमेशा समर्थन मिला। भाजपा से राजनाथ सिंह क्षत्रिय बिरादरी के सर्वमान्य नेता माने जाते हैं। कहा जाता है कि पश्चिम से लेकर पूरब तक राजनाथ सिंह सभी राजपूत रसूखदारों में अच्छी दखल रखते हैं। अब योगी आदित्यनाथ का भी वही रसूख है।

भाजपा से टकराने को तैयार बिहार

कांग्रेस आज के दौर में मंडल कमंडल की राजनीति की तर्ज पर भाजपा से टकराने को तैयार है। अब कांग्रेस ने बिहार के नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी की है, जिसमें राहुल गांधी के नारे, जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी को कमोबेश लागू करने की कोशिश दिखाई पड़ती है। राहुल जातिगत जनगणना और आरक्षण की 50 फीसदी सीमा को तोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस संगठन में इस दिशा में कदम उठाने के बाद, अब बिहार के जारी 40 जिलों के अध्यक्षों की लिस्ट में कौन किस जाति से हैं? सवर्ण 14 (भूमिहार 6, ब्राह्मण 4, राजपूत 3, कायस्थ 1), दलित 5 (पासवान 3, रविदासी 2), अल्पसंख्यक 7 (मुसलमान 6, सिख 1), ओबीसी 10 (यादव 5, कुर्मी 2, कुशवाहा 3), अतिपिछड़ा 3 (धानुक 1, नोनिया 1, कहार 1) और वैश्य 1 शामिल है।

बिहार में भाजपा अपने दिग्गज नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतार सकती है। लोकसभा चुनाव में हारे हुए कुछ चेहरों को भी बिहार विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। पार्टी का यह फॉर्मूला मप्र और राजस्थान जैसे राज्यों में हिट रहा था। अब बिहार चुनाव में भी इस फॉर्मूले को आजमाने की तैयारी है। पार्टी इन दिग्गज नेताओं को उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों से उतारकर विपक्षी दलों के समीकरण को उलट-पुलट करना चाहती है। इसके पहले मप्र विधानसभा चुनाव में पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते को चुनाव मैदान में उतारा था। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय और कुछ अन्य सांसदों को भी चुनाव मैदान में उतार दिया गया था। इसी तरह राजस्थान में पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी, बालक नाथ और किरोड़ी लाल मीणा को चुनाव मैदान में उतारा गया था। इनमें से ज्यादातर दिग्गज बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब हुए थे। इससे पार्टी और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा था। पार्टी अब इसी फॉर्मूले को बिहार में आजमाने की तैयारी कर रही है। हालांकि, वर्तमान सांसदों को चुनाव में उतारे जाने की कोई संभावना नहीं है।

बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव में रामकृपाल यादव, आरके सिंह, सुशील कुमार सिंह, मिथिलेश तिवारी और शिवेश कुमार जैसे नेताओं को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन क्षेत्र और स्थानीय जातीय समीकरणों में फिट बैठने के कारण पार्टी इन नेताओं को विधानसभा चुनाव मैदान में उतार सकती है। इनके अलावा पार्टी संगठन में प्रभावी नेताओं को भी चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। भाजपा सूत्रों के अनुसार, पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत गंभीर है। हर सीट पर सामाजिक-जातीय समीकरणों का अध्ययन कर इस पर जिताऊ उम्मीदवार दिए जाने की तैयारी की जा रही है। पिछले दिनों अमित शाह की पटना यात्रा के दौरान कोर कमेटी की बैठक के दौरान इस पर चर्चा हुई थी। जानकारी के अनुसार, एनडीए के सहयोगी दलों से भी बातचीत करके उनकी सीटों पर भी केवल जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट दिए जाने की योजना है। पार्टी सहयोगी दलों के साथ बेहतर समन्वय करते हुए कुछ सीटों की अदला-बदली पर भी विचार कर रही है।

पिछले साल लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। पार्टी 240 सीटों पर अटक गई थी। इसके बाद भाजपा के लिए राहत की बात यह रही कि उसे हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत मिली। इन राज्यों की जीत ने पार्टी में नई ऊर्जा का संचार किया है। ऐसे में भाजपा के लिए अगला अहम टारगेट बिहार है, जहां इस साल के आखिरी में चुनाव होने हैं। ऐसे में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का दो दिन का बिहार दौरा अहम रहा। केंद्रीय गृहमंत्री ने अमित शाह ने बिहार में कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान भाजपा और एनडीए के सहयोगियों के साथ चर्चा की थी। शाह ने भाजपा के 84 विधायकों में से प्रत्येक को अगले छह महीनों के लिए बूथ प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने का काम सौंपा है। इस काम में भाजपा के पदाधिकारी की सहायता ली जाएगी। बिहार भाजपा के नेताओं के साथ बातचीत में अमित शाह ने कहा कि पार्टी को उन बूथों पर फोकस करने की जरूरत है, जहां भाजपा के पारंपरिक वोटर बिल्कुल नहीं हैं। बता दें कि कुछ ऐसा ही भाजपा ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान किया था, जिसका पार्टी को बड़ा फायदा मिला था। गृहमंत्री ने यह भी कहा कि बूथ मैनेजमेंट के अलावा वेल्फेयर स्कीम के लाभार्थी भाजपा की चुनावी सफलता की अहम कड़ी रहे हैं।

भाजपा नेताओं और पदाधिकारियों के साथ लगातार दो बैठकों में अमित शाह ने एक मजबूत एनडीए के बारे में बात की, जिसमें उन्होंने जेडीयू के चीफ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिक्र किया। अमित शाह ने सहयोगियों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों तक लगभग हर महीने राज्य का दौरा करेंगे। अमित शाह के साथ बैठकों में मौजूद एक भाजपा नेता कहा कि दोनों बैठकों से सबसे महत्वपूर्ण बात यह निकली कि बिहार को फिर से जीतना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 2026 में होने वाले बड़े विधानसभा चुनावों (पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल) के लिए गति तय करेगा।

● **विनोद बक्सरी**

हिंदुत्व की काट के लिए राहुल चल रहे दांव

कुल मिलाकर राहुल लगातार हिंदुत्व की काट के लिए जाति की सियासत पर दांव लगाते दिख रहे हैं। दरअसल, राहुल गांधी जब बिहार के दौरे पर गए थे। तब उन्होंने अपने भाषण में साफ कर दिया था कि कांग्रेस अब बिहार में सवर्ण के साथ अतिपिछड़ों और दलितों को जगह देने जा रही है। मगर जो लिस्ट सामने आई है, उसमें सबसे ज्यादा सवर्णों को जगह दी गई है और सबसे कम दलितों को। कांग्रेस ने एक दलित चेहरा राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, लेकिन दलितों की दावेदारी में कटौती की गई है। राहुल गांधी ने सभी जिला अध्यक्षों को खास निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने अध्यक्षों से कहा है कि वो मतदाता सूची पर नजर रखें। वोटर लिस्ट में कोई बदलाव होने पर आपत्ति जताने की बात भी सामने आई है। उनसे ये भी कहा गया है कि वो नामों को जोड़ने या हटाने पर नजर रखें। राहुल का कहना है कि वोटर लिस्ट को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। जिला अध्यक्षों को मजबूत करने का मूल मंत्र दिया गया है। जिला अध्यक्षों की जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं।

चीन से दोस्ती... भारत से बैर

एक आम कहावत है कि जिनके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते। लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस यह बात भूल गए। वे चीन को भारत के चिकेन नेक (सिलीगुड़ी कॉरिडोर) पर कब्जा करने की बात करने लगे हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से शेष भारत का अपने पूर्वोत्तर राज्यों से संपर्क टूट जाएगा। वे शायद भूल गए कि भारत है इसीलिए वे सुरक्षित हैं। जिस दिन भारत ने बांग्लादेश से हाथ खींचा वे धड़ाम से जमीन पर गिरेंगे आकर। बिजली, दवाएं और खाद्यान्न के लिए वे भारत पर निर्भर हैं। भले उन्होंने चटगांव बंदरगाह पाकिस्तान के लिए खोल दिया हो। लेकिन पूरा भारतीय प्रायद्वीप पार कर पाकिस्तान के जहाज उन्हें हथियार तो आसानी से पहुंचा सकते हैं, लेकिन रोजमर्रा की वस्तुएं नहीं। और यदि मंगवाईं तो वे कितनी महंगी पड़ेंगी, इसका अंदाजा उन्हें नहीं है।

बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार और सरकार के मुखिया यूनुस ने बीजिंग में जाकर घोषणा की कि भारत के सात पूर्वोत्तर राज्य लैंड लॉक्ड हैं इसलिए इस पूरे क्षेत्र के लिए समुद्री रास्ते के अकेले मालिक हम हैं। यह चीन को व्यापार के लिए न्योता है। परोक्ष रूप से उन्होंने कह दिया कि इस पूरे क्षेत्र में चीन की घुसपैठ हमारे जरिये ही हो सकती है। बांग्लादेश सरकार की सोशल मीडिया सेल ने दो दिन पहले मोहम्मद यूनुस का यह बयान सार्वजनिक कर दिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मोहम्मद यूनुस के इस बयान को आपत्तिजनक बताया है। पर केंद्र सरकार ने फिलहाल इस पर कोई टिप्पणी नहीं व्यक्त की है। मोटे तौर पर मोहम्मद यूनुस सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकेन नेट) पर अतिक्रमण की बात कर रहे हैं। यह कॉरिडोर कोई 22 किमी चौड़ा और 60 किमी लंबा है। इसी के जरिये ये सातों राज्य शेष भारत से जुड़ते हैं।

चटगांव भी बांग्लादेश का एक चिकन नेक है और रंगपुर भी। भारत जब चाहे इनसे बांग्लादेश का संपर्क तोड़ सकता है। न तो बांग्लादेश की सेना इतनी शक्तिशाली है न स्वयं मोहम्मद यूनुस की सरकार। आंदोलनकारी छात्रों का उनसे मोहभंग हो गया है। वे कितने दिन और मुखिया बने रहेंगे, कुछ पता नहीं। यूं भी मोहम्मद यूनुस अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन कि कठपुतली थे। बाइडेन अब बाहर हैं और नए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बांग्लादेश में कोई दिलचस्पी नहीं है। ट्रंप की निगाह में चीन किरकिरी की तरह चुभता है। इसलिए शी जिनपिंग से निपटने की तैयारी वो कर रहे हैं। ऐसी स्थितियों में चीन भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे वह भारत और अमेरिका दोनों से पंगेबाजी करने लगे। उसे भी पता है कि बांग्लादेश सामरिक अथवा व्यापारिक दृष्टि से उसे कोई लाभ नहीं है। चीन और बांग्लादेश की सीमा स्थल भू-भाग से नहीं मिलती।

बांग्लादेश को तोड़ने की मांग

चटगांव और रंगपुर बांग्लादेश से जुड़े तो हुए हैं किंतु इन्हें जोड़ने वाला गलियारा भी बहुत संकरा है। इसीलिए भारत में कई राजनीतिक दल को बांग्लादेश को खंडित करने की बात कर रहे हैं। त्रिपुरा स्टेट के पूर्व महाराजा और वहां की एक रीजनल पार्टी टिपरा मोथा के प्रमुख प्रद्योत देवबर्मन ने तो साफ कहा है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अरबों रुपए खर्च कर वहां सुरक्षा मजबूत करने से पहले केंद्र सरकार बांग्लादेश के टुकड़े कर दे। इससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की पहुंच भी समुद्र तक बनेगी। उनका मानना है कि 1947 में चटगांव क्षेत्र पाकिस्तान को नहीं देना था। यूं भी तब चटगांव में हिंदू आबादी बहुत अधिक थी। आज वहां हिंदू आबादी 10 प्रतिशत के करीब है, लेकिन हिंदू वहां हर तरह से सक्षम हैं। पढ़ाई-लिखाई और धन-संपदा की दृष्टि से भी। प्रद्योत के इस बयान से पूर्वोत्तर क्षेत्र में नई बहस शुरू हो गई है।

मोहम्मद यूनुस अपनी हड़बड़ी में बहुत बड़ी भूल कर बैठे हैं। भले भारत सरकार ने ऊपरी तौर पर उनके बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की हो किंतु क्या भारत उनकी इस टिप्पणी को अनदेखा कर देगा। हिमंता बिस्वा सरमा ने निश्चित तौर पर केंद्र का इशारा मिलने पर बोला होगा। एक तरह से भारत ने यह भी बता दिया है कि भारत सरकार की नजर में बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार की अहमियत उनके एक गवर्नर से अधिक नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे डोनाल्ड ट्रंप कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को गवर्नर ट्रूडो कहते थे और कनाडा को यूएसए का 51वां प्रांत। ऐसा नहीं कि मोहम्मद यूनुस इस संकेत को समझे नहीं होंगे। वे निश्चित तौर पर समझ गए होंगे। किंतु अब वे बोल चुके हैं। बांग्लादेश की जनता उनसे खुश नहीं है। क्योंकि न तो वे देश में भ्रष्टाचार दूर कर पाए न बेरोजगारी की समस्या से निपट सके। अर्थशास्त्री होते हुए भी वे कोई हल नहीं निकाल सके। इसमें कोई नहीं कि शेख हसीना के समय बांग्लादेश में भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार खूब पनपा था। मगर शेख हसीना ने पूरे देश को खुशहाल बनाया था। उनके समय बेरोजगारी पर लगाम लगी और पलायन भी रुका। देश धार्मिक कट्टरता से बाहर आया। यही कारण है कि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग आज भी बहुत ताकतवर है। दूसरी तरफ खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की लोकप्रियता कम है और छात्र भी उन्हें पसंद नहीं करते। जमायत-ए-इस्लामी बीएनपी को सपोर्ट करती है। किंतु धार्मिक संकीर्णता उभारकर आप देश को खुशहाल नहीं रख सकते। उसके लिए आपके पास कोई ठोस योजना होनी चाहिए और आर्थिक नीतियां भी। उस समय चूंकि छात्रों की नजर में विलेन शेख हसीना थीं। इसलिए येन-केन-प्रकारेण हसीना को हटाओ ही नारा गूंज रहा था। आज स्थितियां बदल चुकी हैं।

शेख हसीना पिछले साल 5 अगस्त को भागकर भारत आ गईं। उनको भगाने में बांग्लादेश की सेना का भी हाथ रहा होगा! क्योंकि सेना में उनके रिश्तेदार भरे हुए थे। शुरू में तो वहां जनता उनकी शत्रु हो गई थी पर अब लोग महसूस करने लगे हैं कि शेख हसीना मौजूदा निजाम से बेहतर थीं। कुछ भी हो वे एक राजनीतिक थीं। मोहम्मद यूनुस ने तो आते ही भारत के प्रति शत्रु भाव पाल लिया। जबकि बांग्लादेश की सारी जमीनी सीमा भारत से मिलती है। उसके उदय से आज तक भारत ही उसको हर तरह की मदद मुहैया कराता रहा है। चाहे खाद्यान्न हो या बिजली अथवा दवाएं। इसीलिए खालिदा जिया भी भारत के विरुद्ध कभी एक शब्द नहीं बोलीं। पर मोहम्मद यूनुस अमेरिका के इशारे पर भारत के खिलाफ चले गए। उन्हें पता है कि अमेरिका में अब ट्रंप प्रशासन है। इसके बावजूद वे चीन को अपने देश में कारखाने लगाने का न्यौता दे आए। उनकी यह भूल उनको महंगी पड़ेगी।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

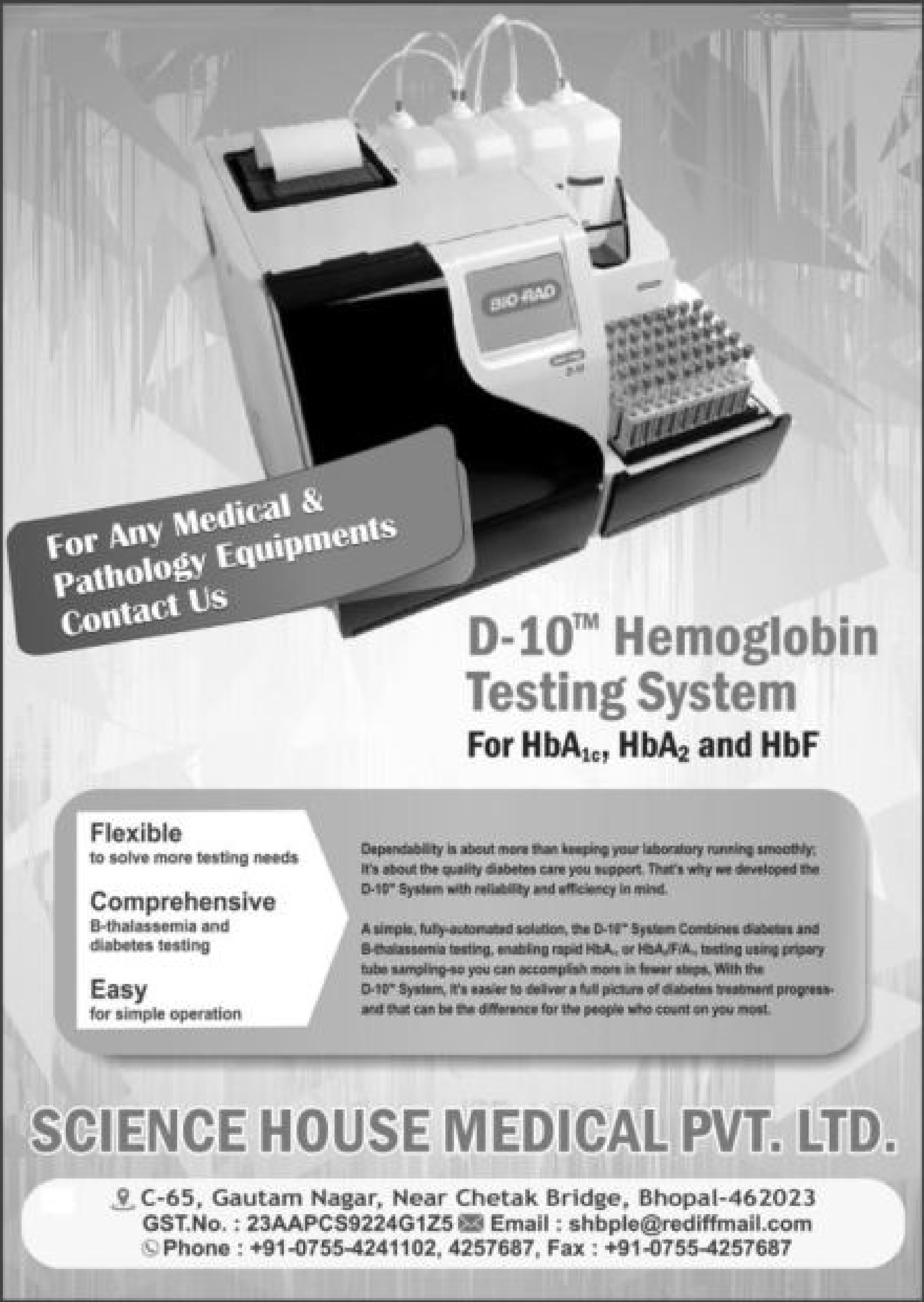

For Any Medical &
Pathology Equipments
Contact Us
D-10™ Hemoglobin
Testing System
For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF
Flexible
to solve more testing needs
Comprehensive
B-thalassemia and
diabetes testing
Easy
for simple operation
Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; it's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.
A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA, or HbA/F/A, testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps. With the D-10™ System, it's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.
SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.
C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

वैश्विक व्यापार पर मंडराया संकट!

भारतीय अर्थव्यवस्था पर कब-कब आई मंदी की आंच

दुनियाभर में आर्थिक मंदी की आहट सुनाई देने लगी है। भारत में भी लोगों की परचेजिंग पावर घट रही है। इसके चलते उद्योगों का पहिया थम रहा है। कंपनियों ने लागत घटाने के लिए छंटनी का सहारा लेना शुरू कर दिया। आर्थिक ग्रोथ तिमाही दर तिमाही सुस्त पड़ती नजर आ रही है। आजादी के बाद से भारत को प्रमुख रूप से दो बार आर्थिक मंदी से झटका लगा है। यह साल थे साल 1991 और 2008। साल 1991 में आई आर्थिक मंदी के पीछे आंतरिक कारण थे। लेकिन 2008 में वैश्विक मंदी के चलते भारत की अर्थव्यवस्था पर आंच आई थी। 1991 में भारत के आर्थिक संकट में फंसने की सबसे बड़ी वजह भुगतान संकट था। इस दौरान आयात में भारी कमी आई थी, जिससे देश दोतरफा घाटे में था।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शुल्क नीति और उसके तहत रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा से विश्वभर में जो माहौल बना है उसने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या संरक्षणवाद एक बार फिर वैश्विक व्यापार को बाधित कर रहा है? यह बहस तेज हो गई है कि टैरिफ आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हैं या यह एक आत्मघाती कदम साबित होता है? दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ वार शुरू किया है उससे विश्वभर के देश उसके खिलाफ लामबंद होने लगे हैं। अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ के जवाब में भारत पर 26 प्रतिशत, चीन पर 34 प्रतिशत और यूरोपीय संघ पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा कर दी है। यह टैरिफ 10 अप्रैल से लागू हो चुका है।

गौरतलब है कि अप्रैल 2025 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कई संकट मंडरा रहे हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। इसके अलावा, अमेरिका और यूरोप में ब्याज दरें बढ़ने से वहां की कंपनियां निवेश कम कर रही हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चेतावनी दी है कि 2025 में कई देश मंदी की चपेट में आ सकते हैं। वहीं अब टैरिफ वॉर ने इस आग में घी का काम किया है। जिससे वैश्विक व्यापार युद्ध की संभावना और अधिक बढ़ गई है। उधर, अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उद्योगपति एलन मस्क की पॉलिसी के विरोध में 1200 से ज्यादा रैलियां निकाली गईं। इन रैलियों का मकसद सरकारी नौकरी में कटौती, अर्थव्यवस्था और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर सरकार के फैसलों का विरोध करना था। इस विरोध प्रदर्शन को हैंड्स ऑफ नाम दिया गया है। हैंड्स ऑफ मतलब होता है- हमारे अधिकारों से दूर रहो। इस नारे का मकसद यह जताना है कि प्रदर्शनकारी नहीं चाहते कि उनके अधिकारों पर किसी का नियंत्रण हो।

ट्रंप की नई टैरिफ नीति लागू होने से पहले ही दुनियाभर के इन्वेस्टमेंट फर्म ने ग्लोबल मंदी के अनुमान को बढ़ा दिया था। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म जेपी मॉर्गन ने रिसेशन के अनुमान को बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया है। फर्म के मुताबिक ट्रंप सरकार के नए टैरिफ और चीन के साथ ट्रेड वॉर के चलते 2025 खत्म होने तक ग्लोबल इकॉनोमी की मंदी में जाने की आशंका 60 प्रतिशत तक पहुंच गई है। पहले यह अनुमान 40 प्रतिशत था। जेपी मॉर्गन ने कहा कि टैरिफ से बिजनेस कॉन्फिडेंस गिरेगा, सप्लाई चेन टूटेगी और ग्लोबल ग्रोथ स्लो होगी। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति से अमेरिकी उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति घटती है और महंगाई बढ़ती है। इससे मांग में कमी आ सकती है, जो कंपनियों के उत्पादन और नौकरियों को प्रभावित करती है। दूसरी ओर, इससे वैश्विक व्यापार युद्ध छिड़ सकता है। इससे निर्यात पर निर्भर अर्थव्यवस्थाएं, जैसे भारत की आईटी और फार्मा इंडस्ट्री, ठप हो सकती हैं।

भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया से जुड़ी है, लेकिन हमारी ताकत हमारी घरेलू खपत में है। करीब 65 प्रतिशत अर्थव्यवस्था भारतीय बाजार पर निर्भर है। फिर भी, मंदी का असर हम पर कई तरीकों से हो सकता है। भारत टेक्सटाइल, ज्वैलरी और आईटी जैसे क्षेत्रों में बड़ा निर्यातक है। अगर अमेरिका और यूरोप में मंदी आई, तो वहां मांग घटेगी और हमारे कारोबार प्रभावित होंगे। हाल के महीनों में टेक्सटाइल निर्यात में 10-15 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है। तेल और गैस की कीमतें बढ़ने से पेट्रोल-डीजल महंगा होगा। इसका असर राशन, सब्जी और रोजमर्रा की चीजों पर पड़ेगा। कंपनियां लागत कम करने के लिए छंटनी कर सकती हैं। 2022-23 में गूगल और मेटा जैसी दिग्गज कंपनियों ने हजारों कर्मचारियों को निकाला था, और यह सिलसिला अभी भी जारी है। भारत में भी आईटी और स्टार्टअप सेक्टर पर दबाव बढ़ सकता है। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिर सकती है, जिससे आयात महंगा होगा। अप्रैल 2025 में यह 85 रुपए प्रति डॉलर के आसपास चल रहा है।

इस व्यापार युद्ध का असर केवल अमेरिका और चीन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह तनाव जल्द ही खत्म नहीं हुआ तो इससे वैश्विक व्यापार अस्थिर हो सकता है। आयात-निर्यात में बाधा आने से विभिन्न देशों की कंपनियों और उपभोक्ताओं को नुकसान उठाना पड़ेगा। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध लगातार तेज होता जा रहा है। ट्रंप प्रशासन जहां अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत आक्रामक व्यापार नीतियां अपना रहा है, वहीं चीन भी अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठा रहा है। दोनों देशों के इस टकराव का सीधा असर वैश्विक व्यापार व्यवस्था पर पड़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या यह व्यापारिक तनाव और बढ़ेगा या दोनों देश बातचीत के जरिए किसी समाधान तक पहुंच पाएंगे।

● सुश्री नित्या

दांपत्य जीवन में बढ़ते अपराध

शादी के बाद जल्दी तलाक न मिलने के चलते गुस्से व तनाव से मन में अपराध की भावना बढ़ती जा रही है। पति-पत्नी के बीच पंडे और काले कोट वाले न आएं तो अलगाव सरल होगा अपराध में नहीं बदलेगा। मां-बाप के द्वारा तय किए जाने वाले रिश्तों में अनबन होना कोई नई बात नहीं है। पहले लड़कियां समझौता करके इसको सहन कर लेती थीं। आज वह इससे बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगती हैं। शादी से बाहर निकलने का रास्ता काफी कठिन होता है। शादी कराने वाले पंडे होते हैं। तलाक के बीच काले कोट वाले पंडे आ जाते हैं, जिससे तलाक में लंबा समय लगता है। अगर पंचायतों की तरह आपसी रजामंदी से चट शादी पट तलाक होने लगे तो पति पत्नी के बीच आपसी अपराध कम हो जाएगा।

तलाक लेने में केवल लड़की की सुनी जानी चाहिए। दोनों के बीच आपसी सहमति से कुछ माह में तलाक पूरा हो जाए। जिससे वह दोनों अपना नया जीवन शुरू कर सकें। पति-पत्नी के बीच अपराध की घटना में एक-दो नहीं पूरे तीन परिवार तबाह होते हैं। अगर नोटरी की तरह एफिडेविड देकर यह काम हो सके तो बहुत ही बेहतर होगा। शादी के बाद तलाक जितना समय लेगा, परेशानी उतनी होगी, युवा लड़के-लड़कियां शादी से उतना ही दूर भागेंगे। विवाह को बचाने के लिए तलाक को बेहद सरल करना होगा।

अगर अदालत से कोई शादी शून्य यानि अमान्य घोषित की जाती है तो लंबा खर्च आता है। इसके साथ ही साथ कई माह भी लगते हैं। पंचायत में यह काम कुछ घंटों में ही बिना किसी बड़े विवाद के हो गया। भारत में विवाह से संबंधित अलग-अलग कानून हैं। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के विवाह, तलाक और संतान की वैधता को समझाने वाला कानून बना है। इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, 1872 ईसाई धर्म के लोगों का विवाह कानून है। मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अधिनियम, 1937 मुस्लिम धर्म मानने वालों के विवाह, तलाक और उत्तराधिकार को बताता है। पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 पारसी धर्म के लोगों के विवाह और तलाक से जुड़ा हुआ है। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 का कानून धर्म और जाति से परे अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाहों को कानूनी मान्यता देता है।

शून्य विवाह क्या होता है? कुछ विवाह ऐसे होते हैं, जो कानून की दृष्टि से शुरू से ही अमान्य होते हैं। इनकी कोई कानूनी वैधता नहीं होती। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 11 के तहत शून्य विवाह का मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति का पहले से कोई वैध विवाह है तो दूसरी शादी शून्य होती है। पति-पत्नी का संबंध अमान्य या निषिद्ध संबंध माना जाता है। इसके अलावा वह विवाह शून्य माना जाता है जिसमें विवाह आवश्यक रस्मों के बिना पूरा हुआ हो। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा-24 के तहत शून्य विवाह तब माना जाता है जब शादी के समय लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम या लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम हो।

इसके अलावा यदि कोई पक्ष मानसिक रूप से अस्वस्थ हो और विवाह की सहमति देने योग्य न हो। यदि विवाह अवैध संबंध में आता हो। यदि पति या पत्नी में से कोई नपुंसक हो। यदि कोई पुरुष या महिला पहले से विवाह में हो और दूसरी शादी कर ले। मुस्लिम कानून के तहत बातिल निकाह वह माना जाता है जिसमें विवाह मुस्लिम कानून की शर्तों के अनुसार न किया गया हो। विवाह निषिद्ध संबंध में हुआ हो। विवाह इद्दत अवधि के दौरान संपन्न हुआ हो। यदि मुस्लिम महिला पहले से विवाहित हो। यदि विवाह धोखाधड़ी या जबरदस्ती से हुआ हो। यदि विवाह पूर्ण रूप से संपन्न न किया गया हो।

शून्य विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दी जाती है। इसमें पति-पत्नी के रूप में कोई अधिकार नहीं बनते हैं। यदि पति-पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो दूसरा उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। ऐसे विवाह से उत्पन्न संतानें वैध मानी जाती हैं, लेकिन उन्हें केवल पिता की अर्जित संपत्ति में अधिकार मिलता है। शून्य विवाह में पत्नी भरण-पोषण की मांग नहीं कर सकती। मुस्लिम कानून में शून्य विवाह के बाद उत्पन्न संतानें अवैध मानी जाती हैं। पत्नी को मेहर या भरण-पोषण का अधिकार नहीं होता। पति-पत्नी के बीच कोई उत्तराधिकार का अधिकार नहीं होता।

● ज्योत्सना अनूप यादव

शून्य विवाह और तलाक में अंतर

शून्य विवाह और तलाक के बीच अंतर होता है। शून्य विवाह वह है जो कानूनन मान्य नहीं है। तलाक कानूनी रूप से वैध विवाह को समाप्त करने की प्रक्रिया होती है। शून्य विवाह को कानूनी स्थिति विवाह कभी नहीं माना जाता है। तलाक में पहले विवाह मान्य था, लेकिन अब समाप्त हो गया है। शून्य विवाह में कोई वैवाहिक अधिकार नहीं बनते हैं। तलाक के मसले में विवाह से जुड़े अधिकार और कर्तव्य बने रहते हैं। शून्य विवाह में पति-पत्नी को कोई अधिकार नहीं होता। तलाक से पहले उत्तराधिकार का अधिकार रहता है। संतान की स्थिति में शून्य विवाह में बच्चे वैध होते हैं लेकिन पिता की पैतृक संपति में अधिकार नहीं होता। तलाकशुदा दंपति के बच्चों को पूर्ण उत्तराधिकार मिलता है। भरण-पोषण में शून्य विवाह में पत्नी को कोई हक नहीं होता। तलाक के बाद पत्नी भरण-पोषण की मांग कर सकती है। विवाह को शून्य करार करने के लिए अदालत का सहारा लेना चाहिए। अदालत विवाह को शून्य घोषित कर सकती है। इसमें समय लगता है। समय तलाक में भी लगता है। यही कारण है कि अधिकतर युवा इस तरह के मसलों में छुटकारा पाने के लिए अपराधिक कदम भी उठा लेते हैं।

रंगों की दुनिया

रवि को बचपन से ही रंगों से खास लगाव था। वह हर चीज में रंगों की दुनिया देखता था। एक दिन, रवि ने एक सफेद कैनवास लिया और सोचा कि वह उस पर ऐसा कुछ बनाएगा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा हो।

उसने लाल, नीला, हरा, पीला-सभी रंगों का इस्तेमाल किया। धीरे-धीरे, उसका कैनवास एक अद्भुत चित्र में बदलने लगा। उस चित्र में एक शहर था, लेकिन वह शहर असली दुनिया से अलग था। वहां की इमारतें आसमान को छूती थीं, पेड़-पौधे रंग-बिरंगे थे, और लोग हवा में उड़ रहे थे। उस चित्र में हर चीज संभव लगती थी।

जब रवि ने वह चित्र पूरा किया, तो उसने महसूस किया कि यह उसकी कल्पनाओं का शहर था, जहां कुछ भी असंभव नहीं था। उसने सोचा, शायद इस शहर की तरह असल जिंदगी में भी हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, अगर हमारे पास सही दृष्टिकोण और रंगों का मेल हो।

उसने वह चित्र अपने कमरे की दीवार पर टांग दिया, और जब भी उसे जीवन में निराशा महसूस होती, वह उस रंग-बिरंगे शहर को देखता और नए सिरे से जीने की प्रेरणा पाता।

– अज्ञात

खोया हुआ सपना

रात के गहरे सन्नाटे में नींद ने रजनी को अचानक जगा दिया। उसने आंखें खोलीं, चारों ओर अंधेरा था। वो बिस्तर पर बैठकर सोचने लगी, कहीं मैंने कोई सपना देखा था? सपना अधूरा सा था, पर दिल में हलचल पैदा कर रहा था।

सपने में वह एक घने जंगल में थी, अकेली। चारों तरफ ऊंचे-ऊंचे पेड़ और पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक, उसके सामने एक नीले रंग का सुंदर पक्षी आया। उस पक्षी की आंखों में अजीब सा आकर्षण था, जैसे वह उसे कुछ बताना चाहता हो। रजनी उसके पीछे-पीछे चल पड़ी, लेकिन अचानक वह पक्षी उड़कर गायब हो गया। रजनी खुद को अकेले, उस घने जंगल में फंसा हुआ महसूस करने लगी।

उसके उठते ही वह सपना टूट गया। सुबह होते ही, रजनी उस पक्षी के बारे में सोचती रही। क्या वह सपना कोई संदेश दे रहा था? कुछ दिन बाद, रजनी को एक पुराने दोस्त का फोन आया, जिसने उसे एक बड़ी नौकरी का प्रस्ताव दिया। वह नौकरी उसे उसके सपनों की दिशा में ले जा सकती थी। रजनी को अब समझ में आ गया कि शायद वह नीला पक्षी उसके सपनों का प्रतीक था, जो उसे एक नया रास्ता दिखा रहा था।

– अज्ञात

कविता

कहां पर बोलना है
और कहां पर बोल जाते हैं।
जहां खामोश रहना है
वहां मुंह खोल जाते हैं।

कटा जब शीश सैनिक का
तो हम खामोश रहते हैं।
कटा एक सीन पिक्चर का
तो सारे बोल जाते हैं।

नई नस्लों के ये बच्चे
जमाने भर की सुनते हैं।
मगर मां बाप कुछ बोले
तो बच्चे बोल जाते हैं।

बहुत ऊंची दुकानों में
कटाते जेब सब अपनी।
मगर मजदूर मांगेगा
तो सिक्के बोल जाते हैं।

अगर मखमल करे गलती
तो कोई कुछ नहीं कहता।
फटी चादर की गलती हो
तो सारे बोल जाते हैं।

हवाओं की तबाही को
सभी चुपचाप सहते हैं।
चरागों से हुई गलती
तो सारे बोल जाते हैं।

बनाते फिरते हैं रिश्ते
जमाने भर से अक्सर।
मगर जब घर में हो जरूरत
तो रिश्ते भूल जाते हैं।

कहां पर बोलना है
और कहां पर बोल जाते हैं।
जहां खामोश रहना है
वहां मुंह खोल जाते हैं।

– अज्ञात

क्रिकेट जगत में इन दिनों एक तरफ जहां आईपीएल की धूम मची हुई है, वहीं रिटायर्ड हर्ट और रिटायर्ड आउट को लेकर सोशल मीडिया और मीडिया में एक नई जंग की शुरुआत हो गई है। हाल ही में दो मामले देखने को मिले हैं जिनमें रिटायर्ड आउट और रिटायर्ड हर्ट की घटनाएं घटीं। आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने तिलक वर्मा को रिटायर्ड आउट करार दिया और मिचेल सैंटनर को मैदान पर भेजा। सैंटनर आमतौर पर एक स्पिन गेंदबाज हैं जो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लेते हैं। लेकिन तिलक की जगह सैंटनर को भेजना थोड़ा अजीब फैसला था। सैंटनर ने क्रीज पर आकर सिर्फ 2 गेंद खेलीं और वो दो ही रन बना पाए। जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है। इस पर महेला जयवर्धने और हार्दिक पांड्या ने बड़ा बयान दिया है। ऐसे में मीडिया और सोशल मीडिया में सवाल उठ रहे हैं है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। रिटायर्ड आउट का मतलब क्या होता है? क्रिकेट प्रेमी इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि रिटायर्ड हर्ट और रिटायर्ड आउट में अंतर क्या है।

गौरतलब है कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2025 के मुकाबले में 12 रन से हरा दिया। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ की टीम ने बोर्ड पर 203 रन लगाए। जवाब में मुंबई की टीम 191 रन ही बना पाई। इस मैच में एक बात को लेकर जमकर विवाद हो गया कि मुंबई की टीम ने तिलक वर्मा को रिटायर्ड आउट कर दिया। तिलक के रिटायर होने पर मुंबई के कोच महेला जयवर्धने और कप्तान हार्दिक पांड्या ने अलग-अलग बयान दिए हैं।

क्या बोले हार्दिक?

तिलक बड़ा शॉट खेलने में संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने 23 गेंद में 25 रन बनाए। हमें कुछ बड़े शॉट की जरूरत थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। क्रिकेट में कुछ ऐसे दिन आते हैं जब आप कोशिश करते हैं लेकिन वह सफल नहीं होता है। बस अच्छा क्रिकेट खेलें, मैं इसे सरल रखना पसंद करता हूं।

कौन सच्चा, कौन झूठा?

रिटायर्ड आउट वाली लिस्ट में शामिल हुए कॉनवे

आईपीएल में 2025 से पहले सिर्फ 3 खिलाड़ी रिटायर्ड आउट हुए, लेकिन इस सीजन दो खिलाड़ी ऐसा कर चुके हैं। नया नाम इस लिस्ट में चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज डेवन कॉनवे का जुड़ा है जो 49 गेंदों में 69 रन बना चुके थे।

तिलक वर्मा : आईपीएल 2025 में तिलक वर्मा पहले ऐसे खिलाड़ी थे जो रिटायर्ड आउट होकर पवेलियन लौटे। वे इस लिस्ट में चौथे खिलाड़ी थे जिनके साथ ये घटना हुई थी।

साई सुदर्शन : गुजरात टाइटन्स के बल्लेबाज साई सुदर्शन 2023 के सीजन में रिटायर्ड आउट होकर पवेलियन लौटे थे। उस सीजन में दूसरे खिलाड़ी ने ऐसा किया था। वे रिटायर्ड आउट होकर लौटने वाले तीसरे खिलाड़ी थे।

अथर्व तायडे : पंजाब किंग्स के बल्लेबाज अथर्व तायडे आईपीएल में रिटायर्ड आउट होने वाले दूसरे बल्लेबाज थे। उन्होंने 2023 के सीजन में ऐसा किया था। उस सीजन पहली बार किसी ने रिटायर्ड आउट होना जरूरी समझा था।

अश्विन : हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले आर अश्विन ने रिटायर्ड आउट वाला मसला शुरू किया था। साल 2022 में मुंबई के मैदान पर आर अश्विन रिटायर्ड आउट होकर पवेलियन लौट गए थे क्योंकि वे तेज गति से रन नहीं बना पा रहे थे। ये पहली बार था जब किसी ने ये कदम उठाया था।

जयवर्धने ने कही ये बात

मैच के बाद मुंबई इंडियंस के कोच महेला जयवर्धने ने कहा, मुझे लगता है कि जब हमने विकेट खोया तो तिलक ने हमारे लिए अच्छी बल्लेबाजी की और सूर्या के साथ साझेदारी भी अच्छी थी। वह बस तेजी से रन बनाना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। आखिरी कुछ ओवरों तक उम्मीद थी क्योंकि उसने कुछ समय वहां बिताया था, इसलिए उसे हिट लगाने में सक्षम होना चाहिए था। लेकिन मुझे लगा कि अंत में मुझे किसी नए खिलाड़ी की जरूरत है।

क्या होता है रिटायर्ड आउट- अगर कोई बल्लेबाज अंपायर के बिना आउट दिए ड्रेसिंग रूम में चला जाता है या कप्तान की मर्जी से उसे बुला लिया जाता है तो बल्लेबाज को रिटायर्ड आउट करार दिया जाता है। यानी अब बल्लेबाज दोबारा बल्लेबाजी के लिए नहीं आ सकेगा जब तक विपक्षी कप्तान की अनुमति न हो।

क्या होता है रिटायर्ड हर्ट- रिटायर्ड हर्ट तब करार दिया जाता है जब कोई बल्लेबाज चोटिल हो या वह खेलने में असमर्थ हो। ऐसी स्थिति में बल्लेबाज ठीक होने पर फिर से बल्लेबाजी करने आ सकता है, जबकि गंभीर स्थिति में बल्लेबाज की जगह सब्स्टीट्यूट बल्लेबाज की गुजारिश भी अंपायर से की जा सकती है।

आईपीएल इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले खिलाड़ी- आईपीएल 2022 के दौरान रविचंद्रन अश्विन ने रिटायर्ड आउट होने वाली प्रथा को शुरू किया था जो उस सीजन तो एक ही बार देखने को मिली, लेकिन अगले सीजन में दो बार खिलाड़ी रिटायर्ड आउट होकर पवेलियन लौटे। 2024 में ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। लेकिन 2025 यानी मौजूदा आईपीएल संस्करण में कुछ ही मैचों के अंतराल पर दो खिलाड़ी रिटायर्ड आउट हो चुके हैं। ताजा मामला तिलक वर्मा और डेवन कॉनवे से जुड़ा है।

● **आशीष नेमा**

1 वजह से छोड़ दिया पिता का सरनेम...!

काजोल ने सालों के बाद बताया सच

दिग्गज एक्ट्रेस तनुजा और शोमू मुखर्जी की बेटी काजोल को एक्टिंग पेरेंट्स से विरासत में मिली थी, लेकिन वो असल में कभी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थीं...

काजोल ने खुलासा किया कि वो अपनी मां को इतना काम करते देखती थीं कि उन्हें फिल्मों में काम करने की इच्छा नहीं थी। वो चाहती थीं कि वो 9 टू 5 जॉब करें, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और आखिरकार काजोल फिल्मों में आ ही गईं। काजोल ने खुलासा किया कि आखिर उन्होंने कभी भी अपने पिता शोमू मुखर्जी के सरनेम का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। वो कहती हैं कि जब वो फिल्मों में कदम रख रही थीं तो उनकी मां चाहती थीं कि वो अपना सरनेम का इस्तेमाल करें।

काजोल के मुताबिक उनकी मां तनुजा चाहती थीं कि वो अपने सरनेम के साथ आगे बढ़ें क्योंकि उनके ग्रैंडपेरेंट्स अपने पीछे एक विरासत छोड़ गए थे। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक वजह से अपने सरनेम का कभी प्रयोग नहीं किया। जबकि, काजोल की बहन तनिषा मुखर्जी ने अपने सरनेम के साथ ही फिल्मों में कदम रखा था।

विरासत के बोझ से बचने के लिए उठाया कदम... अपनी पहचान न खोने और परिवार की विरासत के बोझ से बचने के लिए काजोल ने अपना सरनेम छोड़ दिया। वो कहती हैं, वो एक सोचा समझा फैसला था। जब मैं फिल्मों में आना चाहती थी मेरी मां ने मुझसे पूछा था। उन्होंने कहा था, तुम्हारे पास अपनी दादी और दादा की तरफ से इतनी शानदार विरासत है। मुझे उस समय भी और अब भी लगता है कि मुझे किसी की तरफदारी नहीं करनी थी। वो आगे कहती हैं, मैं अपने प्रति और अपनी एक्टिंग के प्रति सच्ची रहना चाहती थी और अपने परिवार के नाम का बोझ नहीं उठाना चाहती थी। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं सिर्फ काजोल के नाम से जानी जाऊं, तो शायद मुझ पर इतना दबाव नहीं आएगा।

सनी देओल ने भुलाया 32 साल पुराना झगड़ा, अब शाहरुख से नहीं कोई शिकवे

सनी देओल अपने गुस्से के लिए जाने जाते हैं। कई स्टार्स के साथ उनका पंगा हो चुका है। लेकिन 32 साल पुराने झगड़े ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं। सनी ने 32 साल पुराना झगड़े के बारे में हाल ही में बात की और उन्होंने बताया कि शाहरुख खान और यश चोपड़ा के साथ हुए झगड़े को अब भूल चुके हैं। आपको बता दें कि डर की शूटिंग के दौरान एक सीन को लेकर सनी इस बात से बहुत नाराज थे कि शूटिंग कैसे चल रही थी। उन्होंने गुस्से में अपने हाथों से अपनी पैंट फाड़ दी थी। उस सीन के बारे में यश चोपड़ा से गर्मागर्म बहस की थी। कहा तो ये भी जाता है कि यश चोपड़ा और दोनों एक्टर्स की लड़ाई इसलिए हुई थी क्योंकि उन्होंने दोनों को साथ में स्टोरी का नरेशन देने की बजाय अलग-अलग नरेशन दिया था। सनी को नहीं पता था कि उनका रोल शाहरुख के रोल जितना महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसे में जब सनी को पता चला कि उनका बहुत छोटा-सा रोल है तब सनी बहुत नाराज हुए। सनी ने उस दिन के बाद से यशराज फिल्म्स के साथ फिर कभी काम नहीं किया।

वीर सावरकर के लिए रणदीप हुड्डा ने लोगों से तोड़ लिया था कनेक्शन

रणदीप हुड्डा की सनी देओल के साथ फिल्म जाट रिलीज हो चुकी है। एक्टर ने एक इंटरव्यू में अपनी फिल्म के बारे में भी कई खुलासे किए। वो कहते हैं कि वो पिछले साल अगस्त से गोपीचंद मालिनेनी के निर्देशन में बनी इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। रणदीप कहते हैं कि ये पहला मौका है कि जब उन्होंने इतने लंबे समय तक एक ही फिल्म की शूटिंग की है।

रणदीप हुड्डा ने पिछले साल आई फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में बात करते हुए कहा कि इस फिल्म के लिए उन्होंने दुनियादारी छोड़ दी थी। स्मार्टफोन को छोड़कर उन्होंने नोकिया का सामान्य फोन ले लिया था जिससे सिर्फ बात हो सकती थी और कुछ नहीं। एक्टर अपनी फिल्म के लिए इतने समर्पित थे कि उन्होंने अपने आसपास के लोगों से भी अपना कनेक्शन तोड़ लिया था। स्वतंत्र वीर सावरकर के खत्म होने के बाद जब रणदीप वापस अपनी आम जिंदगी में लौटे तो स्मार्टफोन पर उनका काफी टाइम वेस्ट

होने लगा। एक्टर कहते हैं कि अपनी इस आदत को बदलने के लिए उन्होंने अपने स्मार्टफोन से सारे ऐप्स डिलीट कर दिए। आज की तारीख में उनके फोन पर एक भी सोशल मीडिया ऐप नहीं है।

सोशल मीडिया से रहते हैं दूर... आज की जनरेशन के सोशल मीडिया एडिक्शन के बारे में बात करते हुए रणदीप हुड्डा ने कहा कि आजकल लोग अपनी जिंदगी के बारे में हर चीज को सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं कि वो अपनी जिंदगी को प्राइवेट रखना चाहते हैं और दर्शकों से जुड़ने का उनका बस एक ही माध्यम है, वो हैं फिल्में।

बेताल कथा

कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पर अपना परिचय देने से पहले व कहानी शुरू करने से पहले हम अपने खानदान वगैरह के बारे में बता दें ताकि पाठकों को ये मालूम हो जाए कि हम किस विरासत के मालिक हैं और परंपराओं में हमारा कितना विश्वास है।

हमारे दादाजी, सारे गांव में शास्त्रीजी के नाम से मशहूर थे पर शास्त्रों से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं था। कहते थे कि शिक्षा व्यक्तित्व की दुश्मन होती है। उनका मानना था कि यदि हमारे पूर्वज वानर थे और मनुष्य का विकास उन्हीं से हुआ है तो अब इस विकास को क्या हो गया है, जाहिर है जिस दिन से मनुष्य ने अध्ययन आदि करना शुरू किया उसका विकास रुक गया है। मानव जीवन में शिक्षा एक कृत्रिम आवश्यकता है और यही वजह है कि प्रकृति में कोई भी चेतन (सिवाय मनुष्य के) इस दिशा में नहीं सोचता है। आखिर शेर को शेर की तरह व्यवहार करने में कितनी पुस्तकों की सहायता होती है। जब तक वो जीवित रहे अपने सद्धांतों पर अडिग रहे। कहते थे कि कलम बंदूक से भी खतरनाक हथियार है इसलिए कभी हाथ मत लगाना। अपने इन्हीं सद्धांतों की बदौलत हमारे दादाजी सांसद बनकर संसद तक घूम आए और ढाई साल बाद जब वो मध्यावधि चुनावों को कोसते हुए संसद से गांव वापस आए तो इस अखंड विश्वास के साथ कि मनुष्य को वास्तव में किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है (हमें नहीं लगता कि पाठकों को अपनी संसद के परिचय की तनिक भी आवश्यकता है)। उनके इन तर्कों को गांव से लेकर दिल्ली तक, कभी कोई काट नहीं पाया।

देखिए बात कहां शुरू हुई थी और कहां मुड़ गई। भला परंपरा और संसद का भी कोई संबंध है। वहां तो प्रतिदिन नई परंपराएं पड़ती हैं और अगले दिन टूट जाती हैं। तो हम बात कर रहे थे अपने दादाजी व उनके मानव जीवन तथा शिक्षा के प्रति अति विशिष्ट दृष्टिकोण की। अब जैसा कि हर युग हर परिवार में होता आया है, कोई न कोई विद्रोही प्रकृति का निकल ही आता है। यही हाल था हमारे पिताजी का। यह तो पता नहीं की शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या है क्योंकि उस विषय पर हमारी उनसे कभी बात नहीं हुई पर सुनने में आता है कि पढ़ाई-लिखाई में उनकी रुचि कभी नहीं रही। अब चूंकि सुनने सुनाने पर ही हम भारतीयों का पूरा इतिहास क्या, पूरा का पूरा अस्तित्व ही आधारित है इसलिए अविश्वास की गुंजाइश रह नहीं जाती।

इतिहास की बात से याद आया कि न तो मैक्सम्युलर ने तब कोई छेड़खानी की होती और न ही अंग्रेजों ने बाद में कोई शैतानी तो यह दक्षिणपंथी-वामपंथी इतिहास का कोई झगड़ा भी न होता और न ही कुछ प्रतिशत पढ़े-लिखे लोगों को फालतू की मगजमारी ही करनी पड़ती कि सभ्यता का विकास गंगोत्री से गंगासागर की तरफ हुआ है या फिर गंगासागर से गंगोत्री की ओर।

देखिए बात फिर मुड़ गई। अब क्या करें अपनी फितरत ही कुछ ऐसी है, हां तो पढ़ाई हमारे पिताजी ने अवश्य की। पढ़ाई उन्होंने हमारे दादाजी के खिलाफ विद्रोह की दुंदुभी बजाकर की, जैसा कि आजकल हर टीनएजर करने पर तुला हुआ है। पर आजकल तो सब विद्रोह कर रहे हैं, पढ़ाई कोई नहीं कर रहा। जब तक हमारे पिताजी ने बारहवीं पास नहीं कर ली हमारे दादाजी कुढ़ते रहे, जब उन्हें किसी तरह से विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला तब दादाजी को यह सोचकर चैन आया कि अब तो उनका पुत्र नेतागिरी करके सारे खानदान का नाम रोशन करेगा। वैसे भी विश्वविद्यालयों से आजकल किसी को नौकरी की गारंटी भले न मिलती हो पर नेतागिरी जैसे फलते-फूलते व्यवसाय में हाथ-पैर मारने के लिए काफी अनुभव मिल ही जाता है। पर नेतागिरी हमारे पिताजी ने की नहीं यद्यपि उन्हें बातें बनाने में महारत हासिल है, फिर भी...।

अब आप ये बताइए इस देश में बातें बनाने में किसे महारत हासिल नहीं है। राह चलते आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हर विषय के साथ-साथ बातें करने में भी विशेषज्ञ होंगे। राजनीति और समाजशास्त्र से लेकर स्टिंग थ्योरी तक में उनका दखल होगा। पाठकों को लग रहा होगा कि हम विषय से भटक जाते हैं। क्या करें विषय से भटकने की परंपरा का निर्वाह जो करना है। सारे देश का यही हाल है, नेतागण यदि विषय से भटके हुए हैं तो आम जनता भी उनसे पीछे कहां है। वैसे तो आम जनता को तो पता ही नहीं है कि विषय क्या है और जानकर भी क्या करना है। मजेदार बात यह है कि भटक कर भी लोग अपनी परंपराओं को नहीं भूले हैं और किसी न किसी तरीके से कोई न कोई परंपरा वेताल की तरह अपने कंधे पर लादे लिए जा रहे हैं। कोई उनसे पूछे कि भाई विक्रमादित्य बनने में मजा आता है क्या, पर सवाल यह है कि पूछे कौन। सभी तो विक्रमादित्य बनने में व्यस्त हैं। लखनऊ के नवाब साहब एक भूलभुलैया बनवाकर एक अनोखी परंपरा क्या छोड़ गए, सारा का सारा देश ही भूलभुलैया बना हुआ है।

अब जब परंपरा पालन की बात चल ही निकली है तो लगे हाथों क्यों न गांधी परंपरा का भी जिक्र कर लें। यह तो पता नहीं कि गांधी परंपरा का निर्वाह कितने और कौन लोग कर रहे हैं पर गांधी जी के बंदरों के भक्त बहुत मिल जाएंगे- बुरा कहने वाले को कुछ न कहो और वैसे भी आजकल भला कोई कुछ कहता है, यदि कहीं कुछ बुरा हो रहा है तो आंख मूंद लो और यदि कोई किसी को बुरा (भला) कह रहा है तो अनसुनी कर दो।

● **अंशुमान अवस्थी**

MPIDC
MP INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
मध्यप्रदेश में उद्योग और समृद्धि का नया युग
इन्वेस्ट मध्यप्रदेश
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट - 2025
₹30.77 लाख करोड़ के रिकॉर्ड निवेश प्रस्ताव
21.40 लाख नये रोज़गार
25000+ रजिस्ट्रेशन
60+ देश 100+ प्रतिनिधि
9 पार्टनर देश
300+ कम्पनियां
600+ बीटूजी मीटिंग
5000+ बीटूबी मीटिंग
500+ प्रवासियों की भागीदारी
प्रदेश की क्षमताओं में निवेशकों के विश्वास
के लिए हृदय से आभार...

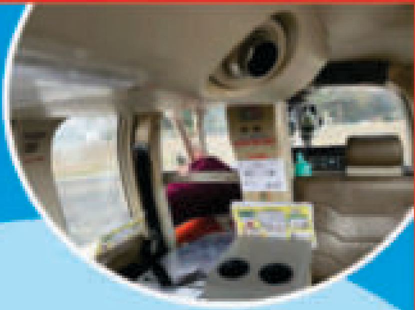

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

मध्यप्रदेश सरकार की

"एक संवेदनशील पहल"

पीएमश्री

एयर एम्बुलेंस सेवा

प्रदेश के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में गंभीर रूप से बीमार, दुर्घटनाग्रस्त लोगों की आपातकाल में त्वरित सहायता के लिए मध्यप्रदेश सरकार की एक परिवर्तनकारी पहल। अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाओं और उपकरणों से सुसज्जित इस सेवा के माध्यम से मुश्किल समय में त्वरित जीवनरक्षक समाधान मिलने से आमजन को समय रहते मिलेगी उचित उपचार की सुविधा।

स्वस्थ और सुरक्षित मध्यप्रदेश का संकल्प

- ₹ 592 करोड़ की लागत से उज्जैन में प्रदेश की पहली मेडिसिटी एवं मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन
- वर्तमान में प्रदेश में 17 शासकीय एवं 13 निजी चिकित्सा महाविद्यालय संचालित
- 55 जिला चिकित्सालयों में भारतीय जन औषधि केंद्रों और 800 आयुष आरोग्य मंदिर का संचालन प्रारंभ
- 8 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय निर्माणाधीन एवं पीपीपी मोड पर 12 चिकित्सा महाविद्यालय शीघ्र होंगे प्रारंभ
- 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग आयुष्मान भारत योजना से ले रहे लाभ

आपातकालीन सहायता के लिए सम्पर्क करें : 9111777858

मध्यप्रदेश शासन